हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 जनवरी, 1998

(द्वितीय बैठक)

खण्ड - 1, अंक - 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 20 जनवरी, 1998

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	3(1)
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
मुख्यमंत्री द्वारा	3(17)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(17)
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
स्थानीय शासन मंत्री द्वारा	3(21)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(22)
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
शिक्षा मंत्री द्वारा	3(25)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(26)
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
परिवहन मंत्री द्वारा	3(27)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(28)
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
श्री जगदीश नायर द्वारा	3(29)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(29)

मूल्य : 12.00

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
मुख्यमंत्री द्वारा	3(30)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(31)
वैयक्तिक स्पष्टीकरण-	
जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा	3(32)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(32)
बैठक का समय बढ़ाना	3(51)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(51)

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 20 जनवरी, 1998

(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो0 छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will take place. Shri Narpender Singh, M.L.A. may move his motion.

Shri Narpender Singh (Badhra) : Sir, I beg to move--

That an address be presented to the Governor in the following terms :--

'That the Members of the Haryana Vidhan Sabha Assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 19th January, 1998.'

स्पीकर साहब, कल 19 जनवरी, 1998 को राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उस पर आज मैं यह प्रस्ताव लेकर खड़ा हुआ हूं कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन इन शब्दों में पेश किया जाए "कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 19 जनवरी, 1998 को सदन में देने की कृपा की है।"

स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से इस डेढ़ साल के बारे में बताया है जिस पर हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने विद्युत के बारे में बताया है। बिजली आज हरियाणा प्रदेश की जनता की सबसे पहली व सबसे ज्यादा जरूरत है। बिजली की समस्या पिछले 20 साल से धीरे धीरे शुरू हो रही है और अब इस समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। हरियाणा की सरकार ने इस समस्या को प्राथमिक तौर पर लिया है। 20 साल पहले जब से सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ी, ट्यूबवैलों के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ी तब से जब-तब हरियाणा प्रदेश में किसानों व दूसरे बिजली के उपभोक्ताओं में बिजली की कमी को लेकर अशांति होती रही है, लेकिन जो भी सरकारें पिछले 20 सालों में आई, उनमें से किसी ने भी बिजली की समस्या के स्थाई हल के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने सबसे पहले बिजली की समस्या से निपटने के लिए प्रयास शुरू किया है व उसके उत्पादन में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले 31 सालों में जब से हरियाणा बना है, बिजली का उत्पादन 863 मेगावाट रहा है जबकि आज हरियाणा प्रदेश में बिजली की खपत 1500 मेगावाट से ज्यादा

[श्री नृपेन्द्र सिंह]

है। हमारी सरकार ने आने वाले 2 सालों में 1168 मेगावाट बिजली का नया उत्पादन करके जोड़ने का लक्ष्य रखा है अगर यह लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं तो हरियाणा प्रदेश के किसानों व दूसरे सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को पूरी बिजली देने के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि सरप्लस बिजली को हम दूसरी स्टेट्स को बेच सकें। जबकि आज प्रदेश में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। स्पीकर सर, इसके बारे में जो मुख्य समस्या मैं बता रहा था, वह यह कि बिजली की समस्या को दूर करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए किसी भी सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किए जिसकी वजह से बिजली की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती गई। चाहे वह ट्यूबवैल्ज हों, इण्डस्ट्रीज हों या घरेलू उपयोग के लिए बिजली की समस्या हो, 70 के दशक से यह समस्या शुरू हुई है लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इसको दूर करने के बारे में कोई विचार नहीं किया जिसके कारण कई बार बिजली के बारे में किसानों को आन्दोलन करने पड़े और वे पुलिस फायरिंग के शिकार हुए। उनका लाभ राजनीतिक पार्टियों ने और राजनीतिक नेताओं ने उठाने की कोशिश की। वे भोले भाले किसानों को भड़का कर इस स्टेज पर ले आये कि उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए उनसे आन्दोलन करवाते और उन्हें लाठियां खानी पड़ती। कई बार ऐसा किया जाता कि बिजली की दर को दो रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दिया जाता और जब कोई आन्दोलन होता तो एक रुपये प्रति यूनिट कम कर दिया जाता, इस तरह से उनकी शिकायत का निपटारा कर दिया जाता। बिजली को बढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। विद्युतीकरण के संबंध में हमारी सरकार ने जो योजना बनाई है, उससे 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की पैदावार होगी। फरीदाबाद में एक गैस पर आधारित 410 मेगावाट का ताप बिजली केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पानीपत ताप बिजली परियोजना में 110-110 मेगावाट यूनिट की चार यूनिटों के चलने से और ज्यादा सुधार आ जायेगा तथा आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के किसानों की, उद्योगों की तथा दूसरे बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की मांग अच्छी तरह से सक्षम होगी। अनेकों राजनीतिक पार्टियां बिजली के नाम पर आजकल आन्दोलन करती रहती हैं। उनको इस बात की चिन्ता है कि कहीं यह सरकार बिजली के सुधार के प्रयासों में सफल हो गई तो उनके पास हरियाणा प्रदेश में आन्दोलन करने का कोई मुद्दा नहीं बचेगा। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Surjewala this is wrong. (Interruptions). Mr. Surjewala please take your seat. You are no body to guide me.

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात जिसमें आपत्ति हो, मैंने नहीं कही है। मैं तो वे बातें बता रहा हूं जो हरियाणा बनने से लेकर आज तक हुई हैं। खासतौर से एग्रीकल्चर सैक्टर में किसानों को बिजली की ज्यादा जरूरत होती है और उसके बारे में मैं बता रहा था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी आप बोलिये, नृपेन्द्र जी आप बैठिये।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, कल रात को मैं और नृपेन्द्र जी एम० एल० ए० होस्टल में बैठे थे और हमारे साथ 5-6 हमारे साथी और भी बैठे थे। उस दौरान श्री नृपेन्द्र जी ने यह कहा था कि हमारे भिवानी जिले में तो बिजली का बुरा हाल है।

श्री नृपेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरा मैम्बर साहेबान से अनुरोध है कि कम से कम ऐसे समय में जब किसी विशेष विषय पर चर्चा हो रही हो, वे ऐसी बातें न करें जिनका कोई मायना न हो। स्पीकर सर, कल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिजली के सुधार के बारे में हरियाणा सरकार की

उपलब्धियों के बारे में जो चर्चा की थी, मैं उस अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर अगले दो साल में बिजली की समस्या हल हो जाती है तो हरियाणा प्रदेश में विपक्ष की पार्टियों के पास कहने को कोई मुद्दा नहीं रह जायेगा तो इनकी यह बात ठीक नहीं है। इनको कुछ परेशानी हो रही है क्योंकि आज बिजली एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी की जरूरत है। आज जो ये माननीय साथी विपक्ष में बैठे हुए हैं, वे सभी पहले बारी-बारी से सत्ता पक्ष में रह चुके हैं और सत्ताधारी होते हुए भी इन्होंने किसानों की मुख्य बिजली की समस्या के बारे में कोई भी हल ढूंढने की कोशिश नहीं की है जिससे आज यह स्थिति आई है कि इनको विपक्ष में बैठना पड़ा है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं हरियाणा प्रदेश के उस क्षेत्र से संबंध रखता हूं जहां का किसान विशेष रूप से बिजली पर ही निर्भर करता है। विपक्ष में बैठे हुए मेरे माननीय साथी जब-जब भी मेरे उस क्षेत्र में गए हैं, इन्होंने अपनी तरफ से लोगों को लालच देने का प्रयास किया है। चाहे पिछले चुनाव की बात हो या किसी और चुनाव की बात हो, ये जब भी वहां पर गए इन्होंने वहां पर जाकर कहा कि हम तुम्हें मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन बारी-बारी से इनके उम्मीदवार वहां से हारते गए और वहां की जनता ने आज मुझे 27 हजार से भी ज्यादा वोटों से जितवाकर विधान सभा में भेजा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब वहां गए थे तो इन्होंने वहां के लोगों से कहा था कि हम तुम्हें मुफ्त बिजली देंगे और बिजली के बिल भी तुम्हारे माफ कर देंगे लेकिन असल बात तो यह है कि वहां की जनता को न तो मुफ्त बिजली ही चाहिए और न ही बिजली के बिलों की मुआफी ही चाहिए। ये जब सत्ता रूढ़ दल में थे तो किसानों के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे लेकिन इन्होंने उस वक्त तो कुछ किया नहीं जिससे जनता के बीच में जाकर ये कह सकें कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस प्रकार से कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसान की जरूरत और बिजली उपभोक्ताओं की जरूरत को अगर सही तरीके से किसी ने समझा है तो हमारी सरकार ने ही इसको समझा है और यह सरकार इसके लिए प्रयासरत है। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। आज बिजली के लिए हरियाणा प्रदेश में आंदोलन होते हैं। हमारे ही साथ लगते क्षेत्र में पिछले दिनों ऐसा ही एक आंदोलन हुआ, जिसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। इन लोगों ने ही किसानों को भड़काया था। इन्होंने किसानों को सही बात न बता कर उनको गलत गाइड किया था। जो उम्मीदवार वहां से चुनाव में खड़े होते थे, उनकी पोल अब खुल चुकी है और जनता ने उनको नकार दिया है। इन लोगों ने किसानों को वहां पर जाकर बहकाना शुरू कर दिया था। परिणामस्वरूप वहाँ टकराव के हालात पैदा हो गए थे जिससे कि 4 किसान गोलियों से मारे गए। इसके लिए यहां पर बैठे हुए ये नेता ही सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन के लिए अब वर्तमान सरकार को ही ये करना पड़ रहा है। यह सरकार विकास कार्य न कर पाए इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही इन्होंने ऐसा कुप्रयास किया है। आने वाले समय में और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी ये ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं। जो किसान गोलियों से मारे गए हैं, उनके कट-आउट लेकर घूमने के इस नापाक इरादे में यह कभी सफल नहीं होंगे और इनकी स्थिति भी उस मैथ के प्रोफैसर जैसी ही होगी जिसने नदी पार करते समय अपने पूरे परिवार को ही उस में डुबो दिया था और वह बाहर बैठा हुआ कह रहा था कि "पानी है ज्यों का त्यूं, फिर भी कुनवा डूब्या क्यूं"। इस प्रकार की जो ये राजनैतिक तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता यह महसूस कर चुकी है कि पिछली सरकारें किसानों व बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ नहीं कर पाई हैं। वर्तमान सरकार ने जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि केवल हम यहां सत्ता पक्ष में बैठकर ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसके लिए हमारी सरकार को विश्व बैंक से भी समर्थन मिला है तथा बिजली बोर्ड में सुधार के कार्य-क्रम के लिए विश्व बैंक से 2400 करोड़ रुपये लेने हेतु 15 जनवरी,

[श्री नृपेन्द्र सिंह]

1998 को दस्तखत वगैरह भी हो चुके हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इस सुधारात्मक कार्य के लिए हमें विश्व बैंक से इतनी भारी धनराशि मिली है कि आज तक किसी भी प्रदेश को बिजली के सुधार के लिए हिन्दुस्तान में इतनी बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में नहीं मिली। जो हमारी सरकार इसमें कार्य कर रही है उनको विश्व बैंक ने मान्यता दी है। आप यह समझते ही हैं कि जब विश्व बैंक किसी को कर्ज देने के लिए तैयार होता है तो वह पूरी तफसील करता है और जब वह मान लेता है कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा, जनता की भलाई के लिए खर्च होगा तभी वह पैसा देता है। वर्तमान सरकार जो कार्य बिजली के लिए कर रही है, मैं यह समझता हूं कि यह आज की जरूरतों के मुताबिक और जनता की भलाई के लिए सबसे उचित कदम है और जिसका कल राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि हमारी सरकार ने नीसिंग में 220 के०वी० का एक नया उपकेन्द्र एवं सागा, मूनक, इस्माईलावाद और छाजपुर में 132-132 के०वी० के चार उपकेन्द्र, हथीन और चान्दपुर में 66-66 के०वी० के 2 नए उपकेन्द्र तथा विभिन्न स्थानों पर 33-33 के०वी के 8 नए उपकेन्द्र चालू करने की योजनाएं बनाई हैं।

स्पीकर सर, यह सारे का सारा जो बिजली के बारे में किया जा रहा है, यह उन सारी बातों पर, जिनके बारे में अपोजीशन के नेता सपने लिए बैठे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं कि इस बिजली के मुद्दे पर जनता के बीच में फिर से जाकर कुछ कर सकें पानी फेर देगा।

मैं यह समझता हूं कि अब समय आ गया है जब अपोजीशन में बैठे लोगों की पोल खुल गई है। आज बिजली के मामले में हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है इनको देखते हुए जनता महसूस करने लगी है कि हविपा और भाजपा की गठबन्धन वाली सरकार ही हरियाणा में पूरी बिजली उपलब्ध कराएगी। अपोजीशन में से जो लोग सरकार में रहे, वे अपने समय में कुछ नहीं कर पाए।

आदरणीय राज्यपाल ने कल के अपने अभिभाषण में गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र के बारे में, विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी के बारे में, इलैकट्रॉनिकी के बारे में, कर्मचारियों की भलाई के बारे में विस्तार से चर्चा की। जहां तक कर्मचारियों की भलाई की बात है, हमारी सरकार ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान का लाभ हरियाणा के कर्मचारियों को देने का निर्णय ले लिया है। मैं यह समझता हूं कि कर्मचारियों की भलाई के लिए यह बहुत अच्छा निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। केन्द्रीय सरकार का 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए वरदान सिद्ध होगा और हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी ज्यादा सफलतापूर्वक और ज्यादा सहयोगात्मक तरीके से हरियाणा में काम कर सकेंगे जिससे हरियाणा की प्रगति बढ़ेगी। वे बहुत तेजी से लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा सिंचाई के क्षेत्र में जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया, हथिनी कुण्ड बैराज के बारे में, और जल संसाधन समकेन परियोजना के बारे में बेहतर तालमेल और उपयुक्त चौकसी की बात बताई। साथ ही सिंचाई के लिए नहरों से घास और लगभग 2 लाख पेड़ निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब हमारी सरकार नहीं थी और अपोजीशन में बैठे लोग जब सत्ता में थे तो इन्होंने कभी भी सिंचाई की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जिस वजह से नहरों में बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए थे। अब इन सारे पेड़ों को कटवाकर उनकी नीलामी करने से फोरैस्ट डिपार्टमैन्ट को काफी आमदनी हुई है। अब हमारी सरकार ने इन पेड़ों को निकालकर नहरों को सिंचाई के लिए चालू करवाया है। वर्ष 1995-96 में अपर्याप्त सप्लाई वाले नहर के अन्तिम छोरों की संख्या 352

से घटकर केवल 39 रह गई और इससे मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में क्रान्तिकारी लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की विकास की गति जो आज है उससे बहुत जल्दी हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत ज्यादा खुशहाल होगा। इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है कि मेवात के शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई के लिए 207 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाई जाने वाली मेवात उठान सिंचाई परियोजना तैयार की गई है। मैं समझता हूं कि मेवात का क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जिसकी तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया है हमारे सामने अपोजीशन में बैठे हुए साथियों ने सत्ताधारी पार्टी में होते हुए मेवात क्षेत्र की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार उस क्षेत्र में विकास का एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ले आएगी। बाढ़ के संबंध में सारे हरियाणा प्रान्त के लिए हमारी सरकार एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले हरियाणा सरकार ने बहुत प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश बाढ़ मुक्त होगा। पिछले दो सालों में बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश में जो नुक्सान हुआ था वैसा नुक्सान हरियाणा की जनता को फिर से फेस नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में हमारे सामने बैठे हुए अपोजीशन पार्टी के साथियों ने गन्ने के भाव के बारे में बड़ा जोर दे कर अपनी बातें कहीं थीं। हमारी सरकार ने चालू गन्ना पिड़ाई मौसम के दौरान गन्ने की विभिन्न किस्मों की देश में सबसे ऊंची कीमत 78, 80 और 82 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को देकर उनके प्रति अपनी उदारता और सद्भावना दर्शायी थी। मैं समझता हूं कि जो किसान गन्ने के उत्पादक हैं उनको दूसरे पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में जो दरें मिल रही हैं उससे वे पूर्णतः सन्तुष्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे अपोजीशन के भाई यदि लोगों को भड़काने की कोशिश भी करें और कोई आन्दोलन चलाने की कोशिश करें तो प्रदेश के लोग इनके उस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया है। हरियाणा प्रदेश केन्द्रीय पूल में 25 प्रतिशत गेहूं और 11 प्रतिशत चावल देता है जबकि हरियाणा प्रदेश एक बहुत ही छोटा प्रदेश है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार की, किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके कारण हमारे प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा कर सकेगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सहकारिता, पशुपालन और उद्योग के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पर्यावरण, वन तथा सामाजिक-वानिकी और समाज कल्याण के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है और इस बारे में जो-जो उपलब्धियां हमारी सरकार की हैं उनके बारे में बताया गया है। पिछली सरकारों ने उनको कभी छुआ भी नहीं था। इनके बारे में पिछली सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था उनकी यह तो हालत थी। आज हमारे सामने बैठे हुए अपोजीशन के भाई जिस पार्टी में बैठे हुए हैं वह पार्टी बिल्कुल सिकुड़ गई है और बहुत छोटी सी पार्टी रह गई है। इन्होंने सत्ता में रहते हुए समाज के किसी भी वर्ग की भलाई के बारे में नहीं सोचा इसलिए आज इनकी हालत यह बन गई है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बुढ़ापा पैंशन की बात है, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पैंशन देने की बात है हमारी सरकार के आने से पहले पिछली सरकारों में इस बारे में यह हालत थी कि उनको चार-चार महीने तक पैंशन नहीं मिलती थी। हमारी सरकार आने के बाद यह स्थिति है कि हर महीने की 7 तारीख को विधवाओं, विकलांगों और वृद्ध लोगों को घर बैठे हुए उनके घर पर पैंशन पहुंच जाती है। इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों का हमारी सरकार के प्रति एक विश्वास कायम हुआ है। इस बात का आभास हमारे अपोजीशन के साथी जब अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो महसूस करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोग इनको यह कहेंगे कि ये सत्ता में रहते हुए निकम्मे रहे। ये लोग सत्ता में रहते हुए प्रदेश के किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके। हमारी सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की पैंशन 100 रुपये महीने से बढ़ा कर 500 रुपये

[श्री नृपेन्द्र सिंह]

महीना की है। ऐसा करके हमारी सरकार ने उनके साथ न्याय किया है। इस बारे में पिछली सरकारों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारी सरकार ने 1 जुलाई, 1996 को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला शराब बन्द करने का लिया था। शराब बंद होने से लोगों के जीवन स्तर में बहुत तबदीली आई है और उनका जीवन स्तर पहले की अपेक्षा ऊंचा हुआ है। इस बात का अहसास हरियाणा प्रदेश की सारी जनता को हुआ है। अब लोग दीवाली और होली जैसे पवित्र त्यौहारों पर एक भला आदमी अपने परिवार के साथ घर से बाहर चला जाता हैं। पहले तो घर वाले उसे जाने से मना करते थे, कहते थे कि घर से बाहर न जाओ क्योंकि कोई शराब पीये हुए टकरा जायेगा। शराब पीये हुए आदमी से सभी लोग तंग होते थे। अब उसमें स्थिति यह आई है कि इस बार दीवाली के त्यौहार पर पूरे बाजार की मिठाई 10 बजे खत्म हो गई थी। सभी लोग अपने बच्चों को साथ लेकर बिना डर के बाजार में निकले हैं। पिछले 5-6 सालों में इसके विपरीत स्थिति थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। सरकार ने शराब बंद करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। विपक्ष के लोग बेमतलब इस मुद्दे को उछालते हैं कि हरियाणा में शराब बंदी नहीं हुई। यह एक सच्चाई है, इनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि शराब बंद करने से पहले यह हाल था कि जब प्रातः अखबार डालने वाला आता था तो उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति और साईकल पर आता था और हांक मार कर कहता था कि खाली बोतल वाला, खाली बोतल वाला। अब वह नहीं आता क्योंकि शराब बिकती नहीं इसलिए खाली बोतल उनको मिलती नहीं। अब शराब बंदी की वजह से कबाड़ी वाली दुकान पर केवल ग्लूकोस की ही खाली बोतल नजर आती हैं जबकि पहले शराब की बोतलों के भी उनके पास ढेर लगे रहते थे। इनको ठीक बात करनी चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस बारे में इनको कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि शराब बंद हो जाने से हरियाणा प्रदेश की जनता को बड़ी भारी राहत मिली है। स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने पंजाब एक्साईज एक्ट 1978-79 में संशोधन करके यह किया है कि कोई व्यक्ति यदि शराब की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका वह वाहन जिसमें वह तस्करी कर रहा था, सरकार उस को जब्त कर लेगी। मैं यह समझता हूं कि इस बुराई को खत्म करने के लिए इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती थी। सरकार ने यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। रामायण और महाभारत के समय में भी शराब पी जाती थी जबकि अब इस सरकार ने यानि हमारी सरकार ने शराब का नामो निशान प्रदेश में मिटा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून और व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। कानून व्यवस्था की आज स्थिति यह है कि आज के दिन समाज के 3 वर्ग सबसे ज्यादा दुःखी हैं। एक तो हमारे अपोजीशन में बैठे हुए सारे लोग, इनको सबसे ज्यादा परेशानी शराब बंद करने से हुई है। दूसरे वर्ग में वकील भाई आते हैं वे इसलिए दुःखी हुए हैं क्योंकि शराब बंद होने के कारण अब दंगे-फसाद कम हो रहे हैं और वकीलों के पास केस कम आ रहे हैं जिस वजह से उनको दुःख है। तीसरे वर्ग के अन्दर जो लोग मीट की दुकान चलाया करते थे जिनकी दुकान पर रात को बकरे कटा करते थे, वे दुःखी हैं क्योंकि शराब न मिलने के कारण लोग पीते नहीं और शराब नहीं पीते हैं तो वे मांस आदि भी नहीं खाते हैं। यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि ये तीन वर्ग सबसे ज्यादा शराब बंदी के कारण प्रभावित हुए हैं। अब शराब बंदी के कारण पूरा प्रदेश अमन-चैन से जी रहा है। अगर सबसे ज्यादा परेशानी हुई है तो विपक्ष में बैठे हुए लोगों को हुई है। ये सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। ये सच्चाई से परहेज करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन विभाग से संबंधित विषय पर कहना चाहूंगा। हमारी सरकार ने 567 नई बसें खरीदने का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ सरकार ने राज्य में चलने वाले मैक्सी कैब वाहनों को समूचे राज्य में चलाने हेतु संविदा वाहन परमिट देकर उनको विनियमित करने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ है।स्पीकर सर, इसके साथ ही शिक्षा और साक्षरता के बारे में हमारी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है और विशेष तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरियाणा बनने के बाद इतनी संख्या में स्कूल कभी अपग्रेड नहीं हुए जितने वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर के वक्त में हुए हैं। इसके साथ ही पिछली सरकारों के दौरान में 10-10 सालों से स्कूल अपग्रेड हुए पड़े थे लेकिन वहां पर टीचर्ज नहीं पहुंचे। जितने स्कूल हमारी सरकार ने अपग्रेड किये इतने इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं किए थे। जो स्कूल हमार सरकार ने अपग्रेड किये हैं उन सभी में क्लासें चल रही हैं और टीचर्ज अगले दर्जे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भारी काम किया है। जहां तक पीने के पानी का ताल्लुक है, हरियाणा बनने से लेकर आज 31 साल तक किसी भी सरकार ने पीने के पानी के बारे में कभी सोचा नहीं था कि खाने से पहले भी पानी की जरूरत होती है लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर पूरा ध्यान दिया है और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी लोगों को दिया जा रहा है और घरों में भी पीने के पानी के कनैक्शन्ज दिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो काम न केवल हरियाणा बनने के बाद से शुरू होना चाहिए था बल्कि देश के आज़ाद होने के बाद ही हो जाना चाहिए था वह काम भी हमारी सरकार ही कर पाई है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हिन्दुस्तान को आज़ाद हुए पूरे 50 साल हो गए हैं लेकिन पीने के पानी की समस्या खत्म नहीं हुई है। आज हरियाणा की वर्तमान सरकार के समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण विकास, चिकित्सा-स्वास्थ्य की देखभाल एवं पंचायत के क्षेत्र में भी जो फैसले हमारी सरकार ले रही है उससे जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। जिस बात से सबसे ज्यादा जनता तंग और परेशान थी वह भवन और सड़कों का काम है उससे भी अब लोगों को निज़ात मिली है और भवन तथा सड़कों के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। सड़कों के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो प्रयास किये हैं मैं मानता हूं कि पिछली सरकार को लोगों ने इसी लिए नकार दिया था क्योंकि उनकी सड़कों की हालत ऐसी थी जो बहुत ही खस्ता थी। पिछली सरकारों के जाने का एक मुख्य कारण यह भी रहा है। आज हमारी सरकार ने सड़कों की मुरम्मत के काम में और नई सड़कों के निर्माण के काम में पूरी तवज्जो दी है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोग सोचते हैं कि सड़कों के नाम से एक मुद्दा बनाया जा सकता है। पर्यटन, खेलकूद तथा श्रम तथा रोज़गार के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विस्तार से चर्चा की है। मैं यह मानता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उसमें टोका-टाकी की गई थी, स्पीकर सर, यह एक परम्परा सी बन गई है, एक ट्रैंड बन गया है कि राज्यपाल के अभिभाषण में ओपोजीशन की तरफ से टोका-टाकी हो। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो चर्चा की तथा जो बातें बताई मैं समझता हूं कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर टोका टाकी की जाती लेकिन ओपोजीशन के लोग यह महसूस करते हैं कि ये सब बातें जनता तक पहुंचेगी और जनता की आंखे खुल जाएंगी और जनता इन लोगों को घुसने नहीं देगी और इनसे यह सवाल पूछेगी कि जब तुम सत्ता में थे तो इन कार्यों को पूरा क्यों नहीं किया ? आज ये लोग उन बातों को मुद्दा बनाने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि इनका यह प्रयास अच्छा नहीं होगा।स्पीकर साहब, मैंने जो बाते बताई हैं उनके साथ ही मैं बिजली के क्षेत्र के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी अपोजीशन के हमारे साथियों को बिजली के बारे में ही है। आज ये जहां भी जाते हैं वहां पर बिजली को ही मुद्दा बना रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता

[श्री नृपेन्द्र सिंह]

हूं कि हमारे क्षेत्र में बिजली के ट्यूबवैल्ज़ बहुत कम हैं। हमारे यहां के जो किसान हैं उनके पास अपने ट्यूबवैल्ज़ इतने ज्यादा नहीं हैं और वे पड़ौसी किसान से पानी लेते हैं। ट्यूबवैल वाला उनसे 30 रुपया प्रति घंटा पानी का लेता है। 8 घंटा प्रतिदिन बिजली का हिसाब लगाएं तो 30 8 30 दिन का 7200 रुपये बनता है। इस हिसाब से जो बिजली बेचता है वह तो अपने महीने का बिल अढ़ाई दिन में पूरा कर लेता है। उसका महीने का बिल 6 सौ रुपये का होता है बाकी साढ़े 27 दिन वह सरकार से बिजली मुफ्त लेता है। हमारी सरकार बिजली के बारे में आज जो प्रयास कर रही है, उससे हरियाणा में बिजली की प्रोब्लम को खत्म किया जा सकता है। अपोजीशन को यह प्रोब्लम है कि अगर हमारे प्रयास पूरे हो गए तो लोग इनको पूछेंगे नहीं। इसलिए ये इस काम में अड़चन डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यबाद करता हूं। जय हिन्द।

Mr. Speaker : Now, Shri Nirmal Singh, M.L.A. will second the motion.

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया मैं उसका अनुमोदन करता हूं। राज्यपाल महोदय, ने बड़े विस्तार से चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार के पिछले डेढ़ वर्षों के कार्यों की और नीतियों की उसमें चर्चा की है। हमें बड़ी खुशी हुई कि थोड़े समय के अर्से में इस सरकार ने काफी अचीवमैंट्स की हैं। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार की जो नीतियां हैं उनसे ऐसा लगता है कि हमारी स्टेट एक बार फिर से तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होकर रहेगी और हिन्दुस्तान की सभी स्टेट्स में आगे रहेगी। अभिभाषण में सभी विभागों का जिक्र किया गया है और ऐसा लगता है कि हर विभाग में नई तबदीलियां की गई हैं, नई बातें की गई हैं। लेकिन साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, हमें दुख भी होता है कि पिछले 20 सालों के अध्याय पर नजर मारते हैं तो लगता है कि पिछले 20 साल स्टेट की तरक्की रुकी रही। पिछली सरकारों ने स्टेट की तरक्की और खुशहाली तथा लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ किया होता तो आज हमारा स्टेट कहां होता। (विघ्न) स्पीकर साहब, आज से 30 साल पहले इस स्टेट का जन्म हुआ था और अगर हम सब थोड़ा गौर से देखें तो उस वक्त हमारी स्टेट का क्या हाल था। दूसरी स्टेट्स यह कहती थीं कि ये लोग अपनी स्टेट के कर्मधारियों को तनख्वाह कहां से देंगे। उस वक्त हमारी स्टेट का बहुत बुरा हाल था। अकाली पंजाबी सुबे की मांग करते थे तो उस समय हमारी इस स्टेट की क्रिएशन हुई थी। उसके बाद यह स्टेट एक ऐसे आदमी के हाथों में आयी जो कि केवल स्टेट के बारे में ही सोचता था जिसका नजरिया बहुत तरक्की पसंद था और वह आदमी था चौधरी बंसीलाल। उन्होंने उस समय स्टेट में बहुत मेहनत की और इसको इतना चमकाया कि पंजाब के बाद हरियाणा का नम्बर आने लगा। हर क्षेत्र में चाहे वह उद्योग हो, एजुकेशन हो या ऐग्रीकल्चर हो, सबमें स्टेट ने बहुत तरक्की की। सड़कों के क्षेत्र में तो यहां तक तरक्की हुई कि यह स्टेट ऐसा पहला स्टेट था जो हर गांव से सड़कों को जोड़ने वाला बना। इसके अलावा हरियाणा में हर गांव में बिजली भी पहुंचायी गयी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह स्टेट ऐसे हाथों में चली गयी कि फिर विकास के काम होने बंद हो गये। आज बिजली के क्षेत्र में चौधरी बंसीलाल जी ने अपने डेढ़ वर्ष के शासन काल में ही बहुत कुछ कर दिखाया है। बिजली के क्षेत्र में जो रैवोल्यूशनरी ये लाने जा रहे हैं उसकी इतिहास गवाही देगा कि हरियाणा की जनता के लिए चौधरी बंसीलाल जी ने कैसे कदम उठाए हैं। आज जिस रास्ते पर चौधरी बंसीलाल जी स्टेट को ले जा रहे हैं वह सराहनीय है। पिछली सरकारों ने तो बिजली

की तारें तक नहीं बदलीं। आज जो तारें हैं उनकी उम्र दस या पन्द्रह साल की बताते हैं लेकिन आज ये तारें बीस-बाईस साल पुरानी हो गयी हैं। सर, यह सब रिकार्ड की चीजें हैं। पिछली सरकारों ने कोई नया कारखाना नहीं लगाया, कोई नया प्लांट नहीं लगाया और न ही कोई बिजली का उत्पादन बढ़ाया। जबकि आज ये लोग बिजली के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और भोले-भाले किसानों को बिजली के बिल न देने के लिए उकसाते हैं तथा अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किस तरह से ये चालीस-चालीस विधायकों को दल बदल करवाकर इधर से उधर लेकर गये।

एक आवाज : आपकी तरफ भी दो दलबदलू बैठे हैं।

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हम समता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे लेकिन जब बाद में हमने इलैक्शन के खर्च का हिसाब मांगा तो हमें हिसाब नहीं दिया गया और हमें पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में चले गये। ये ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिएं। अब आपकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। (विघ्न) ओम-प्रकाश चौटाला सब बातें जानते हैं। इनके पास कोई नहीं आना चाहेगा क्योंकि आपकी कारगुजारी ही ऐसी है। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : आप तो एक घंटे तक चौधरी बंसीलाल जी को गालियां दिया करते थे और अब आप इनके साथ हैं। आप कहते थे कि मुझे इन्होंने बीस साल तक बाहर बिठा कर रखा।(विघ्न)

Mr. Speaker : I would request all the Hon'ble Members to avoid controversy.

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्टेट में जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे स्लोगन दिए गए जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं थे। यह घोर पाप है। इन्होंने एक कर्जा माफी का भी स्लोगन दिया था और उस समय इन्होंने किसानों को उकसाया कि आप कर्जा न दें। इस तरह से इन्होंने उन किसानों के रिश्ते हर बैंक से, सारी दुनिया से तोड़ दिये। अध्यक्ष महोदय, जब बैंक नेशनलाइज हुए थे तो हम सब बड़े खुश थे कि आज बैंक से हमारा रिश्ता बन गया अब हम तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। जब बैंक नेशनलाइज नहीं थे तो हमारे बुजुर्गों का पैसा साहूकारों के पास 5 परसैंट के रेट से 60-60 परसैंट पर फंसा हुआ था तब हमारा खेतों की मेहनत का सारा पैसा ब्याज के रूप में चला जाता था। जब किसानों को इस बात का पता चला कि बैंक नेशनलाइज हो गए हैं तो किसान लोन लेते थे, लौटाते थे और तरक्की के रास्ते पर बढ़े जा रहे थे लेकिन बाद में ऐसे स्लोगन दिये गये कि सभी बैंकों से हमारा रिश्ता तोड़ दिया गया और लॉंग व शॉर्ट टर्म लोन सब पर बंदिश लग गई और यह हो गया कि 100 रुपये लेकर 200 रुपये लौटा दो तो कर्जा माफ है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि तब हमारी स्टेट की क्या हालत हुई थी। कोई भी किसी भी किस्म के लेनदेन के लिए तैयार नहीं था बाद में यह सारी बातें हाउस में रिमूव करनी पड़ीं, रद्द करनी पड़ी। इसके साथ ही इस स्टेट में दलबदल की बातें हुई। 40-40 विधायक एक रात में स्टेट में बदल गए। जब सिर्फ इन बातों की ओर ध्यान हो कि हमने कुर्सी कैसे हथियानी है तो फिर स्टेट की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, राज्य तक सीमित होकर रह जाती हैं। अपोजीशन के सदस्यों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि जब भी वह क्रीटिसिज्म करें तो हैल्दी करें। इस हाउस में क्या नहीं होता। आपकी कुर्सी की तरफ शोक प्रस्ताव की आड़ में उंगली उठाई जाती है। गवर्नर साहब के अभिभाषण के बीच में वाकआउट किया गया। यह सब अच्छी कन्वैंशन नहीं है। हम

[श्री निर्मल सिंह]

सभी की ड्यूटी इस हाउस की गरिमा को कायम रखने की है। कई बार हमारे साथियों की ओर से चैलेंज हो जाता है कि लोगों में चलो, 16 फरवरी को फैसला होगा तो फैसला जो होगा वह तो होगा ही। जो भी फैसला होगा उस पर घमंड की क्या जरूरत है। लोगों की कचहरी तो ऐसी है जिसमें से सभी लीडर्ज ने गुजरना है और अपना हिसाब देना है, यह तो समय बताएगा। बहुत बार लोग हारे हैं, बहुत बार लोग जीते हैं, ऐसा आगे भी होता रहना है। (विघ्न) इसमें घबराने की क्या बात है हम हर बात के लिए तैयार हैं। अब मैं आपके घबराने की बात सुना देता हूं बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें दे दीं यह घबराहट नहीं तो और क्या है। आपका और बहुजन समाज पार्टी का आपस में क्या लेन-देन है। लोगों का फैसला देखना आपको रिजैक्ट करेंगे ना थारे वाले उनको वोट पाएंगे, न उनके वाले थारे को वोट पाएंगे। अगर यह समझौता एक दूसरे को धोखा देने के लिए किया गया है तो यह अलग बात है। यह समझौता छोटे-छोटे लाभ उठाने के लिए किया गया है इसका आप रिजल्ट देख लेना। एक तरफ इन्होंने जाट बांट दिए और दूसरी तरफ भजन लाल जी ने नॉन जाट लीडर बनने की कोशिश की। कांशी राम ने * * * * लीडर बनने की कोशिश की तो फिर रौला किसका रह गया। यह सब इस बात का सबूत है कि यम घबराए हुए हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह शब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्री निर्मल सिंह : स्पीकर सर, आज जो इस तरह के समझौते किये जा रहे हैं इनका विश्वास तो यहीं पर देखा जा सकता है। इन्होंने लोक सभा चुनाव की 10 सीटों में से 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दे दी हैं। अगर लोकसभा के चुनावों में समझौता किया है तो फिर विधानसभा के चुनावों में भी इन्हें 90 सीटों में से 30 सीटें बहुजन समाज पार्टी को देनी पड़ेंगी। (विघ्न) हम तो सभी आजाद विधायक बंसी लाल जी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे (शोर एवं व्यवधान) हम तो अपनी ईमानदारी निभायेंगे। हमें तो खुशी है कि फूल का निशान वाली पार्टी आये क्योंकि हमें तो उसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी निर्मल सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने श्री कांशीराम जी को देश का प्रधान मंत्री बनाने के लिए कहा था लेकिन श्री कांशीराम जी तो एम०पी० का चुनाव लड़ने के लिए ही मना कर गये और अपने घर पर बैठे हैं ऐसा इनकी पार्टी का गठन है।

श्री निर्मल सिंह : पूनिया जी को इन्होंने अपने साथ मिलाया और उस गरीब हरिजन को तीन बार कूटा गया तथा * * * * गवर्नर जी को ताऊ जी ने कूट दिया।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो महामहिम राज्यपाल जी के लिए बेचारे शब्द का प्रयोग किया है इसे कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष : गवर्नर महोदय के लिए जो बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया है यह कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उसके बारे में लेश मात्र भी उल्लेख

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

नहीं किया गया है चाहे आप रिकार्ड उठाकर देख लें। शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी साथी बोले हैं उन्होंने अभिभाषण के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो फिर आपकी मर्जी है, आप अपनी चलाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। (शोर) अध्यक्ष महोदय, चुनाव सिर पर हैं और इस सरकार को भी आखिर लोगों को जवाब देना है। इसलिए आगे क्या होने वाला है, कम से कम इसके वास्ते तो सुनने की कोशिश करिए। जो चीज अभिभाषण में लिखी हुई नहीं है, उसके बारे में अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। आखिर यह सदन है। इसकी कुछ सीमा होती है । (शोर)

श्री निर्मल सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो शोक प्रस्तावों के समय में ही अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने की कोशिश की थी। (शोर) स्पीकर सर, अभिभाषण पर बोलते समय कुछ न कुछ "पॉलिटिकल हैल्थ" के बारे में भी बताना पड़ता है। अभी अभिभाषण में बिजली के बारे में चर्चा हुई। इस में चौधरी बंसी लाल जी के प्रयत्नों का जिक्र किया गया जिनको देखते हुए हरियाणा राज्य 2400 करोड़ रुपये विश्व बैंक से लेने में कामयाब हुआ। दूसरी तरफ हम यह नारा सुनते जा रहे हैं कि बिजली के बिल माफ कर दिये जाएंगे। अगर ऐसा नारा लगाया जाएगा तो हमारे राज्य को कोई भी कर्जा देने वाला नहीं मिलेगा। इसकी बड़ी भारी जिम्मेवारी आप लोगों पर है और ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग आपसे इन सब बातों का हिसाब लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर कर्जा माफी का नारा इतना असरदार होता तो फिर दोबारा ये साथी इलैक्ट होकर के आते। आज तो 100 रुपये भी अगर किसी के माफ कर दिये जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। यहां तो हजारों करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जब राज्य के विकास की बात होती है तो और भी बहुत सारी बातें होती हैं। इनके समय में तो प्रजातंत्र ही खतरे में पड़ गया था और लोग डरने लगे थे। चौधरी बंसी लाल जी भी कह रहे थे कि ये तो अपने समय में कह देते थे कि मीटिंग से उठकर चला जा। वास्तव में मैं भी उस समय डरने लगा था क्योंकि इन्होंने मेरे को एक बार अम्बाला में लठ मरवाए थे। (शोर) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य आज चहुंमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है और पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। इस सरकार की आज जितनी भी तारीफ की जाए, वह कम है। हरियाणा राज्य में आज की तारीख में कुल 800 मैगावाट बिजली का उत्पादन होता है। आने वाले समय में यह बढ़कर 1100 मैगावाट से भी ज्यादा हो जाएगा और हरियाणा दूसरे राज्यों को भी बिजली बेचने लगेगा। अध्यक्ष महोदय, छोटे-मोटे कार्यों के लिए भी आज बिजली की जरूरत और बढ़ गई है। पहले जब बिजली पैदा हुई थी, उस समय तो लोग बिजली लेने से ही इन्कार करते थे, कहते थे कि बिजली कनैक्शन लेने से घर में आग लग जाएगी। आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ट्यूबवैल कनैक्शन कितने होते थे, और आज कितने हैं। छोटे-छोटे कार्यों के लिए जैसे कि दूध बिलौना, आटा गूंथना, कपड़े धोना इत्यादि के लिए भी मशीनें बन गई हैं और परिणामस्वरूप ज्यादा बिजली खर्च होने लगी है। इस बढ़ती जरूरत को देखते हुए अगर ये साथी कुछ विकासोन्मुख कार्य समय रहते कर लेते तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी थी। लेकिन शुक्र है कि आने वाले दो सालों में हम बिजली की समस्या पर काबू पा लेंगे। यह कितनी खुशी की बात है।(शोर) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कृषि विभाग के क्षेत्र में यह प्रचार किया गया कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार द्वारा गन्ने का भाव कम दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुकाबले गन्ने का भाव दो रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा दिया है। इनके समय में तो यह कहा जाता था कि किसानों का सारा गन्ना मिलें नहीं उठा सकती हैं। दूसरी तरफ चौधरी बंसी लाल जी ने सभी गन्ना मिलें चलवाई हैं और गन्ने की पोरी-पोरी उठायी जा रही है। आज राज्य में गन्ना पीड़ने की क्षमता इतनी अधिक बढ़ गई है कि समय से पहले ही सरकार द्वारा गन्ना उठा लिया जाता है। इसके अलावा, सिंचाई

[श्री निर्मल सिंह]

15.00 बजे के क्षेत्र में पिछली सरकारें नहरों के टेल-एंड तक पानी पहुंचाने में असफल रही हैं। आज नहरों की सफाई हो जाने से 6 लाख एकड़ फालतू भूमि की सिंचाई हुई है। स्पीकर सर, शराबबन्दी के बाद क्राइम कम हुआ है। पिछली सरकार में रेणुका, सुशीला और द्रौपदी काण्ड हुए उनके बारे में पुलिस ने क्या किया है, आज तक सी०बी०आई० की इन्क्वायरीज लटकी हुई हैं। हम यह मानते हैं कि सोसायटी में क्राइम हो सकता है लेकिन सरकार उसको कैसे लेती है, सरकार मुजरिमों को पकड़ती है या उनको शैल्टर देती है। सुशीला, रेणुका और द्रौपदी काण्डों में आज तक दोषियों का पता नहीं चला है। पिछली सरकार तो अपनी पूरी शक्ति अपने विरोधियों को दबाने में लगाया करती थी। अपने राजनैतिक विरोधियों को दबाने के लिए हर हथियार अपनाया करती थी। बंसी लाल जी की सरकार में आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं मिली है। इसके साथ जाति-पाति के अन्तर में किसी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, किसी ने अजगर पार्टी बनाई और किसी ने समाज से जाटों को अलग डाल दिया। कौन सी ऐसी बात है जो इस स्टेट में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होती रही है। यह बहुत सुन्दर स्टेट है, इसमें बहुत टेलन्टिड लोग हैं, बहुत मेहनती किसान हैं। बंसी लाल की सरकार पर जाति-पाति के नाम का किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया है। करप्शन में तो पिछली सरकारों के समय में हरियाणा पूरी तरह से बदनाम हुआ था। उस समय जब करप्शन की बात चलती थी तो तरह तरह की बातें चलती थी, हरियाणा के विधायकों और लीडरों को बिकाऊ कहा जाता था लेकिन आज की सरकार में कभी भी नौकरियों के मामले में या किसी और मामले में इस प्रकार की बात नहीं कही गई। इस सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। पहली बार इस सरकार में मैरिट पर नौकरियां दी जा रही हैं, सिफारिश और पैसे से नहीं दी जा रही। (विघ्न) स्पीकर सर, पिछले डेढ़ वर्ष के थोड़े समय में बंसी लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने चहुंमुखी तरक्की की है। इस सरकार से आने वाले समय में हमें और इस स्टेट के लोगों को बड़ी आशाएं हैं और भगवान बंसी लाल जी को लम्बी उम्र दें और लम्बे समय तक राज करने का समय दे। हम इस स्टेट को स्वर्ग बना देंगे और उस पर जो दाग लगे हैं उनको धो देंगे। एजूकेशन के बारे में पिछले एक साल में लगभग 385 स्कूलों को अपग्रेड किया गया जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। मैं शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा जो सुबह वीरेन्द्रपाल जी अंग्रेजी को पहली कक्षा से पढ़ाने के बारे में कह रहे थे उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। स्पीकर साहब, अंग्रेजी बोलना आप मान लो नैसेसरी है। यह माना कि अंग्रेजी एक बुराई है लेकिन हमारे बच्चों को कम्पीट करना है। आप हिन्दी में चाहे जितनी मर्जी बात करें लेकिन आज अंग्रेजी के बिना गुजारा भी नहीं है। अंग्रेजी के बिना हमारे बच्चे पिछड़े हुए हैं। इस तरफ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। आज एक सवाल के जवाब में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने यह बताया था कि हमारे प्रदेश में 6 साल की उम्र में बच्चा अंग्रेजी सीखना शुरू करता है। मैं कहता हूं कि आप बच्चों को पहली कक्षा से ही अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दें ताकि वे कम्पीट कर सकें। आप कहते हैं कि यदि बच्चों को पहली कक्षा से ही अंग्रेजी सिखाना शुरू करते हैं तो उनके बस्तों का भार बढ़ जाएगा। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बनना चाहता या डाक्टर नहीं बनना चाहता तो हिसाब और साईंस के लिए मास्टर बच्चों को क्यों पीटते हैं। अंग्रेजी ही क्यों, अगर आपने बच्चों को सिखानी ही है तो उनको चार पांच लैंगवेजिज सिखाएं। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी एक इन्टरनैशनल लैंगवेज है। आप कहीं भी जाएं वहां पर आपको अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे और हिन्दी बोलने वाले बहुत ही कम यानि नाममात्र के मिलेंगे। जो अंग्रेजी बोलता है उसको एक किस्म से सबसिडी मिलती है। यदि कोई अंग्रेजी बोलने वाला है तो उसको किसी भी दफ्तर में जल्दी घुसने दिया जाएगा लेकिन जो हिन्दी बोलने वाला है उसको प्रार्थना करने पर भी दफ्तर में नहीं घुसने दिया जाता

है। अंग्रेजी बोल कर आदमी दूसरे को इम्प्रेस कर सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि पढ़ाई के सारे सिस्टम को टेलीविजन के माध्यम से शुरू कर दें ऐसा करने से बच्चों के बस्तों का भार भी कम होगा क्योंकि बस्तों के भार के कारण बच्चों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। जो स्कूलों के टीचर हैं उन पर आप चाहे जितनी मर्जी सख्ती कर लें फिर भी वे अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाते, वे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। आजकल जिस लैवल के टीचर हैं वे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा सकते। आजकल के टीचर्ज ऐसे हैं शायद बच्चों को पढ़ाना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाई के सारे सिस्टम को टेलीविजन के हवाले कर दें, उसके लिए चाहे आपको एक चैनल के लिए 20 या 30 करोड़ रुपये देने पड़ें। जैसे टेलीविजन में कोई साईंस का लैक्चर आएगा तो साईंस पढ़ने वाले बच्चे उस लैक्चर को ध्यान से सुनेंगे और यदि हिसाब के बारे में लैक्चर होगा तो हिसाब पढ़ने वाले बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी बच्चे को 12वीं कक्षा तक पढ़ कर इंजीनियर नहीं बनना है और वह हिसाब पढ़ना चाहता है तो उसका ज्ञान जमा नफी तक ही रहेगा। यदि कोई बच्चा साईंस पढ़ने वाला है तो उसको टेलीविजन पर दिया गया लैक्चर ही काफी होगा। इसमें क्या हिच है। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी भाषा सीखना एक बहुत बड़ा हथियार है। आप जानते हैं कि आप कहीं पर भी जाओ अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप वहां पर कामयाब रहेंगे। आज सुबह डॉ० वीरेन्द्र पाल जी ने अंग्रेजी के बारे में जो बातें कही थीं वे ठीक थीं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शराब बंदी के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। चौधरी बंसी लाल ने प्रदेश में शराब बंद करने का एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। आज हम कहते हैं कि इसमें हमें 90 परसैंट कामयाबी मिली है। मेरे सामने बैठे भाई कहते हैं कि इसमें हमको 50 परसैंट कामयाबी मिली है। ये इस बात को नहीं मानते हैं कि इसमें सरकार को 90 परसैंट कामयाबी मिली है। स्पीकर साहब, शराब बंद करने के बारे में विल पावर की बात है। हमारे मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी की विल पावर बहुत अच्छी है, उनकी नीयत साफ है। एक बहुत बड़े रेवैन्यू का घाटा सहते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश से शराब को बंद कर दिया। हरियाणा प्रदेश में शराब बंदी से पहले घर घर में क्राइम होते थे, गांव गांव में गुण्डागर्दी होती थी। जिन औरतों के पति शराब पीते थे जिनके बच्चे भूखे मरते थे यही नहीं छोटे छोटे बच्चों ने शराब पीना शुरू कर दिया था। (शोर) स्पीकर साहब, विपक्ष ने शराब बंदी के मामले में या दूसरे मामलों में कभी भी सहयोग पूर्ण रवैया नहीं अपनाया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इनमें कोई दिलेरी भी नहीं है। जब एक बार इनसे पूछा गया कि क्या आपका राज आ गया तो आप शराब खोल देंगे तो इस पर वे चुप हो गये । इनको जवाब नहीं सूझा। शराब बन्द करना कोई आसान काम नहीं है। हमारा हरियाणा प्रदेश 7 स्टेटों से लगता है। अब यह शराब लीगली बंद कर दी गई है। अब यह इललीगली हो गई है। यह सही बात है कि हमारे लोग अभी शराब बंद करने के बारे में मेन्टली तैयार नहीं हैं। अगर ये समाज के हितकारी हैं तो इनका सहयोगपूर्ण रवैया होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब से बंसी लाल जी ने राज्य की दुबारा से बागडोर संभाली है तब से ये हर विभाग में तेजी लेकर आये हैं। इन्होंने करप्शन पर काबू पाया है। नौकरियों और तबादलों में जो पैसे खाये जाते थे उनको बंद किया है। इस बुराई पर काबू पाया गया है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जब जब इन्होंने हरियाणा प्रदेश में सरकार की बागडोर संभाली तो इन्होंने यानि हमारे प्रिय नेता चौधरी बंसी लाल जी ने प्रदेश से मोहब्बत करके इसको चार चांद लगाए हैं और जब जब नादानों के हाथों में यहां की बागडोर गई तो उन्होंने प्रदेश की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Motion moved---

[Mr. Speaker]

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 19th January, 1998."

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है विशेष रूप से बिजली के मुद्दे के प्रस्ताव से उन्होंने अपनी चर्चा शुरू की और अपनी चर्चा में हर मामले में सरकार की बहुत मुद्दा सराई करने की कोशिश की। बिजली के उत्पादन को बढ़ा हुआ बताया गया और बिजली के वितरण की पालिसी को बहुत ठीक बताया। साथ ही बिजली सस्ती देने की बात की गई । इसके साथ साथ विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा से चुन कर आये हुए प्रतिनिधियों ने खासतौर से विपक्ष पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश कि इन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात जग जाहिर है कि हमारी सरकार के वक्त में बिजली लोगों को 24 घंटे मिलती थी। इस बात की ये साथी भी यहां पर भले ही सराहना न करें लेकिन बाहर तो ये भी इस बात की सराहना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिजली सस्ती भी थी। मैं, मेरे उस दोस्त को सरकार के आंकड़ों के द्वारा यह बात बता दूं कि हमारी सरकार के वक्त में एक से 40 यूनिट तक बिजली 65 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती थी, 41 से 60 यूनिट तक 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती थी, 100 यूनिट तक 1 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती थी और आज डोमैस्टिक बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है। लीडर ऑफ दि हाउस ने पिछले सत्र में भी इस हाउस को गुमराह करने की कोशिश की थी। मैं पुनः यहां यह बता दूं कि कमर्शियल बिजली 3.35 रुपये प्रति यूनिट कि हिसाब से मिलती है और डोमैस्टिक बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है। जहां तक दक्षिणी हरियाणा का ताल्लुक है, हमारी सरकार के वक्त सलैब प्रणाली लागू की गई थी। जहां 50 फुट तक पानी जमीन में गहरा था वहां बिजली का फ्लैट रेट 18 रुपये प्रति हॉर्स पावर, 50 से 80 फुट तक जहां पानी गहरा था वहां पर बिजली का 14 रुपये प्रति हॉर्स पावर तक का रेट था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में बिजली मिलती थी 12 रूपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से। जहां 80 फुट से पानी अधिक गहरा था उस क्षेत्र में लोगों की एक विशेष मांग थी कि वहां पानी का लैवल नीचे जा रहा है इसलिए हमें और रियायतन दर पर बिजली दी जाए। इसी बात को लेकर उस वक्त कांग्रेस सरकार के समय में वहां के लोगों ने एक आन्दोलन किया था। मैं इस बात को थोड़ा और साफ कर देना चाहूंगा कि वह आन्दोलन किसी राजनैतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं था और न ही यह आन्दोलन भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ था। वह आन्दोलन उस इलाके के किसानों की विकास समिति द्वारा चलाया गया था। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने भी उन किसानों पर गोलियां बरसाई थीं। सदन के नेता को याद होगा कि कादमा में 5 लोग मारे गए थे तब चौधरी बंसी लाल जी स्वयं उस गांव में गए थे और कह कर आए थे कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, हमारी सरकार आने दो इस मामले में आपकी मदद हम करेंगे और मेरी सरकार आते ही आपके वारे-न्यारे कर देगी। अध्यक्ष महोदय, शायद ये भूल गये होंगे और आप भी इस तरफ बैठा करते थे और आपने भी उस काण्ड को जोर से उठाया था। कादमा काण्डा को सिर पर उठाने वालों में आप भी शामिल थे और आप भी कहा करते थे कि बड़ा अत्याचार और अन्याय हो रहा है। चौधरी बंसी लाल जी जब मुख्य मंत्री बने और जिस काण्ड को ले कर मुख्य मंत्री बने उस काण्ड से जुड़े 17 गांवों के लोग चौधरी बंसी लाल जी को जब ये चुनाव जीत कर पहली बार अपने हल्के भिवानी में गये और दादरी के रैस्ट हाउस में रूके तो वहां पर इनसे मिलने के लिए गए। मुख्य मंत्री

बनने से पहले आम सभाओं में चौधरी बंसी लाल जी यह बात कहा करते थे कि मैं अब वह बंसी लाल नहीं रहा, अब मैं बदल गया हूं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह बात है कि कुत्ते की पूंछ 12 बरस तक भी नलकी में रखी रहे तो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अध्यक्ष महोदय, ये बदले नहीं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, पिछले सैशन में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोलते हुए कई बार गैर जिम्मेदाराना बातें कही थीं। जब ये बोलते हैं तो ये इस बात को भूल जाते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा का यह महान सदन और हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति हर बात को बड़ी गहराई से देखता है और समझता है परन्तु ये बोलते हुए पता नहीं क्या अनाप-शनाप बात कह देते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इस प्रकार की कोई बात कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। इन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदन के नेता के प्रति इस प्रकार की बातों को न कहें जो कि गरिमा के प्रतिकूल हों। ये बोलते हुए इस बात को जरूर ध्यान में रखें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी भाषा सदन में भी वही है और सदन के बाहर भी वही है। दिन में भी वही है और रात में भी वही है क्योंकि मेरा वास्ता ऐसे दोस्तों से पड़ता है जो सदन में और तरह की बात करते हैं और रात को मेरे से बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं और बातें नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यह मामला 16 फरवरी तक का ही है और इन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आज कौन कैसे टाईम काट रहा है इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें यहां पर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भेजा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे किसान अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे थे और मौजूदा सरकार ने उन्हें गोलियों से भून दिया। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि किसान आन्दोलन कर रहे थे। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी की टिकट से बाढड़ा से जो उम्मीदवार थे, वे नृपेन्द्र सिंह से 27 हजार वोटों से हार गए और नृपेन्द्र सिंह जी आज यहां पर बैठे हुए हैं। उस उम्मीदवार ने बाढ़ड़ा में बकाया बिजली के बिल माफ किए जाएं की बात को लेकर आन्दोलन शुरू किया था। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से यह सरकार बनी है उस दिन से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी भजन लाल ने मिलकर हरियाणा में चाहे गवर्नर साहब से मिले हैं, चाहे जनता में गए हैं, चाहे किसी की भैंस ने कौली भर दूध नहीं दिया हो तो भी कहने लगे कि बंसी लाल की सरकार को डिसमिस करो। किसी की गधी को जुकाम हो गया हो तो कहने लगे कि बंसी लाल की सरकार को डिसमिस करो। इसके अलावा आज तक इन्होंने और कोई काम नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, वह उम्मीदवार झोझू गांव जो कि एक बहुत बड़ा गांव है वहां का रहने वाला है। यह वहां पर बैठकर आन्दोलन करना चाहते थे तो वहां के लोगों ने कहा कि हमने आपको चुनाव में बता दिया है और हम आपको यहां पर बैठने नहीं देंगे। फिर ये कादमा, महेन्द्रगढ़ और नारनौल रोड़ पर पाली गांव और नांगल सरोही गांवों में बैठ कर आन्दोलन करने के लिए गए मगर वहां के गांवों वालों ने भी इनको वहां पर आन्दोलन करने नहीं दिया। नांगल सरोही के किसानों ने इनको कहा कि हमारे यहां आपके वाली समस्या नहीं है, यदि आपने आन्दोलन करना है तो आप भिवानी में करो हम आपकी मदद करेंगे। फिर ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर बाढ़ड़ा में जो सड़क है वहां पर गए और वहां पर आन्दोलन किया। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला हिम्मत करके क्यों नहीं कहते कि किसानों को भड़काने का यह सारा काम इनकी पार्टी के उम्मीदवार ने किया जो इनकी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था। वह किसान संघर्ष समिति का प्रधान था, उसको तो लोक दल

[श्री राम बिलास शर्मा]

का प्रधान कहना चाहिए। स्पीकर साहब, आज ये पार्टी की बात करते हैं। इनकी पार्टी तो विधान सभा में बैठे बैठे ही बदल गई। भाई रामपाल माजरा कह रहे थे कि हम आए तो समता पार्टी से थे और बन गए हलदोरा। स्पीकर साहब, मुझे एक कहावत याद है जो गांव के सयाने लोग सुनाया करते थे। स्पीकर साहब, कुछ कावर थे वे स्कूल में गये और स्कूल में साथियों ने पूछा कि तुम्हारी गोतजात क्या है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, चौटाला साहब ने जो शुरूआत की है मैं उसकी फैक्चुअल जानकारी इस महान सदन को दे रहा हूं। इसमें कहीं भी अगर 19-20 की बात हो तो आप बताएं। ये इल्जाम लगाएं और अगर हम भुनते रहें तब तो ठीक है लेकिन इनको सच्चाई भी सुननी चाहिए। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, ये पार्टी की बात करते हैं (विघ्न) यह बार बार 16 फरवरी की बात कह रहे हैं तो इनकी तो पार्टी बैठे बैठे बदल जाती है। ये कोई भी दूसरा चुनाव पहले वाले निशान पर नहीं लड़ते हैं। पिछली बार ये छत्तरी लगा रहे थे कि आ जा कमला क्यों भीगे खड़ी खड़ी और अब पता नहीं ये क्या निशान ले आए। इनके बारे में मैं एक कहावत सुनाता हूं। स्कूल में एक बच्चा गया तो साथ वाले बच्चों ने उससे पूछा कि तुम्हारा गोत नात क्या है बच्चे ने कहा कि भाई पहले थे हम दीन जुलाहे फिर हो गये दर्जी, आजकल राजपूत के घरों के मालिक बाकी मां की मर्जी। स्पीकर सर, यह जो मामला है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, ये किसानों की बातें क्यों नहीं करते। क्योंकि यह बहुत ही सीरियस मामला है। इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिएं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, कप्तान साहब को टिकट तो कांग्रेस ने नहीं दिया और गुस्सा ये हमारे ऊपर झाड़ रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है और क्या बात चल रही है। स्पीकर सर, कितनी बड़ी अनैतिकता है कि दूसरे जिले के किसानों को लाकर ये भड़काते हैं। किसानों को मरवाना, किसी के घर जलवाना या एक ही थाली में साथ खाना खाकर उसकी जान लेना चौटाला साहब का इतिहास है। मंडियाली में जो आन्दोलन हुआ तो इससे ज्यादा बड़ी अनैतिकता और नहीं हो सकती। सर, अगर हरियाणा विकास पार्टी या हमारी पार्टी का कोई जिम्मेदार आदमी, कोई चुनाव लड़ा हुआ आदमी, कोई हमारा जिले का पदाधिकारी जिस आन्दोलन को करता है हम उसको ओन करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। उस उम्मीदवार को भिवानी जिले में किसी ने घुसने नहीं दिया। वे अपने गांव झोंझू में जा नहीं सकते। इन्होंने राजस्थान की सीमा पर भोले-भाले किसानों को भड़काया इसलिए उनको मरवाने कि जिम्मेदारी भी इनको स्वीकार करनी चाहिए। (विघ्न) ये 16 फरवरी की बात करते हैं तो पिछली बार भी इनका खाता नहीं खुला और इस बार भी खाता इनका नहीं खुलने देंगे। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है या रामबिलास शर्मा जी को समय दिया है।

श्री अध्यक्ष : मेरी प्रार्थना है कि आप सभी कंट्रोवर्सी से बचें। मेरी ट्रैजरी बैंचिज के लोगों से भी प्रार्थना है कि वे इंट्रप्ट न करें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

मुख्यमंत्री द्वारा

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। आदरणीय लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने कहा कि कैनाल रैस्ट हाउस में मेरे से किसान मिलने गए और मेरी उनकी बात नहीं हुई। हकीकत तो यह है कि किसान मैंने बुलाए थे और वे आए भी थे। दादरी रैस्ट हाउस में मेरी उनसे दो घंटे बात हुई। वे हर चीज मानकर गए थे। इसके बाद चौटाला जी की पार्टी के उम्मीदवार जिसका भाई रामबिलास जी जिक्र कर रहे थे ने, दो तीन दिन बाद फिर उनको गुमराह किया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विशेष रूप से आपसे एक अनुरोध करूंगा कि किसी को भी अपनी बात कहने से पहले आपको मुखातिब होकर बात करनी चाहिए। अगर आप दूसरों को छूट दें और हमें यह कहें कि आपको सीमा में रहना चाहिए तो हम तो सीमा में ही रहेंगे लेकिन यह कायदा सब पर ही लागू हो तो यह ज्यादा बढ़िया बात रहेगी। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं रामबिलास शर्मा की कही हुई बातों पर पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। इन्होंने हम पर दल बदल को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये शायद उत्तर प्रदेश को भूल गए और शायद इनको वहां के हालात का ज्ञान नहीं रहा हो और शायद इनको संविधान के दसवें शिड्यूल के बी० जे० पी० द्वारा किए गए उल्लंघन का भी ज्ञान न रहा हो। शायद ऐंटी डिफैक्शन बिल को पांव तले न रौंद पाए हों और कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो सारे देश ने टैलीविजन पर देखा सुना होगा कि इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने लोकसभा भंग होने के समय पर यह कहा था कि हमने कांग्रेस के 40 एम०पी० तो तोड़ लिए थे, 7 और तोड़ लेते तो सरकार बना लेते। इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब कितनी गलत बयान बाजी कर रहे हैं। 40 कांग्रेस के मैंबर पार्लियामैंट आना चाहते थे, हमने स्वीकार नहीं किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने त्याग-पत्र दिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो लोग चौराहे पर नंगे खड़े हों वे दूसरों को सबक सिखाते हैं। राम बिलास जी मैं आपकी ऐनर्जी अभी समाप्त नहीं करवाना चाहूंगा अभी तो मैंने ट्रांसपोर्ट विभाग तक की ही बात कही है और अब सिंचाई विभाग की चर्चा चल रही थी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी आंकड़े हैं और आंकड़ों के मुताबिक हमारी सरकार के वक्त में बिजली सस्ती मिलती थी और बिजली 24 घंटे मिलती थी। अध्यक्ष महोदय, जिन दक्षिणी हरियाणा के लोगों का अभी जिक्र आया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन दक्षिणी हरियाणा के लोगों को मैंने बुलाया और उनकी बात सुनी। चौधरी बंसी लाल जी ने चुनाव से पहले चौथी स्लैब प्रणाली की बात लोगों में जाकर कही और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक समान बिजली का सारे प्रदेश में एक सिलसिला शुरू कर दिया। जिनको 12 रुपये हार्स पावर के हिसाब से बिजली मिलती थी उन्होंने शत-प्रतिशत वोट बंसीलाल जी की पार्टी के उम्मीदवार, उस क्षेत्र से चुने हुए बंसी लाल जी के दामाद की झोली में डालने का काम किया। उनको ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ 70 टयूबवैल के कनैक्शन बांटे थे और आपके मंत्री सैनी जी के मुताबिक 8 लाख 80 हजार रुपया उनकी तरफ बकाया था। अतर सिंह सैनी राज्य, मंत्री सिंचाई विभाग ने जो अपनी प्रैस कांफ्रैंस में ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक सारी स्टेट में 400 करोड़ रुपये से अधिक हरियाणा प्रदेश के लोगों की तरफ हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का बकाया है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर क्लेरीफिकेशन देना जरूरी है। वह फिगर 8 लाख 80 हजार नहीं बल्कि 33 करोड़ रुपये और 22 करोड़ रुपये के दो आंकड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि हाउस अब भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। 70 ट्यूबवैल्ज़ के जिन लोगों की तरफ बिजली के बिल बकाया हैं उनके जिम्मे अत्तर सिंह सैनी के ब्यान के मुताबिक 8 लाख 80 हजार रुपये बकाया है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जो अब कह रहा हूं वह फिगर सही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : तो फिर आप अपने सिंचाई मंत्री से कहें कि गलत फिगर न दें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि झगड़ा तो करते हैं ट्यूबवैल के रेट का और डौमैस्टिक कनैक्शन के बिल भी पांच साल से नहीं दिये हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लोग ट्रांसफार्मर ठीक कराने की मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी सारे देश के स्तर पर प्रचारित करते हैं कि हम बिजली पानी मुफ्त नहीं दे सकते जबकि उन किसानों की डिमांड कतई बिजली पानी मुफ्त मांगने की नहीं है। देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मांगने वाला उसके सामने हाथ फैलाता है जो दे सके, उन लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते जो लोगों के खून से हाथ रंगना जानते हों और वह भी ऐसे लोगों का खून जिन्होंने इनको अपना सब कुछ दिया, शत-प्रतिशत वोट दिए और जिनकी बदौलत आज ये सत्ता में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोस्त जिन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम बिजली आब्याने के रेट पर देंगे। राम बिलास शर्मा जी उन मासूम लोगों के खून से आपके भी हाथ रंगे हुए हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, अब ये ड्रामेटाइज कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी तो प्राथमिक इनकी है। राजस्थान के बार्डर पर कौन सा आन्दोलन होता है। यह बात मैंने पहले भी इस महान सदन के सामने तारीख बाईज रखने की कोशिश की है। यह कोई किसानों का आन्दोलन नहीं था। श्री ओमप्रकाश चौटाला जी को चौधरी बंसीलाल जी की सरकार हज्म नहीं हो रही है। इनका अपना उम्मीदवार चुनावों में हार गया और उसको कुबध करने के लिए कोई धँधा चाहिए था। हरियाणा के किसी गांव की चौपाल में, किसी शहर में और किसी एस०डी०एम० के कार्यालय के सामने इनको किसी ने बैठने तक नहीं दिया तो राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर इन्होंने गांवों के किसानों को भड़काया और यह आन्दोलन करवाया। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी वहां पर कई बार गये। स्पीकर सर, जो चार किसान मारे गये हैं वे पुलिस ने अपने बचाव में जो गोली चलाई उस दौरान मारे गये और वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई। उन किसानों के मारे जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अफसोस है, इस सदन को अफसोस है। परन्तु उन किसानों के मारे जाने की प्राथमिक जिम्मेवारी चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी को स्वीकार करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी आप बोलिये।

श्री सत पाल सांगवान : सर, लीडर ऑफ दि ओपोजीशन हाउस को टोटली गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें (विघ्न)

श्री सत पाल सांगवान : स्पीकर सर, सच्चाई क्या है वह मुझे मालूम है क्योंकि वह मेरा एरिया है ये तो राजनीतिक बातें करते हैं। सच्चाई सुनने की इनमें हिम्मत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपको अपनी बात कहने का मौका देंगे।

श्री सत पाल सांगवान : स्पीकर सर, ये खूनी हमें बताते हैं, वास्तव में खूनी तो ये ही हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी आपको जब मौका दें तब अपनी बात कहना। आपको मौका जरूर देंगे।

श्री नृपेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, लीडर ऑफ दि ओपीजीशन ने जो विवाद खड़ा कर दिया है और ये बता रहे थे कि वह संघर्ष तो संघर्ष समिति ने किया था। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस संघर्ष समिति के प्रधान जो कि इनकी पार्टी के उम्मीदवार विधान सभा चुनावों में मेरे से 27 हजार वोटों से पराजित हो गये थे। इसी हार का बदला लेने के लिए संघर्ष समिति के नेता जो इनकी पार्टी का उम्मीदवार था, ने हमारे जिले से बाहर जाकर महेन्द्रगढ़ के उस गांव में स्टेज लगाकर इस आन्दोलन में मारे गये लोगों को राहत देने के नाम पर लोगों को बहलाकर उसने 30 लाख रूपया इकट्ठा किया। आप तो आठ लाख रुपए की बात करते हैं। इनकी पार्टी के 1996 के चुनावों के उस *उम्मीदवार ने उन 30 लाख रुपयों में से दस लाख रुपये तो मरने वालों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांट दिये। बाकी रुपया चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ही बताएं कि वह इनकी पार्टी के कोष में है या इनकी पार्टी के 1996 के चुनावों के उम्मीदवार की जेब में है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह है कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं हो और उसके प्रति अनर्गल इल्जामात लगाए जाएं और वह सदन की कार्यवाही में छपते रहें, इसके लिए तो आपको स्वयं ही नोटिस ले लेना चाहिए। अब ये तो बोले जा रहे हैं क्योंकि इनकी लंबी-लंबी जुबानें हैं। वह आदमी यहां पर आकर अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकता है। क्या आप रवीन्द्र सांगवान से संबंधित अल्फाज़ सदन की कार्यवाही से निकलवाने की कृपा करेंगे ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : जहां पर रवीन्द्र सांगवान नाम लिखा है, उसकी जगह इनकी पार्टी का 1996 के चुनावों का उम्मीदवार कर दिया जाए। (शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उनका नाम चाहे डिलीट कर दें लेकिन जो व्यक्ति किसान संघर्ष समिति का लीडर बना हुआ है और पिछले 1996 के चुनावों में जो ओम प्रकाश चौटाला जी का पार्टी का उम्मीदवार था, उसको श्री नृपेन्द्र सिंह जी ने 27000 हजार वोटों से हराया। यह बात किसानों के संघर्ष की नहीं है। अगर किसानों के संघर्ष की बात होती तो वहां पर किसान ही होते। भाई रामबिलास का 25 कि०मी० दूर जाकर घर नहीं जलाया जाता, उनकी बूढ़ी माता जी को घसीटकर नहीं ले जाया जाता। अध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन नहीं था, यह तो आग लगाने का एक तरीका था जिसको ये ही लोग कर सकते हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट के समय भी इन्होंने पेड़ कटवाए थे, अब भी पेड़ कटवाए गए। उस वक्त बसें जलवाई गई थीं, अब भी बसें जलवाई गईं। उस वक्त रेलवे स्टेशन जलवाए गए थे, अब भी रेलवे स्टेशन जलवाए गए। उस समय जो "मोडस-ऑपिन्डी" अपनाई गई थी, बिल्कुल आज भी इन्होंने उसको अपनाया है। उसके जन्मदाता ये ही लोग हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे तो मुझे और आराम मिल जाएगा तथा नया इशू भी मिल जाएगा। मैं जितना समय ले रहा हूं, वह नोट करता जा रहा हूं। लेकिन इससे सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, श्री रामबिलास शर्मा जी ने चुनावों के वक्त अपने चुनाव-घोषणा पत्र में कहा था कि आवियाना के रेट पर बिजली देंगे। अब जबकि ये

*Substituted as ordered by the Chair.

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
सरकार में हैं, बिजली देने की बात तो दूर रही, ट्रांसफार्मर ठीक करने की बात को लेकर जब जनतांत्रिक तरीके से लोग आन्दोलन पर बैठे तो उनको गोलियों से भून दिया गया। यह कोई जनतांत्रिक परिभाषा नहीं है। आखिर हम लोगों को जनता के बीच में जाना है और जिस मुद्दे को यहां पर उछाला जा रहा है जिसको श्री नृपेन्द्र सिंह जी ने मूव किया, उस सारी बात की मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल संवेदना व्यक्त करते समय मैंने किसी दिवंगत स्पीकर महोदय का जिक्र कर दिया तो मुझे काफी चीखों और शोरगुल का सामना करना पड़ा कि मैं चेयर की बेईज्जती कर रहा हूं। भाई नृपेन्द्र सिंह जी ने प्रोफैसर का उदाहरण देते हुए कहा कि कुनबा डूबेगा, अब कुनबा डूबेगा, तो प्रोफैसर का डूबेगा जो इनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब कल इन्होंने कहा था कि स्पीकर भी कभी मरेंगे तो हम ने कहा था कि ऐसे मुख्यमंत्रियों का क्या होगा जिन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए प्रदेश के अंदर हत्याएं करवा दी हों। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बिजली हमारे वक्त में बहुत मिलती थी, सस्ती मिलती थी और 24 घंटे मिलती थी, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। (विघ्न)

Mr. Speaker : Dr. Virender Pal you are nobody to guide me. Please take your seat. (Interruptions). Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरी सबमिशन यह है कि हम किस के द्वारा बात करें। स्पीकर सर, हम आपको मुखातिब करके कोई बात कहना चाहते हैं। मेरी पार्टी का कोई सदस्य कानून कायदे की उल्लंघना करने में यकीन नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, आप इनको सम्भालने में असमर्थ हैं। आपकी मजबूरी को ध्यान में रख कर मैं कह रहा हूं कि इनको इकट्ठे एक ही बार समय दे दें। मैं सबका एक ही बार में सत्या नाश कर दूंगा। (शोर)

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी सत्यानाश के लिए जाने जाते हैं। श्री सीता राम केसरी और नरसिम्हा राव के लिए महात्मा गांधी जी भी ऊपर माला लिए तैयार बैठे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को तोड़ दो। नेहरू जी, पटेल आदि कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ सके। ओम प्रकाश ने जो सत्या नाश की बात कही है वह सही है क्योंकि देवीलाल जी ने जो तप किया था वे उसका सत्या नाश करेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बिजली के उत्पादन का मुख्यमंत्री जी बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं आज बिजली के उत्पादन में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह स्थिति रही है कि 1993-94 में 832 करोड़ 61 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई और सरकार के खजाने में 693 करोड़ 8 लाख रुपया आया था। 1994-95 में 821 करोड़ 25 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई थी और सरकार के पास 905 करोड़ रुपया आया था। 1995-96 में 864 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई और सरकार के खजाने में 1147 करोड़ 30 लाख रुपया आया। अध्यक्ष महोदय, 1996-97 में 914 करोड़ 40 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई और सरकार के खजाने में 1220 करोड़ 70 लाख रुपया आया। 1997-98 में 933 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार 18 करोड़ यूनिट बिजली बढ़ी है। आप अन्दाजा लगा लें कि 18 करोड़ यूनिट बिजली बढ़ी और रेवेन्यू 603 करोड़ रुपया बढ़ गया। पिछले सदन में भी कहा गया था कि

हम बहुत सस्ती बिजली देते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए नृपेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इस सरकार की बिजली के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़ी सस्ती बिजली दी जा रही है। इन्होंने यह भी कहा कि बड़े फख्र और गर्व की बात है कि बिजली के लिए वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये कर्जा लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में किसानों को सबसिडी देने का जब जिक्र आया था तब ये बोले कि हम सबसिडी समाप्त नहीं करेंगे। यह बात रिकार्ड में दर्ज है। किसानों को सबसिडी देने की बजाय अब इन्होंने एक नई चिट्ठी वर्ल्ड बैंक को लिखी है। यहां हाउस में सिंचाई तथा पावर सैक्रेटरी श्री एस०वाई० कुरैशी बैठे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक को जो नई चिट्ठी भेजी है वह चिट्ठी सरकारी रिकार्ड में दर्ज है। उस चिट्ठी के मुताबिक किसानों के ऊपर बिजली का रेट 200 प्रतिशत और पता नहीं कितने प्रतिशत पड़ेगा और उस रेट को इन्होंने हर साल बढ़ाने का वर्ल्ड बैंक से वायदा किया है तब जा कर इनको वर्ल्ड बैंक से यह लोन-सैंक्शन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 1998 में वर्ल्ड बैंक को इन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें डोमैस्टिक बिजली 15 प्रतिशत जाएगी, एग्रीकल्चर सैक्टर में कोई रियायत नहीं है इन्डस्ट्रीज में 15 प्रतिशत जाएगा। इंस्टीच्यूशन बल्क सप्लाई के लिए लाइटिंग 15 प्रतिशत इसी रेशो से 1998 में 228, 1999 में 264, 2000 में 290, 2001 में 319, 2002 में 345, 2003 में 349, 2004 में 361 है। इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां आज 55 प्रतिशत के हिसाब से बिजली मिलती है वह इस एग्रीमैंट के मुताबिक उनको 191 प्रतिशत फालतू पैसा देना पड़ेगा। ये यह एग्रीमेंट करके आए हैं। (शेम शेम की आवाजें) अध्यक्ष महोदय, यह लैटर एस०वाई० कुरैशी ने वर्ल्ड बैंक को लिखा है। वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमैंट करने के लिए जो टीम गई थी उस टीम में चीफ सैक्रेटरी गए थे इस बारे में मुख्य मंत्री जी हमें बताएं कि उस टीम में चीफ सैक्रेटरी किस कैटेगरी में गए थे। वर्ल्ड बैंक के लोगों ने कहा था कि चीफ सैक्रेटरी नहीं आएगा। उसके बाद क्या किया गया कि इन्होंने चीफ सैक्रेटरी को चूंकि सैर करवानी थी इसलिए और लोगों की बजाय उनको टैक्नीकल एडवाइजर के नाम पर वहां भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, जनता के पैसे को कैसे बेदर्दी के साथ बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में पैसे की बहुत किल्लत है इसलिए सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड से पैसा लिया जा रहा है, हैफेड से पैसा लिया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों को सैर कराने के लिए विदेशों में बिना हैसियत के भेजा जा रहा है। इससे ज्यादा अजीब बात और क्या हो सकती है। शराबबंदी के घाटे को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक आई०ए०एस० अधिकारी को यूनिसेफ से पैसा लाने के लिए भेजा। उस अदायरे का काम केवल यह है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को खुराक दें। अध्यक्ष महोदय, यूनिसेफ की तरफ से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बिस्कुट आए थे उनको बहन कमला जी अकेली खा गई थी। (हंसी)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

स्थानीय शासन मन्त्री द्वारा

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : स्पीकर साहब मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूं। मुझे विपक्ष के नेता से यह उम्मीद थी कि वे किसी तथ्य के आधार पर अपनी बात करेंगे लेकिन इन्होंने बिना किसी तथ्य के आधार की बात कह दी। सरकार ने 9 करोड़ रुपये के बिस्कुट खरीदे थे। इन्होंने एक अखबार से पढ़कर यह कह दिया कि बिस्कुट की परचेज में 30 करोड़ रुपये का स्कैण्डल हुआ है। स्पीकर साहब हरियाणा सरकार ने केवल 9 करोड़ रुपये के बिस्कुट खरीदे थे। जब चौधरी बंसी लाल

[डॉ० कमला वर्मा]

जी मुख्य मंत्री बने तो मैंने पौष्टिक आहार परचेज करने का काम उस समय हाई पावर परचेज कमेटी को दे दिया था। पहले तो डिपार्टमैंट अपने आप ही परचेज कर लिया करते थे, सारे डिपार्टमैंट वाले अपने आप ही नियमानुसार खरीदोफरोखत किया करते थे। मैंने मुख्य मंत्री जी से सलाह करके, यह कहा कि यह लगभग 28 करोड़ की खरीद करनी पड़ती है इसलिए यह काम हाई पावर परचेज कमेटी को दे दिया जाए। यह भी देखा जाता है कि बिस्कुट की एनर्जी प्रोडक्शन कितनी है। प्रोटीन व कार्बो हाईड्रेट कितनी है यह सब देखने के बाद अन्य वस्तुओं के साथ एक दिन देने के लिए बिस्कुट भी खरीदे गये। जो हाई पावर परचेज कमेटी है उसमें आई०ए०एस० अधिकारी और मिनिस्टर होते हैं। सेठ सिरी किशन दास उसके चेयरमैन हैं और वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री आदि सारे सदस्य हैं। सारी कमेटी के सामने केस को देखा गया जिसका अधिकार बनता था या पूरे नियमों का पालन करते हुए, जिसको टेण्डर देना था उसको दिया। इसमें केवल डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं आती है। परचेज के आर्डर देने के बाद नीचे फील्ड में ए०डी०सी०, सी०डी०पी०ओ० और पी०ओ० यानि तीन आदमियों की कमेटी है और जब भी कोई सामान आता है बाकायदा उसको पूरा चैक किया जाता है। उसके वेट का, क्वालिटी और क्वांटिटी का पूरी चैकिंग कर के ही लिया गया है। उस वक्त 9 करोड़ रुपये के बिस्कुट खरीदे गए थे और वह यथावत क्षेत्र में समय पर बांटे गये। विरोधी पक्ष के नेता तथ्यों से परे कोई बात कहें, अच्छा नहीं लगता। चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार किसी भ्रष्टाचार या स्कैण्डल में शामिल नहीं हो सकती जैसे कि स्वयं विपक्ष के नेता हांगकांग से आते हुए घड़ियों समेत पकड़े गये थे। चौधरी बंसी लाल जी और बी०जे०पी० की सरकार के ऊपर आप ऐसा कोई दोषारोपण नहीं कर सकते क्योंकि यह सरकार कोई गलत काम ही नहीं कर रही है। मैंने उस वक्त भी कहा था और अब भी कह रही हूं कि सी०बी०आई० या सी०बी०आई० से ऊपर की कोई जांच ऐजेंसी केन्द्रीय सरकार की हो तो, वह इस की जांच कर लें। दामन हमारा सारा साफ है इसलिए मैं आपकी ऐसी गलत बातों से नहीं डरती।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कमला वर्मा जी तो वैसे ही तैश में आ गई। मैंने तो यूनिसेफ का जिक्र किया था कि यूनिसेफ गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल का काम करती है, उसके पास शराब बंदी का काम कहां से आ गया, यह मैं कहने जा रहा था। सरकार ने अपने अधिकारियों को मौज लुटाने के लिए विदेशों में भेजा था। जितनी भी प्रोटीन की गोलियां थी वह तो बहन जी अकेले ही डकार गई। (हंसी) मैं उस केस के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता जिसकी विजिलेंस इन्क्वायरी चल रही हो। आप अपनी सफाई उनके सामने देना। मैंने तो जो अखबारों में खबर पढ़ी थी उसका जिक्र किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहने जा रहा था कि बिजली के निजीकरण के नाम पर हरियाणा प्रदेश के किसानों की सारी सबसिडी खत्म करके उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सबसे मंहगी बिजली जो वर्ल्ड बैंक के एग्रीमैंट के हिसाब से मिलने जा रही है वह इस देश के उस किसान को मिलने जा रही है जो अपने खून पसीने से धरती को चीर कर अन्न पैदा करके सारे देश का भरण-पोषण करता है। जिस किसान ने अन्न पैदा करके देश के अन्न भण्डार भर दिये हैं और कटोरा लेकर हमारी सरकारें अनाज के लिए बाहर के मुल्कों में जाती थी उन्हें वहां जाने से बन्द कर दिया था जबकि अब यहां के मेहनती किसानों ने अपनी मेहनत से अन्न के भण्डार भर दिए हैं तो अब ये उनकी ही सुविधाएं वापस ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो यह बिजली के रेट की बात है इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि डोमैस्टिक बिजली 1 रुपये 92 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी लेकिन आज बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है और जिस दिन बिजली के निजीकरण पर दस्तखत हो जाएंगे तो 5 रुपये प्रति यूनिट से अधिक रेट पर मिलेगी। इसलिए बगैर किसी कायदे-कानून के सारे विपक्ष को सदन से निष्कासित करके सरकार ने जल्दबाजी में बिजली के उस अहम बिल को पास करने की कोशिश की जिसका परिणाम हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुआ। लेकिन यह सरकार इसे भी अपनी उपलब्धि गिनने लग रही है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के निजीकरण की बात को लेकर मैंने कहा था कि बिजली बोर्ड के बहुत से कर्मचारियों की छंटनी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा बल्कि बिजली बोर्ड के 132 इंजीनियर्ज ने सरकार को एक पत्र लिखकर भेजा है, उस पत्र की कापी मेरे पास है। उन इंजीनियर्ज ने कहा है कि सरकार जो यह कर रही है यह बहुत गलत बात है। इससे बहुत बड़ा नुक्सान होने का अन्देशा है लेकिन सरकार अपनी बात पर बजिद है। चूंकि इससे हजारों-करोड़ों रुपयों का घोटाला होना है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के नाम पर आज इस प्रकार का सिलसिला इन्होंने 16.00 बजे शुरू किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह उन इंजीनियर्ज का दस्तखतशुदा लैटर मेरे पास है जिन्होंने इस सरकार को इस मामले में कहा है कि यह आप गलती करने जा रहे हैं। इस सरकार ने किसी की भी बात मानने की कोशिश नहीं की और अपनी जिद को कायम रखने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। आज भी हालत यही है कि प्रदेश में बिजली नहीं है। इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद जिससे कि फसल को नुक्सान पहुंचा है और बहुत सी जमीन बिना बोये रह गई है, प्रदेश में बिजली नहीं मिल पा रही है। जब गेहूं को पानी की जरूरत होगी तो बिजली न होने के कारण किसानों में बड़ी भारी मायूसी होगी और पता नहीं उनका क्या हाल होगा। अध्यक्ष महोदय, उन 1700 कर्मचारियों का क्या होगा जो आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य मन्त्री जी आज भी उसी भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि आन्दोलन करके देखो और कभी कहते हैं कि चुनावों से निपट लूं तो उसके बाद देखूंगा। अध्यक्ष महोदय आज कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। 15-20 हजार कर्मचारी आज आन्दोलन करने पर मजबूर हैं। अखबारों में छपी तस्वीरों और खबरों के मुताबिक उन्होंने बड़ा भारी प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि हमारे हकों की हिफाजत की जाए। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों लागू करूंगा। प्रधान मन्त्री जी के साथ हुई मीटिंग में भी ये कह कर आए थे कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों मानूंगा लेकिन उसके बाद आज "इफ" और "बट" लगाने की क्या जरूरत है। उनके वेतन फिक्सेशन का तरीका क्या होगा, नये वेतनमान उनको कैसे मिलेंगे। कर्मचारी अपने ही पैसे को एक साल तक अपने खाते में से नहीं निकलवा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी के घर में कोई शादी है, किसी के घर मुण्डन संस्कार है, किसी के घर भात आ जाए और यदि किसी कर्मचारी को जरूरत पड़ेगी तो क्या वह कर्मचारी अपने ही पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। केवल ब्याज के लिए उस पैसे को रखे रहेगा और उसे अपना पैसा निकलवाने का अधिकार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, 1700 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों को हटा दिया जाए लेकिन पंजाब सरकार ने उनको सर्विस से नहीं निकाला। वैसा ही कोई रास्ता इस सरकार को भी तलाश करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह सरकार बदले की कार्यवाही के तहत ऐसे काम कर रही है। 16 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। अगर कर्मचारियों में इसी प्रकार से असंतोष बढ़ता गया और कर्मचारियों ने कोई कठोर निर्णय ले लिया तथा उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो ये सोच लें कि इनकी क्या हालत होगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। श्रीमान चौटाला साहब फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं। वे हमारी सरकार पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका हमारी सरकार से कोई वास्ता नहीं है। स्पीकर सर, यह कह रहे हैं कि बदले की कार्यवाही की गई है। इस सरकार ने पिछले करीब 18-19 महीनें के अपने शासनकाल में किसी के प्रति कोई बदले की कार्यवाही नहीं की है लेकिन ये सदन के नेता और हमारी सरकार के खिलाफ अनाप-शनाप आरोप लगाते रहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जीं अपने दिन भूल जाते हैं। पहले जब ये मुख्य मंत्री थे तो कहा करते थे कि रात को सोते हुए अगर आदमी इनकी सरकार का नाम सुन कर, दो करवटें ले कर खाट से नीचे न गिर पड़े तो फिर शासन किस बात का है, आज वही चौटाला साहब, हमारी सरकार पर बदले की भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। इनकी ऐसी आदत हो गई है। जो सरकार लोगों की भलाई के इतने कार्य कर रही है उसके बारे में इन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि अगर कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता रहा और अगर इस सरकार की तरफ से उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो 15-20 हज़ार कर्मचारी जो एजिटेशन कर रहे हैं उनकी संख्या और बढ़ जाएगी और वे अपना निर्णय सरकार के खिलाफ देंगे तो इनके लिए क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है, सरकार को इस बात का भी खासकर ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सरकार इस बारे में प्रभावी पग उठाए। अध्यक्ष महोदय, निर्मल सिंह जी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कह रहे थे कि सरकार ने किसान का गन्ने का रेट 2 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट तो बढ़ा दिया गया है लेकिन ढुलाई उतरवाई और ट्रांसपोर्ट के चार्जिज पहले मिल मालिकों को देने पड़ते थे लेकिन यह 10-12 रुपये क्विंटल का खर्च अब किसान से वसूल किया जाएगा और आज ये लोग किसान के भले की बात कर रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। चौटाला साहब, गलत ब्यानी कर रहे हैं। गन्ने की ढुलाई और भाड़े का आधा खर्च किसान देगा और आधा खर्च मिल मालिक देगा। चौधरी बंसी लाल के राज में किसानों को पूरा महत्व दिया गया है। इनको अपना वक्त याद नहीं रहा जब किसानों को अपने खेतों में ही गन्ना जलाना पड़ा था। जितना भाव गन्ने का हमने दिया है उतना भाव कहीं भी देश के किसी राज्य में नहीं है। यू०पी० और पंजाब सरकार से ज्यादा रेट हमने गन्ने का दिया है। हमने पिछली दफा भी हाउस में यह बात कही थी। चौटाला साहब यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो किसानों को खेतों में अपना गन्ना जलाना पड़ा था और आज ये किसानों के हित की बात कहने का ढोंग करते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल की सरकार के वक्त गन्ने के दाम 22 रुपये से बढ़ाकर 44 रुपये कर दिये गए थे। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले हविपा और भाजपा की गठबन्धन की सरकार ने इस प्रदेश के लोगों से बहुत से वायदे किए थे। विशेष रूप से पढ़ने वाले युवकों को कभी गैस ऐजैंसिया, कभी पैट्रोल पम्प, कभी नौकरियां या कभी बसों के परमिट देने की बात कही थी। चौधरी बंसी लाल जी पीटर रेहड़े वाले को भी परमिट देने की बात कर रहे थे जिस पर हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया था कि ये सड़क पर चलने लायक नहीं है। उन पीटर रेहड़े वालों को ये कहते थे कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, गैस की ऐजैंसी देने का सवाल आया तो वह अपने भाई को दे दी। पैट्रोल पम्प का सवाल आया तो वह भी अपने भतीजे को दे दिया। अध्यक्ष महोदय, बसों के परमिट की लिस्ट मेरे पास है। राम विलास जी खासा गुस्से में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और

राजस्थान की सरकारों का कुछ रूट परमिट का फैसला हुआ है। उसमें से जो हरियाणा के हिस्से में परमिट आए थे उन परमिटों में से हो सकता है रामबिलास जी बता दें। मैं कोई भाई वाज तो हूं नहीं लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की है। कुर्सीनामा बता रहा हूं अगर मैं कहीं कोई गलती कर जाऊं तो मुझे याद करवा देना, तनाव में मत आना। राम बिलास जी मैं आपके गुस्से को बर्दास्त नहीं कर सकता क्योंकि ब्राहमण का गुस्सा पता नहीं क्या कर दे। अध्यक्ष महोदय, एक मै० कृष्णा मोटर्ज सर्विसिज के नाम से परमिट है जिसका एड्रैस इस प्रकार से है "बी-147/ए, मंगल मार्ग, बापु नगर, जयपुर। यह पिलानी से चण्डीगढ़ की बसें हैं इस रूट का परमिट चौधरी रघुबीर सिंह को मिला है। चौधरी रघुबीर सिंह, चौधरी बंसी लाल जी का भाई है जो कि आज मुख्यमंत्री हैं, उनके बाप का नाम चौधरी मोर सिंह है। इसके बाद चौधरी धर्मबीर सिंह, सन आफ श्री कर्म सिंह, 4/3 नव जीवन कम्पलैक्स, जयपुर है। इनकी बसों का परमिट भी पिलानी से चण्डीगढ़ का है जोकि चौधरी रघुबीर सिंह का रिशतेदार है। इसके अलावा जो मै० कृष्णा मोटर्ज सर्विसिज है इसका एड्रैस बी-147/ए, मंगल मार्ग, बापु नगर, जयपुर है, जिनकी बसें झुंझनु से दिल्ली चलती हैं। इस कम्पनी के प्रोपराईटर चौधरी रघुबीर सिंह जी हैं। इसी प्रकार इन्हीं का एक और परमिट कोटपुतली से हिसार का है। इसके अलावा रोशन लाल, सन आफ श्री जय राम, रैजीडैंट आफ बारी कचानी है, उन्हें भी तीजाला का परमिट मिला। यह परमिट होल्डर जो है यह राम बिलास शर्मा जी का सगा भाई है। यह है या नहीं है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अगर है तो यह राम बिलास जी बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मेरे पास 16 ऐड्रैसिज हैं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

शिक्षा मंत्री द्वारा

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वांयट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुखी हो रहे हैं इसलिए मैं इनको सारी बात बता देता हूं। ओम प्रकाश जी ने किसानों के आन्दोलन से अपनी बात शुरू की और उसके बारे में हमारे सामने एक तथ्यपूर्ण बात रख दी। (विघ्न) अकेले ओम प्रकाश चौटाला जी कभी बहन जी पर, कभी किसी पर कीचड़ उछालते रहते हैं यह तो इनका स्वभाव है। जब इनके पास कोई तर्क नहीं होता है, कोई फैक्टस नहीं होते हैं तो ये ऐसी बातें करते हैं। यह किसान आन्दोलन से चले थे, वह आन्दोलन मेरे पड़ौस में भूपेन्द्र सिंह के हल्के में इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने शुरू किया था अब इनमें इतना साहस नहीं है कि ये उसको औन कर सकें। अब ये छींटाकशी पर आ गए हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने अभी कोई प्राईवेटाईजेशन नहीं किया है। राजस्थान में 60 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट प्राइवेट है। चौधरी रघुबीर सिंह 30 साल से ट्रांसपोर्टर हैं, मेरे भाई 13-14 साल से ट्रांसपोर्टर हैं और मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि जो परमिट दिए जाते हैं वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर दिए जाते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, रोशन लाल मेरा सगा भाई है। स्पीकर साहब, मैं आपको बताता हूं कि पिछले 13 सालों से मेरा छोटा भाई ट्रांसपोर्टर का काम करता है। राजस्थान में 60 परसैंट प्राईवेटाजेशन है और हरियाणा सरकार ने न तो चौधरी रघुबीर सिंह के साथ और न ही मेरे छोटे भाई के साथ कोई रियायत की है। चौटाला साहब की गैर कानूनी तरीके से नौहर से दिल्ली तक बस चलती है इसके अलावा इनकी 18 और भी बसिज चलती थीं। ये बसिज बगैर किसी काउंटर सिगनेचर के गैर कानूनी ढंग से चलती थीं। ये इस बारे में कोर्ट में भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पिछले 6 महीने से एक अभर्गल प्रचार भी कर रहे हैं लेकिन हम इस तरह से नहीं करते हैं। धंधा करके खाना कोई जुर्म नहीं है। 13 साल से मेरा भाई जो कि एल०एल०बी ग्रेज्यूएट है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है और राजस्थान का उसका परमिट है। हरियाणा सरकार ने किसी को भी कोई

[श्री राम बिलास शर्मा]

रियायत नहीं दी है। हम चौटाला साहब की तरह से नहीं है कि डिजनीलैंड के नाम से जमीन ऐक्वायर कर ली और फिर मनाली में होटल ले लिया। स्पीकर सर, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगवाया, माँ-बाप का अपहरण करवाया और घर जलवाया परन्तु उसके बाद भी ये कहने लगे कि यह इनका असली घर नहीं है बल्कि असली घर तो इनका जयपुर में था। मैंने कहा कि जिसको आप मेरा जयपुर में घर बताते हैं वह सारा आप ले लो और जो आपका पार्टी दफ्तर के लिए सौ कमरों का मनाली में होटल है उसमें से एक कमरा मुझे दे दो। इसके अलावा भूंतर में जो इनका बगीचा है उसके बारे में ये बता दें। स्पीकर सर, छाज बोले तो बोले छलनी भी बोले। मैं आमंत्रित करता हूं कि यदि काउंटर सिगनेचर के मामले में चौधरी बंसी लाल ने मेरे किसी परिवार के साथ या मेरे और किसी साथी के साथ कोई रियायत दी हो तो इसी सदन में हम त्याग पत्र दे देंगे।

श्री बंसी लाल : मैंने इस बारे में पूरा नोट तो अभी पढ़ा नहीं है लेकिन मैं साफ कहूंगा । अध्यक्ष महोदय, कोई दो साल पहले एक दिन मैं करनाल में ठहरा हुआ था। दस या साढ़े दस बजे हम करनाल में लेक पर खाना खाने जा रहे थे। उस समय एक बस वहां खड़ी थी और उस पर लिखा हुआ था विनोद बिशनोई। यह बस सफेद रंग की बहुत खूबसूरत थी और इस पर दो टेलीफोन नम्बर भी लिखे हुए थे और दोनों टेलीफोन नम्बर चौटाला साहब के मनाली के होटल के थे। अध्यक्ष महोदय, शायद आपके नोटिस में भी आया होगा यह बस अभय चौटाला के नाम से थी। एक आदमी दिल्ली से मंढाल बैठकर आया था उसने ही मुझे टिकट दी थी। वह बस बगैर किसी काउंटर सिगनेचर के चाहे कितने ही चक्कर मारे, चलती रहती थी। मैं और भी बातों का खुलासा करूंगा जब मैं यह नोट पढ़ लूंगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रामविलास जी ने बहुत लच्छेदार भाषा में अपना स्पष्टीकरण देने की बात कही। इनका भाई बहुत पुराना ट्रांसपोर्टर है इनके और भाईयों के नाम बताने के बजाए मैं बताना चाहूंगा कि उर्मिला देवी पुत्री श्री केलाराम निवासी खोड़वा जिसको तेजारा से दिल्ली तक का रूट परमिट मिला है। इसके परमिट होल्डर राजकुमार रीयल ब्रदर ऑफ रामविलास हैं। इनकी वाइफ को भी शायद अच्छा तजूर्बा ट्रांसपोर्ट चलाने का रहा होगा ? अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के कोटे में जो 79 परमिट आने थे उनमें से ज्यादातर इन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही दे दिए। जिन युवकों से कहकर इन्होंने वोट लिये थे कि हम आपको बसिज के परमिट दे देंगे और आप मौज लूटोगे, उसके बजाए इन्होंने ये परमिट किसी और को ही दे दिए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम आज भी कहते हैं कि हम उनको परमिट देंगे। हम तो इस बारे में ऐडवरटाइजमैंट करने जा रहे थे लेकिन इलैक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी। इलैक्शन के बाद हम उन लड़कों की कोओपरेटिव सोसायटी बनाकर अनइम्पलायड यूथ को करीब 450 रूट्स परमिट देंगे। हम आज भी इस बात पर कायम हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : वे इलैक्शन में आपकी अपनी ही सोसायटी बना देंगे क्योंकि वे आपको अच्छी तरह से जान गए हैं।

श्री बंसी लाल : हम भी बता देंगे कि आपकी सोसायटी बनेगी या हमारी बनेगी। अध्यक्ष महोदय, ये तीनों बार मिलाकर 6-7 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे लेकिन हर बार इनको यह कुर्सी फट खा जाती है। एक बार तो इनको इस कुर्सी पर पहुंचने भी नहीं दिया गया। दिल्ली में ही ओथ दिलायी और दिल्ली में ही इस्तीफा मांग लिया तो ये ऐसे भले आदमी हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी कोई परमिट दिया गया है मिलना भी चाहिए क्योंकि जब राम बिलास को, चौधरी बंसी लाल जी के भाई को और राम बिलास जी की भाभी को मिल सकता है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का भी अधिकार है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, राम चन्द्र मटौरिया श्री ओम प्रकाश चौटाला के समधी हैं, राजस्थान में उनकी कितनी बसें चलती हैं ये यह भी बताएं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मेरा समधी राजस्थान में बहुत पुराना ट्रांसपोर्टर है व राजस्थान में बसें चलाता है और परमिट से चलाता है, टिकट काटकर चलाता है जबकि बंसी लाल जी के भाई के लिए प्रशासनिक अधिकारी बिना टिकट के बसें भरवाते हैं बिना टिकट के बसें चलती हैं बिना काऊंटर सिगनेचर के चलती हैं। (शोर एवं विघ्न) पकड़े जाने पर चालान भी हुए हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में और भजन लाल की सरकार में दिन में 3-3 चालान होते थे। मेरे टाइम में मैंने इनकी बसों के साथ ऐसा नहीं किया।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

परिवहन मन्त्री द्वारा

परिवहन मन्त्री (श्री कृष्ण पाल गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। चौटाला साहब ने बस परमिटों के बारे में सदन को गुमराह किया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहली बात तो यह परमिट हरियाणा सरकार ने नहीं दिए, राजस्थान सरकार ने दिए हैं। 1968, 1971, 1975 और 1986 में और अब राजस्थान के साथ समय समय पर समझौता होता रहा है परन्तु 1968 से आज तक कोई लीगल समझौता दोनों के बीच में नहीं हुआ, फाइनल नोटीफिकेशन नहीं हुई। पहली बार प्रौपर लीगल समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच में किया गया है। तीस हजार किलोमीटर हरियाणा को राजस्थान में और इतना ही राजस्थान को हरियाणा में बसें चलाने की छूट थी लेकिन बाद में आबादी बढ़ी तो उसके बाद इललीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। हरियाणा में प्राइवेट परमिट नहीं दिये जाते। हरियाणा में सरकारी बसें हैं उसके बदले में राजस्थान रोडवेज की बसें चलती हैं। चौटाला साहब आप यह भी बताएं कि आपके समधी के नाम से नौहर से सिरसा के बीच मटौरिया बस सर्विस के नाम से कितनी बसें चलती हैं, अभय चौटाला के नाम से बसें चलती हैं और उसने सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान गवर्नमैंट को नोटिस दिलवाया है उसके बारे में भी आप बताएं और जैसा राम बिलास शर्मा जी ने बताया कि मनाली में आपका पांच सितारा होटल कैसे बना। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्टस गवाह हैं जब आपकी सरकार थी तो एक अधिकारी हुआ करता था वह आपके नाम पर फरीदाबाद के उद्योगपतियों से एक परसैंट मांगा करता था आज उस अधिकारी ने गेरूए वस्त्र धारण कर लिए हैं और वह दिन भी आने वाला है जब आप भी गेरुएं वस्त्र पहनेंगे। स्पीकर साहब, मैं इस सदन के सामने दावा कर सकता हूं कि जो रूट परमिट की बात है हरियाणा सरकार की तरफ से या ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से काउंटर साईन करने के बारे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इस बारे में आप किसी भी एजैंसी से जांच करा लें अगर कोई कोताही होगी तो हम जिम्मेवारी भुगतने के लिए तैयार हैं। चौटाला साहब आप यह आरोप बार बार लगाते हैं परन्तु हरियाणा की जनता अब समझ गई है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है इस बारे में पता लग जायेगा। मनाली के होटल की बात (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये कौन से परमिट की बात कह रहे हैं ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : तुम्हारी भी लम्बी चौड़ी लिस्ट हमारे पास है कि चौधरी भजन लाल जी के रिश्ते में भाई पोकरमल जी की बसें चलती थीं। इन सब बसों के नम्बर और रिकार्ड मेरे पास हैं। तुम्हारी तो सबसे बड़ी लिस्ट है। वह सदस्य तो दुनिया से चले गये। वे तो डबल टैक्स पेड पर काउंटर साईन करवाते थे और गाड़ी चलाते थे। ऐसे भी विधायक कांग्रेस में रहे हैं जो डबल टैक्स पर दबाव में काउंटर साईन करवाते थे। वे सिरसा से नई दिल्ली बसों को बगैर परमिट के और बगैर काउंटर साईन के चलाया करते थे। इस सरकार ने दबाव में आकर कोई काउंटर साईन नहीं किया। (विघ्न) उनके समय में एक नहीं कई परमिट दिये गये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठिये।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो वैसे ही गुस्से में आ गये, मैंने तो इनके परमिट का हवाला देना ही नहीं था पर क्या करूं इनकी लिस्ट आ गई और इनका नाम आ गया। हमने तो सभी परमिट लीगली दिए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव तो यह था कि अगर परमिट देने ही थे तो बेरोजगार युवकों को देने चाहिए थे, खैर उनको नहीं दिये गये औरों को दे दे दिए उनकी भी बेरोजगारी दूर हो गई इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। लीडर ऑफ दी अपोजीशन सदन को गुमराह कर रहे हैं। परमिट हमने नहीं दिए। ये परमिट राजस्थान गवर्नमैंट ने समझौते के आधार पर दिये हैं हमारी सरकार ने परमिट किसी को नहीं दिये। हमारी किसी व्यक्ति विशेष को परमिट देने की कोई आस्था नहीं है, Not a single permit to any individual has been given by us. These permits were issued by the Rajasthan Government on the recommendations of Rajasthan Government within the agreement. The Rajasthan Government recommended them and we gave them counter signatures. राजस्थान में जो हमारी गाड़ियां चलती हैं वे सब हरियाणा रोड़वेज की गाड़ियां चलाई जाती हैं। कोई प्राईवेट गाड़ियां नहीं चलाई जाती हैं। ये सदन को गुमराह कर रहे है। इन्होंने गुमराह करने का ठेका ले रखा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो इनकी ठीक है कि राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और दूसरी रियासतों के हिसाब से, सड़क के फासले के हिसाब से कुछ परमिटों का एग्रीमैंट होता है और उसमें से जब पूरे राष्ट्रीयकरण की प्रथा यहां थी तो स्टेट गवर्नमैंट की जिम्मेवारी होती थी कि वह स्वयं हरियाणा रोड़वेज के खाते से परमिट देते। सरकार की सहमति से सरकार के बताये हुए लोगों को परमिट दिये गये और काउंटर साईन हरियाणा सरकार ने किये। यहां तक तो मैं मान लूंगा यह ठीक था लेकिन क्या उन बसों में दारू ढोने के लिए तो छूट नहीं दी गई थी। आज गुड़गांव के थाने में ..... (विघ्न)

श्री बंसी लाल : जिस भी व्हीकल में शराब आती है हम उसको इंपाउंड करते हैं किसी को नहीं छोड़ते। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। अगर शराब आती होगी तो ये अपनी गाड़ी में लाते होंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की परमिट वाली गाड़ी आज भी गुड़गांवा के थाने में इंपाउंड है।(विघ्न) मैंने यह बात पहले भी कही थी।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, इससे साबित होता है कि सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है। चाहे वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की ही गाड़ी क्यों न हो वह भी थाने में बन्द हो सकती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह बस मेरे भाई के नाम थी जिसका कि लीगल परमिट था। (शोर) स्टेट कैरेज में कोई 55-60 सवारियां सफर कर रही होती हैं, उन में से कोई यात्री सूटकेस या बैग लेकर यात्रा करता है। उन में शराब वगैरह की स्मगलिंग की जहां तक बात है, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि स्मगलिंग ऐसे नहीं हुआ करती है। स्मगलिंग तो चौटाला साहब और इनके समधी जी करवा रहे हैं। ये ठेकेदार बने हुए हैं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर बहुत ही भले आदमी हैं। इन्होंने बड़ी फ्राखदिली से तस्लीम तो किया। हरियाणा सरकार इस मामले में सराहना के योग्य है कि इन्होंने रियायत किसी के साथ नहीं की है।अगर यह बात है तो फिर श्री राम सरूप राणा जी के साथ रियायत क्यों की गई ? एक मिनिस्टर की गाड़ी में अफीम पकड़ी गई और एक एम०एल०ए० हसनपुर क्षेत्र से हैं उनके भाई को उनकी पार्टी के अध्यक्ष की मौजूदगी में इनकी गाड़ी से दारू पकड़ी गई। (शोर) मैं इस प्रकार से इन पर लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के हौंसले का अनुसरण करें ताकि एक नई प्रथा कायम हो सके। अगर ये गलत काम कर भी दें तो ये लोग गांधी जी की तरह से पश्चाताप तो करें। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाएंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बात को ड्रामाटाईज किया है। मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर ने तस्लीम नहीं किया है। आज हरियाणा प्रदेश में व्हीकल्ज जब्त करने के प्रावधान को राष्ट्रपति महोदय ने सहमति दे दी है, उसके बाद हरियाणा रोडवेज की बे बसें भी थाने में खड़ी हैं जिन में शराब पकड़ी गई थी। इसी प्रकार से डी०टी०सी० की बसें भी थाने में खड़ी हैं और प्राईवेट ट्रांस्पोर्टर्ज की बसें भी थाने में खड़ी हैं। जिस प्रकार से इस बात को श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ड्रामाटाईज कर रहे हैं, वास्तव में बात यह नहीं है। हमारी सरकार ने शराबबंदी के मामले में पूरी सख्ती बरती है। (शोर)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

श्री जगदीश नायर द्वारा

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो मेरे भाई के ऊपर आरोप लगाया है, वह बिल्कुल गलत है। इनको तो गलत बात बोलने की आदत पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं कि कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके द्वारा शराब खरीदी व बेची जाती है। मैं उनके कागजात दिखा सकता हूं। अगर कोई इन में पढ़ा लिखा है तो कागजात देख सकता है। इसके साथ-साथ मैं यह बात जोर देकर कहता हूं कि अगर यह बात साफ हो जाए जो इन्होंने कही है तो या तो ये राजनीति से संन्यास ले लें अथवा मैं इस सदन को छोड़ देता हूं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर सर, करीब डेढ़ घंटा हो गया है चौटाला साहब जितना भी अनाप-शनाप कह सकते थे कह रहे हैं और डेढ़ घंटे से इस तरह का खेल चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि ये सारी बातें वह आदमी कह रहा है जो अपने गिरेबान

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

में झांककर नहीं देखता कि उसने अपने समय में क्या किया था। जब इनके पिता प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इनके अपने गांव चौटाला में इनके परिवार के लोग हरिजनों को डरा धमका कर उनकी जमीनें अपने नाम करवाते थे। इसी तरीके से इनके राज में इनकी पार्टी के लोगों ने मकानों के मुहूर्त करने बन्द कर दिये थे। इनको किसी मकान के मुहूर्त में जाना पड़ता था तो ये मकान देखकर कहते कि मकान बहुत अच्छा बना है और यह मकान मुझे दे दो। (शोर)

स्पीकर सर, प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव को प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सरकार बाहर भेजती है तो उन्हें क्यों एतराज होता है? ये अपना समय भूल गए हैं जब इनके भाई प्रताप सिंह जो एक्सपोर्ट कारपोरेशन के चेयरमैन थे, ने करोड़ों रुपये की चपेट सरकार को लगाई थी। इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर बूथ कैपचरिंग से लेकर राजनीति में अपराधीकरण इनके समय में हुए हैं। वे किसने करवाए थे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हैरानी तो यह है कि इनको इतनी छूट मिली हुई है कि जब मैं बोलने लगता हूं तो ये बीच में बोलने लग जाते हैं और इनका सारा समय आप मेरे खाते में गिन रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं उसका इससे ज्यादा क्या सबूत होगा कि मैं तथ्यों पर आधारित बात कह रहा हूं। श्री रामविलास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इनकी सराहना करता हूं। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया जिसमें किसी के साथ कोई रियायत नहीं की गई है। एक दिन मैं दिल्ली से चण्डीगढ़ आ रहा था। जब मैं स्टेशन पर गया तो किसी ने मुझे बताया कि आज शताब्दी ट्रेन नहीं आएगी। मैंने पूछा क्यों ? तो मुझे बताया गया कि आज शताब्दी ट्रेन में पानीपत के पास शराब पकड़ी गई और वह इम्पाउंड हो गई।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बातें बोल रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक दिन मुझे किसी काम से अहमदाबाद जाना था जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, वह कौन सी तारीख थी जिस दिन शताब्दी ट्रेन शराब पकड़े जाने के कारण इम्पाउंड हो गई थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वह तारीख बाकायदा मेरे पास दर्ज है। गुड़गांव थाने में जो रोडवेज की दो बसें खड़ी हैं उनमें से एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की है और दूसरी चौ० बंसी लाल के रिश्तेदार की है जो नारनौल में वकील हैं और उसका नाम जयपाल है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जयपाल मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या रघुबीर नाम का आपका कोई भाई नहीं है। रघुबीर का रिश्तेदार ही जयपाल है। रघुबीर बंसीलाल का भाई और मोर सिंह का बेटा है और उसका बेटा मटरू के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, इतना खुला कुर्सीनामा मेरे पास है फिर भी ये उलटे भाग रहे हैं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

मुख्य मंत्री द्वारा-

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। रघुबीर मेरा भाई है यह 16 आने सही है। जयपाल वकील जिसकी ये बात कर रहे हैं। वह हमारी पार्टी का 25-30 सालों से वर्कर है।

[श्री बंसी लाल]

मगर हमारी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर मेरे भाई की उससे रिश्तेदारी है तो मेरी रिश्तेदारी तो उससे अपने आप ही हो जाएगी। यह इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते कि इसका भाई प्रताप सिंह जब बाहर गया था तो कितना पैसा खर्च करके आया और एक्सपोर्ट कारपोरेशन के लिए आर्डर केवल 4 या 5 लाख रुपये का ही लाया। मैं इस बारे में सारा अपने जवाब में बताऊंगा । तब इनको पता लगेगा कि ये कहां खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का खतरा है कि जब मैं जवाब दूंगा तो ये भाग जाएंगे।

श्री राम विलास शर्मा : हम रिश्तों को डिसओन नहीं करते। हमारे लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। हम श्री ओम प्रकाश चौटाला की तरह नहीं हैं। चौधरी देवी लाल ने कह दिया कि मैं अपने बेटे को डिसओन करता हूं क्योंकि वह स्मगलिंग में पकड़ा गया था। हम आपकी तरह अपने रिश्तों को डिसओन नहीं करते। चौधरी बंसी लाल के भाई 30 साल से ट्रांसपोर्टर हैं और मेरे भाई 15 साल से ट्रांसपोर्टर हैं। हम अपने रिश्तों को डिसओन नहीं करते।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी के बारे में बड़ी-बड़ी दलीलें दी गई और कहा गया कि शराब हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल बंद हो गई है। अखबार में एक खबर छपी है उसकी कटिंग मेरे पास है। शराब का भरा हुआ ट्रक का ट्रक उल्ट गया और वहां पर शराब ही शराब बिखर गई। अध्यक्ष महोदय, निर्मल सिंह जी किताबों के बारे में जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि बस्ते के भारी बोझ के कारण बच्चों की रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ गई लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी रीढ़ की हड्डी किताबों के बोझ के कारण कमजोर नहीं पड़ी बल्कि जहां बच्चों के बस्तों में किताबें होनी चाहिए वहां उनके बस्तों में शराब के पाउच होते हैं। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के हाथों में स्टिक या हाकी होनी चाहिए थी लेकिन शराबबंदी की नीति ने उनके हाथों में बन्दूक पकड़ा दी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। ये निराधार और बेबुनियाद बात कह रहे हैं। यह सरकार ऐसी नहीं है कि आपकी तरह खाली कैप्सूल मंगा मंगा कर लोगों से उन रंगे हुए खाली कैप्सूलों में अफीम भरवा कर सप्लाई करवाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़े बलंगबांग दावे किए कि प्रदेश में शराबबंदी होने से क्राइम कम हुए हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अकेले शराबबंदी की वजह से 5 हजार केसिज दर्ज होने की हर महीने की एवरेज है बाकी और जितने केसिज दर्ज होते हैं वे अलग हैं। वह 5 हजार केसिज वे हैं जो हिदायत के बावजूद भी दर्ज होते हैं। अध्यक्ष महोदय, 31-12-97 तक शराब के बारे में जितने केस रजिस्टर्ड हैं मैं वह बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 31-12-97 तक 88 हजार केस रजिस्टर हुए उनमें से number of persons arrested are 9700. The number of vehicles impounded 6100. The number of challans put up in Courts 63000. The number of persons convicted 3100 and the number of persons acquitted are 200. अध्यक्ष महोदय, इनमें अलग अलग कैटेगरीज की वाइन मिली है। इंगलिश वाइन की 9 लाख बोतलें, कंट्री मेड इंडियन लीकर की 3 लाख 40 हजार बोतलें और 17 लाख पाउचिज पकड़े गए। अध्यक्ष महोदय, जो लाहन है जिसका कभी चालान नहीं होता था वह भी 17 लाख के०जी० पकड़ा गया है। ये सारी चीजें इनके डेढ़ साल के अर्से में पकड़ी गई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में नाजायज शराब की तस्करी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण गवर्नर ऐड्रैस पर बहस के लिए 12 घंटे का समय निश्चित हुआ है और उस 12 घंटे के मुताबिक एक आनरेबल मैम्बर को बोलने के लिए 8 मिनट मिलने चाहिएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे टाईम का तो आप एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं यह कोई नई बात नहीं है। ये सारी पाबंदियां और हिदायतें केवल हमारे ऊपर ही क्यों लागू होती हैं? अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां से सभी मैम्बरों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस शराबबंदी की नीति के लागू होने से पहले हरियाणा प्रदेश में नाजायज शराब की कसीद कहीं पर भी नहीं होती थी लेकिन इस शराबबंदी की नीति के लागू होने के बाद प्रदेश में नाजायज शराब की कसीद शुरू हो गई और उस जहरीली शराब के पीने से काफी लोग मर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था। उसके बाद 30 साल तक हरियाणा प्रदेश में एक या दो हूच काण्ड हुए हैं। चौधरी जगन्नाथ जी भी छिप कर पिया करते थे, ये भी जीवित हैं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा-

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं पहले शराब नहीं पीता था। 1962 में मैं इन्डीपेंडेंट जीत कर आया था और उस वक्त तक चौधरी देवी लाल मुझे जानते नहीं थे। जब इनके परिवार से मेरा सम्पर्क हुआ था तो ये सभी शराब पीते थे। इनके भाई शराब पीते थे, वहीं से मैंने शराब पीनी सीखी। मैं शराब पीने लगा और चौटाला जी देसाई की बीड़ी पीकर क्लब जाते थे। (विघ्न) मैंने तो शराब पीनी 24 जनवरी 1985 को छोड़ दी थी। जबकि इनके परिवार ने आज तक शराब पीनी नहीं छोड़ी है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : चौटाला साहब, मेहरबानी करके आप अपनी बात जल्दी खत्म करिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं कह रहा था कि इनके डेढ़ साल के अरसे में जहरीली शराब के कारण 12 हूच ट्रेजडी के केस हुए हैं। शराब बंदी के हम पक्षधर हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में जब इस बारे में एक बिल आया था तो हमने उसका समर्थन किया था कि यह समाज में एक बुराई है इसे बन्द होना चाहिए। इसे बंद करने की जिम्मेवारी सरकार की है। जब सत्ता पक्ष के लोग ही शराब की तस्करी करें तो शराब कैसे बंद हो जाएगी? इसीलिए इनकी यह पालिसी फेल हो गई।

अध्यक्ष महोदय, जब बंसी लाल जी यहां पर हमारी तरफ बैठा करते थे तो ये कहा करते थे कि यमुना जल समझौता जो हुआ है यह बड़ा घातक हुआ है। भाजपा के भाई तो उस वक्त भी इसे ठीक बताया करते थे क्योंकि उस वक्त भी उन प्रदेशों में इनकी सरकारें थी। लेकिन बंसी लाल जी तो इसे ठीक नहीं मानते थे और उस जल समझौते को इन्होंने आज तक नहीं बदलवाया। इस यमुना जल समझौते के तहत पानी हिमाचल को, राजस्थान को, यू०पी० को और दिल्ली को मिलता है। उस वक्त ये कहते थे कि हम पावर में आएंगे तो इसे रद्द करेंगे, लेकिन ये उस मामले पर अब बिल्कुल चुप बैठे हैं। ये इस पर सख्ती से अमल इसलिए नहीं करते क्योंकि बी०जे०पी० के भाईयों से समर्थन ले रहे हैं अगर ये सख्ती करेंगे तो बी०जे०पी० अपना समर्थन वापस ले लेगी। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि दिल्ली का जो वाटर वर्क्स प्लांट है वह irrespective of this agreement between the five states, it is the responsibility of the Haryana Government to keep it full. हमने इसके रिव्यू की दरख्वास्त दी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट के कन्टैम्प्ट के भागीदार होना नहीं चाहते।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से ये आगरा कैनाल का कन्ट्रोल भी 3 महीने में अपने हाथ में लेने की बात कहा करते थे और एस०वाई०एल० नहर भी 6 महीने में बनाने की बात कहा करते थे। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन मामलों में भी इनको सुप्रीम कोर्ट के कन्टैम्प्ट के भागीदार होने का खतरा है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब हरियाणा के हितों के लिए कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एस०वाई०एल० इस प्रदेश के अन्दर नहीं बन रही। एस०वाई० एल० नहर पहले किसके कहने पर नहीं बनी यह सभी को पता है। ये यहां पर हाउस में गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। आगरा कैनाल के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, जितना बंसी लाल जी ने दिया है। जब इनका वक्त था तो उस वक्त 5 विधायक फरीदाबाद से चुनकर इनको दिये थे लेकिन इन्होंने अपने समय में फरीदाबाद और मेवात का नाम तक नहीं लिया। जिस आगरा कैनाल की बात ये कह रहे हैं उस बारे में पूरे फरीदाबाद जिले का एक एक गांव इस सरकार को और खासकर बंसी लाल जी को बधाई दे रहा है कि जिन खालों पर सालों से कस्सी नहीं लगी थी वहां पर अब मशीनों से खुदाई हो रही है।

स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आने के बाद जिला फरीदाबाद के अन्दर से निकलने वाली आगरा नहर का कंट्रोल लेने के लिए कदम उठाए गए और पहली बार हरियाणा सरकार की निगरानी में और हरियाणा सरकार के खजाने के पैसे से इस पर काम किया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार से हरियाणा सरकार ने पानी का नियन्त्रण लिया है। (विघ्न) इस नहर की खुदाई का काम बाकायदा हो रहा है। 20-20 साल तक जिन नहरों में कभी पानी नहीं आता था आज उनके अन्तिम छोर तक पानी पहुंच रहा है। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय कई सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे जो भी बोलें चेयर की अनुमति ले कर ही बोलें। चेयर की परमिशन के बिना जो भी बोला जाएगा वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे लोग बीच में बोलना तो नहीं चाहते हैं लेकिन यह खतरा रहता है कि इन्होंने कभी जवाब नहीं सुना जवाब के समय तो यह लोग भाग जाते हैं इसलिए हम साथ ही साथ इनको जवाब सुना देते हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि हमारी मिलीभगत होने के कारण प्रदेश के हितों को नुक्सान हुआ है, पंजाब सरकार के साथ हमारी मिलीभगत होने की कोई बात ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के मुखिया ने तथा पंजाब के गवर्नर महोदय ने जब चण्डीगढ़ तथा डिस्प्यूटिड मामलों के बारे में अपने अभिभाषण में उल्लेख किया तो आपके सामने ही हमने एक एडजर्नमैंट मोशन दे कर इसी सदन में लीडर ऑफ दि हाउस को कहा था कि हम मुश्तर्का तौर पर एक रैजोल्यूशन पास करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि उस वक्त यूनैनिमस रैजोल्यूशन हम सब लोगों ने मिल कर पास किया था। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में यह छापा गया है कि डिस्प्यूटिड ऐरियाज के बारे में मीटिंग हुई थी। अध्यक्ष महोदय,

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

लीडर ऑफ दि हाउस ने उस मीटिंग में लीडर ऑफ दि ओपोजिशन को बुलाने तक का कष्ट नहीं किया और चोरों की तरह से मीटिंग कर ली गई थी। उसमें विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया। यह कह रहे हैं कि हमारी प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलीभगत थी। आज जितने भी विषयों पर चर्चा चल रही है और जितने भी वायदे चुनाव से पहले इन्होंने लोगों से किये थे वे पूरे नहीं हुए हैं। (विघ्न)

आवास राज्य मंत्री (श्री सतनारायण लाठर) : स्पीकर सर, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। श्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्य मंत्री हैं और वे अखबारों में ब्यान देते हैं कि अगर एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा में जाएगा तो वह मेरी लाश पर से ही जाएगा, उसी प्रकाश सिंह बादल की जींद में इन्होंने 5 सितम्बर को रैली करवाई है और उनको पगड़ी बांधी है, उनसे ये पगड़ी बदल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इनका अपना राज था तो उस वक्त की ये सारी बातें भूल गए हैं। उस दिनों एक नारा लगा करता था "नीचे बेटा ऊपर बाप नरमा बिके 308" अध्यक्ष महोदय, इनको अपना वक्त तो याद नहीं है इनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि किस प्रकार चौधरी बंसी लाल पर कटाक्ष किया जाए। प्रकाश सिंह बादल के बारे में आज ये बात कर रहे हैं और जो प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं वह भी सब को पता ही है। वे कह रहे हैं कि एस०वाई०एल० का पानी हरियाणा में नहीं आने देंगे और फाजिल्का के 108 गांव भी हरियाणा में नहीं आने देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यह अर्ज है कि आप इनको बीच में टोकने से रोकिए और इनको थोड़ा समझाइये। इनको यह भी शायद ज्ञान नहीं है कि प्वांयट ऑफ आर्डर कहां किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बीच में ये लोग बोल रहे हैं और समय हमारा कटेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जितने भी वायदे किये थे वे पूरे नहीं हुए हैं। इन्होंने वायदा किया था कि लॉटरी को खत्म करेंगे एक दम बन्द करेंगे लेकिन आज किस तरह से लॉटरियों की संख्या बढ़ रही है और गरीब आदमियों को लूटा जा रहा है। लॉटरी से सरकार को 75 करोड़ रुपये की आमदनी होती है और लोगों की जेबों से हजारों करोड़ों रुपये निकल जाते हैं। इन लॉटरीज को खरीदता कौन है ? गरीब लोग रिक्शा चलाने वाले, स्टेशन पर सामान ढोने वाले, रेहड़ी वाले और खोमचे वाले लोग लॉटरीज़ खरीदते हैं। लॉटरीज़ के बहाने अरबों रुपये का घोटाला किया जा रहा है। मेवात ऐरिया में बीमारी फैली थी और उस बीमारी को समाप्त करने के लिए ये कहते हैं कि 18 करोड़ रुपये की दवाईयों का स्प्रे किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक समिति मुकर्रर की जाए जो कि मेवात ऐरिया में छिड़की गई दवाई की जांच करे कि क्या मेवात ऐरिया में कोई हवाई जहाज़ उड़ा या कोई स्प्रे हुआ है ? वहां पर जो दवाई की स्प्रे हुई है वह 18 करोड़ रुपये की दवाई खरीदी गई है। किन लोगों ने खरीदी है, कहां पर उसका स्प्रे हुआ है, किस किस्म की दवाई थी और उस दवाई से किसको लाभ हुआ था ? अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल के मुख्य मंत्री बनने से पहले कांग्रेस सरकार ने मानेसर गांव में जापान डिवैल्पमैंट सीटी बनाने के लिए जमीन एक्वायर की थी।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त के प्रधान मंत्री मेवात में आए थे और उन्होंने 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, न तो चौधरी बंसी लाल जी द्वारा और न ही मेरे डिपार्टमैंट द्वारा 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री जी दो बार मेवात में आए थे उन्होंने 18 करोड़ रुपये की दवाई देने की घोषणा की थी पर पैसे नहीं दिये थे। हमने तो स्प्रे करने की मशीनें जर्मनी से हवाई जहाज़ द्वारा मंगवाई थी और उन से मेवात क्षेत्र में सारा स्प्रे करवाया है। जिन बच्चों का दो-तीन ग्राम होमोग्लोबिन था उनको दवाईयां देकर बचाया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कमला जी ने स्पष्टीकरण देना चाहा यह अच्छी बात है। केन्द्र सरकार की तरफ से 18 करोड़ रुपये की जो घोषणा की गई थी वह रुपया पहुंचा या नहीं पहुंचा?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि देवगौड़ा जी यह कह गए थे कि सारा का सारा पैसा वे देंगे। आज तक न तो एक दवाई आई है और न ही पैसा आया है। अब वह क्यों नहीं आया यह तो इनको पता होगा इनके पिता तो उनको उठाए फिरते थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उनके बाद भी तो एक प्रधानमंत्री आए थे और वे भी एक आधारशिला रख गए और वह आधारशिला वैसी की वैसी ही है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, देवगौड़ा जी के बाद प्रधान मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल जी आए। उन्होंने हरियाणा की बहुत बड़ी सहायता की है। उन्होंने चार सौ मैगावाट के गैस बेस्ड प्लांट के लिए बारह सौ करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट दिया है। इस प्रोजैक्ट पर जो पैसा खर्च होगा वह सारे का सारा भारत सरकार का होगा और इससे जो बिजली मिलेगी वह हरियाणा प्रदेश को ही मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश चौटाला जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड ही करने लगा हूं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लीडर ऑफ दि हाउस हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्लांट की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसा जापान से मिलना था और वह आज तक नहीं मिला है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला में ऐसी मशीन लगी हुई है जो पता नहीं क्या क्या बातें घड़ती रहती है। इनको घर से बातें घड़कर आने की जरूरत नहीं है। अगर इनके दिमाग में कोई अच्छी बात आती है तो इनका दिमाग उसे नज़दीक नहीं लगने देता है। यह हमेशा गलत बात ही बोलते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जापान की ओ०सी०इ०एफ० कम्पनी का पैसा आ गया है और फरीदाबाद में काम शुरू हो गया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये यह भी बताएं कि करनाल की रिफाइनरी पर काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जिस दिन यह रिफाइनरी चालू होगी उस दिन 70 या 75 मैगावाट बिजली बनने लगेगी। हम जो बिजली पहले बना रहे हैं उसको भी इसमें शामिल करके दें तो यह 108 मैगावाट होगी।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें तो रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन करने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो सूरजकुंड में बैठकर यमुनानगर के थर्मल प्लांट का उद्घाटन किया जो आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये गलत बातें कहकर हाऊस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि यह जो कहा जा रहा है कि इस प्लांट की बिजली हरियाणा इस्तेमाल करेगा, ठीक नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिस्कुट खाने की बात कही थी तो ये बिस्कुट तो जरूर खाएं पर पहले चाय मनाली के होटल में पीएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह जो कहा जा रहा है कि गैस बेस्ड पावर प्लांट से जो बिजली तैयार होगी वह सारी हरियाणा प्रदेश को मिलेगी मेरा यह कहना है कि वह हरियाणा प्रदेश को नहीं मिलेगी। केन्द्रीय सरकार की तरफ से अलग अलग रियासतों में जो प्रौजैक्ट लगाए जाते हैं उसी आधार पर केन्द्रीय सरकार का यह प्रोजैक्ट है। जितनी बिजली हम खर्च करेंगे उतना पैसा हरियाणा सरकार को देना पड़ेगा। अगर हरियाणा सरकार के पास पैसा हो तो आज भी जितनी बिजली चाहे आप खरीद सकते हैं क्योंकि एन०टी०पी०सी० के पास बिजली है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस भाई का क्या करें। यह तो न कभी पढ़ा है और न कभी लिखा है। अध्यक्ष महोदय, हकीकत तो यह है कि एन०टी०पी०सी० भारत सरकार की है और उसके मालिक प्रेजीडैंट ऑफ इंडिया हैं। प्रेजीडैंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमको लिखकर आ गया है कि फरीदाबाद के पावर प्लांट की जो बिजली है वह टोटल हरियाणा गवर्नमैंट को सप्लाई होगी तथा यह प्रौजैक्ट सैंक्शन किया जाता है। यह हमारे पास राष्ट्रपति जी की तरफ से आर्डर आ गए हैं। अब आप ही बताएं कि यह ज्यादा सच्चा है या राष्ट्रपति जी ज्यादा सच्चे हैं। इस बात का फैसला सदन ही करे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बड़े जोर शोर से यह प्रचारित किया गया कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। अगर मैं हरियाणा की कानून व्यवस्था की मुंह बोलती तस्वीर के बारे में आपको सारा पढ़कर सुनाऊंगा तो आप मुझे अलाऊ नहीं करोगे क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस सरकार के आने के बाद लूटपाट, डकैती, हत्याएं, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं में निरन्तर बढ़ौत्तरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच, सात-सात साल की मासूम बच्चियों का अपहरण हो जाना तथा उनके साथ बलात्कार करके मारकर फेंक देना और अगर उनके रोते बिलखते मां-बाप थाने के आगे प्रदर्शन करें तथा इस सरकार की पुलिस अगर उनको गोलियों से मारे तो फिर क्या होगा ? आज तक भी उन दोषी लोगों को पकड़ा नहीं गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आज ये बलात्कार और नारी सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन इनको अपना राज याद नहीं रहा जब मंडल कमीशन के विरोध में इन्होंने हरियाणा के नौजवानों को आग में झोंक दिया था और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पेड़ काटकर डाल दिए थे तथा चलती हुई गाड़ियों में से मां बहनों को उतारकर उनके साथ मुंह काला किया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कानून व्यवस्था के बारे में सारी घटनाएं सुनाऊं तो बहुत समय लगेगा। एक अगस्त को करनाल के सैक्टर 14 में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने एक घर में घुसकर श्री विद्या सागर शर्मा, अभियन्ता उनके पुत्र विकास शर्मा, आदित्य शर्मा एवं उनकी पत्नी मधु शर्मा की निर्मम हत्या कर दी और सरकार की इस लापरवाही की वजह से इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि सरकार अभियुक्तों को आज तक पकड़ नहीं पायी। इसी तरह से 20 अगस्त को दो अज्ञात मोटर साईकिल सवार युवक रोहतक जिले में पुलिस गश्ती दल के ऊपर सांपला गांव के निकट गोली चलाकर फरार हो गए और उनका आज तक कुछ पता नहीं कि वे कौन थे ? 2 सितम्बर, 1997 को ही पूनाना में बदमाशों द्वारा सरकारी नकदी लूटने और एक अध्यापक की गोली मारकर हत्या करने की घटना घटी। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरे समय का हिसाब लगाएंगे तो आप को पता चलेगा कि मेरा समय अभी भी बाकी है। मुझे तो इंटरवीन किया गया है और अपनी बात कहने ही नहीं दी गयी। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति की सारी चर्चा करें तो बहुत समय लग जाएगा। आज किसी की जान माल इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मौजूदा गठबंधन की सरकार पुलिस

के डंडे से उनकी जुबान बंद करती है। अगर मजदूर अपनी बात कहें तो उनको लाठी से पीटा जाता है। अगर व्यापारियों ने बढ़े हुए टैक्स के विरोध में प्रर्दशन किया, धरना दिया तो उनके ऊपर झूठे मुकदमें 17.00 बजे बनाए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का जनतंत्र में बिश्वास नहीं है। इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि यह सरकार वोट ऑन अकाउन्ट ला रही है जो कि जाने वाली सरकार लाती है। इस प्रकार सरकार ने स्वयं तसलीम कर लिया है कि यह सरकार जा रही है और हरियाणा में लोकदल और बसपा की सरकार आ रही है इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बंसी लाल : स्पीकर सर, करनाल केस का चौटाला साहब ने जिक्र कर दिया तो उस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि उसमें मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमारी सरकार वोट ऑन अकाउंट क्यों ला रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे बजट के सारे कागज पेश किए हैं। चौटाला साहब ने इलैक्शन कमीशन को शिकायत की थी कि इनको शक है कि कहीं अगर हम बजट पेश करें तो नयी स्कीम उसमें न आ जाए। इसलिए हमने सोचा कि इलैक्शन कमीशन हमसे नाराज न हो जाए इसलिए हम पूरा बजट न पेश करके केवल वोट ऑट अकाउंट ले रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उसके लिए आपके पास 7 मार्च से 31 मार्च तक का समय था। उस समय आप कर सकते थे। लेकिन आपको पता है कि 7 मार्च के बाद आपकी छुट्टी होने वाली है इसलिए आप वोट ऑन अकाउंट लेकर भाग रहे हो। अध्यक्ष महोदय, जाने वाली सरकार वोट ऑन अकाउंट लाया करती है। चुनाव तो 16 फरवरी को हैं। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : हमारी सरकार उन सरकारों में से नहीं है जिनकी हरियाणा भवन में बैठे-बैठे छुट्टी हो गई । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 543 सीटों का चुनाव है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ले देकर 10 सीटों पर समझौता किया है। इनको करनाल में उम्मीदवार मिला नहीं है और ये उम्मीदवार के लिए बम्बई गये थे लेकिन दारा सिंह ने मना कर दिया। गधी मरी पड़ी है और रिवाड़ी का भाड़ा कर रहे हैं। (हंसी) ये चौधरी बंसी लाल जी की मजबूत सरकार के लिए कह रहे हैं कि जाने वाली है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार चुनाव मैदान में उतरती है तो प्रदेश और देश की जनता के लिए किए हुए विकास के कार्यों का उल्लेख करके और अपनी उपलब्धियां गिनाकर वोट मांगती है। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : पिछली बार भजन लाल ने माफी मांगकर पीछा छुड़ाया था।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी आप बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में कन्कलूड कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आपको दो मिनट का समय दिया जाता है।

Sbri Ram Bilas Sharma : He has concluded his speech twice. He has already taken two hours. I want to know for how much time he can speak because he has no content in his speech.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि विकास के काम के आधार पर वोट मांगे जाते हैं जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है इनको वोट तो क्या लोग देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि इन्होंने प्रदेश में विकास का कोई काम नहीं किया है। इस सरकार ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसके नाम पर यह लोगों से वोट मांगे। एक-डेढ़ साल में बस एक ही काम किया है। चौधरी बंसी लाल जी का जी०टी०वी० पर एक इंटरव्यू सुनने का मुझे अवसर मिला जिस पर इन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। इनका तो एक ही काम है या तो लाठी मारें या किसी को अन्दर करें। जिन व्यापारियों ने हड़ताल की उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बनाकर उनको अन्दर किया गया। (विघ्न) आप समय तो दे नहीं रहे मैं कंक्लूड कैसे करूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप कंक्लूड करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। फिर भी आप नहीं करने दे रहे हैं। आखिर मैं विपक्ष का नेता हूं मेरा भी तो अधिकार है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहना था वह तो कह दिया अब तो ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार की सारी उपलब्धियां ही बताई गई हैं और कुछ नहीं बताया गया।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, देश के प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में 410 मैगावाट के संयंत्र का उदघाटन करते हुये कहा कि पूरे देश में इतनी रफ्तार से काम कहीं नहीं हुआ जितनी रफ्तार से चौधरी बंसी लाल की सरकार ने 18 महीनों में काम किया है। जिसने 1500 मैगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करने का काम किया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : व्यापारियों के टैक्स बढ़ाये उन्होंने विरोध में बन्द किया तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बनाये गये और उन्हें जेलों में बन्द किया। बी०जे०पी० ने यह वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो मूसार चूंगी को खत्म करेगी। इन्होंने कर्मचारियों पर ज्यादतियां की, किसानों पर गोलियां चलाईं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गाबा जी आप बोलिये।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले यह अर्ज करना चाहूंगा कि ऑनरेबल गवर्नर महोदय का अभिभाषण प्रदेश का एक आईना होता है। उसमें गवर्नमेंट की पोलिसी, गवर्नमेंट की प्लानिंग आदि क्या काम करने जा रहे हैं उस पर डिस्कशन होती है। परन्तु आखिरकार इस चर्चा के दौरान एक दूसरे पर ऐलीगेशन लगाने या एलीगेशन का जवाब देने के अलावा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। इस चर्चा में कुछ सुजेशन आते, यह सुनने को मिलता कि इस मद में यह पैसा इस काम के लिए रखा है, इस मद में यह रखा है ऐसी बातें डिस्कस की जाती तो फायदा होता लेकिन यहां तो ऐलीगेशन के सिवाय कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसी बात तो आती ताकि हम यह समझते कि सरकार बनाने का हमें यह फायदा हुआ है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) मेरी आपसे सबमिशन है कि क्या ऊंचा बोलने से, झूठ को सच बनाया जा सकता है या ऐलीगेशन लगाने से कोई बात सही बन जाती है यह बात मुमकिन नहीं है यह सब ठीक नहीं किया गया। जो बातें डिस्कस करनी थीं वे धरी की धरी रह गई हैं। डिप्टी स्पीकर सर,

मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा आईना है जो यह बताता है कि पब्लिक के लिए क्या-क्या काम किये गये या करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ ढिंढोरा यहां पर पीटा गया है। बिजली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इससे तो यह साबित होता है कि जो कुछ भी इन्होंने अब करना है या ये करने जा रहे हैं, वह सब इन्हीं की देन है तथा इनसे पहले कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं कर सकी है। इन्होंने कहा कि 800 मैगावाट बिजली हरियाणा में पैदा हो चुकी है और आगे आने वाले समय में 1100 मैगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। राज्य की जनता की डिमांड को पूरा करना हर सरकार का कर्तव्य है। आदरणीय बहिन जी जो कि मंत्री हैं, ने भी कह दिया कि यमुना नगर में रिमोट कंट्रोल के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया। मैं आपके द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं कि फाउंडेशन स्टोन तो रख दिया गया, लेकिन उसका काम पूरा क्यों नहीं किया ? क्या उस कार्य को कोई विपक्ष का आदमी करेगा या कोई बाहर से आकर के करेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में, कानून और व्यवस्था के बारे में और इंडस्ट्रीज के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। आज हम ने इंडस्ट्रीज के बारे में एक प्रश्न रखा था लेकिन दुर्भाग्य से वह प्रश्नकाल में नहीं लग सका। मैंने पूछा था कि गुड़गांव में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य की रफ्तार चालू की थी वह आज रुकी हुई है, क्या उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ? जो जमीन किसानों की एक्वायर की गई है, उसका बोझ उद्योगपतियों पर डाल दिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि वहां पर एम०आई०टी०सी० बनाएंगे। इस बारे में जिक्र हुआ है, इस संदर्भ में जो पैसा मुआवजे के रूप में मानेसर के लोगों को मिल रहा है, वह बहुत कम है। आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वे भी पहले विपक्ष में थे तो उस वक्त ये भी कहा करते थे कि यह मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इनके द्वारा इस बात का ढिंढोरा पीटा गया कि एम०आई०टी०सी० बना देंगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। लेकिन इनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि ये क्या करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था के बारे में प्रश्न किया गया कि सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है ? हम ने दो-तीन बार पूछने की कोशिश की तो हर बार कह दिया गया कि बैठ जाइए। लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि हम पुलिस को व्हीकल्ज़ दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि सदर थाना, गुड़गांव में कुल 13 सिपाही हैं और उस के अधीन 200 गांव पड़ते हैं। एक सिपाही की डियूटी बाहर लगी होती है, एक लिखने-पढ़ने के कार्य में संलग्न रहता है और एक सिपाही सम्मन के आदेशों को देकर के आता है। इस प्रकार से वे 13 सिपाही वहां पर क्राईम कैसे रोक पाएंगे ? क्राईम्ज को रोकने के बारे में सुझाव किसी ने नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुड़गांव की एक कॉलोनी में रहता हूं। वहां पर एक पुलिस पोस्ट है उस पोस्ट के प्रभारी के पास कोई टेलीफोन सुविधा नहीं है। इस प्रकार से वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे काबू हो सकेगी ? इसलिए डिस्कशन का फायदा यह है कि उस में अच्छे सुझाव ही दिये जाने चाहिएं। सिर्फ ढिंढोरा पीटने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। आज यहां पर जो कुछ बोला गया है, उस बारे में कोई साफ-साफ पता ही नहीं चलता है कि किस बारे में डिस्कशन की जा रही है। लोगों ने हमें यहां पर चुनकर भेजा है तथा जब वे वहां पर हम से यह बात पूछेंगे कि सदन के अंदर क्या कुछ हुआ है तो हम बता पाने की स्थिति में नहीं होंगे। अतः उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ढिंढोरा यहां पर पीटते हुए एक बात यह भी कही गई कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गई है। उसका क्या यह सबूत है कि चण्डीगढ़ में वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में एम्पलाइज ने डिमानस्ट्रेशन किया उसको देखकर आप कह सकते हैं कि आपने एम्पलाइज के लिए बहुत कुछ किया है इसके अलावा कर्मचारियों ने यह अनाउंसमैंट की है कि अगले हफ्ते से वे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टरों पर डिमान्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। यह इस बात का सबूत है

[श्री धर्मबीर गाबा]

कि आपने एम्पलाइज के लिए कुछ नहीं किया हमने और रणदीप जी ने यहां प्रोहिबिशन के बारे में सवाल किया था उसके बारे में आंकड़े पढ़कर बताए गए थे। चौटाला साहब ने भी अभी वे आंकड़े दोहराएं हैं। यह जानकर मुझे दुःख होता है जब यह कहा जाता है कि यह सरकार प्रदेश में शराबबंदी नीति लागू करने में कामयाब हुई है। इसकी स्कीमें कामयाब हुई है। अगर शराब के बारे में कोई सच्ची बात कहता है तो इनको उस बात से बहुत दुःख होता है। अगर हम शराब के बारे में सही बात कहते हैं तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं। चौटाला साहब बोलें या अपोजीशन का कोई और मैम्बर बोले तो इनको उसकी बात अच्छी नहीं लगती। आज प्रदेश के गांव-गांव में शराब बेचने का धंधा हो रहा है। आज जिस गांव की दो या अढाई हजार की आबादी है उसमें 20-20, 25-25 आदमी शराब बेचने में लगे हुए हैं। अगर किसी भाई को इसका यकीन न आता हो तो मेरे पास आ जाए मैं उसको गुड़गांव के गांवों के नाम बता देता हूं कि किन गांवों में शराब बिकती है जिस गांव की आबादी 2 या 3 हजार है वहां पर 20-20 और 25-25 आदमी शराब बेचने के काम में लगे हुए हैं। इससे बढ़कर शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? कहा जाता है कि शराबबंदी की नीति लागू होने से ला एण्ड आर्डर की पोजीशन बिल्कुल ठीक हुई है। क्या ये दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की पोजीशन सही है? आज एक प्रश्न इस सदन में किया गया था और उस पर गवर्नमैंट ने जवाब दिया कि गुड़गांव में 50 लाख की डकैती हुई है, उसमें से 8 लाख रुपये तो रिकवर हो गये हैं और 42 लाख रुपये रिकवर नहीं हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जिन आदमियों ने डाका डाला क्या उन आदमियों के नाम दर्ज हैं? आज थानों की हालत यह है कि यदि कोई आदमी किसी नाजायज काम के बारे में थाने के अन्दर अपनी दरख्वास्त देने जाता है तो उसकी दरख्वास्त नहीं ली जाती है, जब तक कोई बहुत बड़े अधिकारी या पोलिटिशियन की सिफारिश न हो। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब हम सारे मिलकर इस बारे में सुधार करें। इस काम को ठीक ढंग से चलाएं। आज तक वह डकैती का 42 लाख रुपया गुड़गांव का नहीं मिला और जब तक वह मिलेगा तब तक वहां पर और डकैती हो जाएगी। आज गुड़गांव के अन्दर कोई ऐसी सेफ जगह नहीं है जहां शाम 7 बजे के बाद कोई बच्चा या लेडी कार चलाकर चली जाए और वह वापिस सही सलामत घर आ जाए। उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि उसकी ला एण्ड आर्डर की पोजीशन बहुत अच्छी है। उपाध्यक्ष महोदय, किस-किस बात का हम इनसे जिक्र करें।

श्री मनी राम गोदारा : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ गाबा जी कह रहे हैं इन्होंने इस बारे में मुझे एक बार लिख कर दिया था। I got inquired and gave their application in the hand of Mr. Guaba but he never replied me. He never told me anything after that. He never asked me again.

श्री धर्मबीर गाबा : मैंने आपको जो एप्लीकेशन दी थी वह आपने डी०आई०जी० को मार्क की थी। My duty was to give the letter to the D.I.G. आप डी०आई०जी० से पूछें कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया मैं पूछने वाला नहीं हूं। मेरा कसूर तब है जब वह लैटर डी०आई०जी० को न मिला हो। इसका मतलब तो यह है कि ये आफिसर आपकी (होम मिनिस्टर) परवाह नहीं करते। इसका आप अन्दाजा लगा लीजिए। मैं तब गुनाहगार हूं अगर वह लैटर दूसरे दिन डी०आई०जी० को न मिला हो। मुझे क्या पता कि आपके अन्दर, पुलिस विभाग के अन्दर या डी०आई०जी० के अन्दर क्या कम्यूनिकेशन है। मैंने तो वह लैटर दे दिया था और वाई हैंड दे दिया था। मैं समझता हूं कि कुछ लिमिटेशन हर एक की होती हैं। आज एक किस्सा यहां पर हुआ था कि जब चौटाला साहब के पिता आदरणीय श्री चौधरी

देबीलाल यहां पर मुख्यमंत्री थे और बादल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब भी एस०वाई०एल० कैनाल नहीं बन सकी। जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी भजनलाल की हुकुमत थी और पंजाब में कांग्रेस की हकूमत थी तब भी नहीं बन पाई। इस समय बी०जे०पी० यहां भी पार्टनर है, पंजाब में भी पार्टनर है तब भी वह नहीं बन पा रही। इसका हल तो एक ही है कि सारे एम०एल०ए० सैन्टर गवर्नमैंट पर जोर दें कि एस०वाई०एल० कैनाल को बनाने का काम अपने हाथों में लेकर पूरा कराएं। मैं 1982 में पहली बार एम०एल०ए० बन कर आया था और 1983 के अन्दर चौधरी भजन लाल जी हसनपुर गए थे। हसनपुर के एम०एल०ए० यहां हाउस में बैठे हुए हैं।उनको पता है कि वहां पर मेरे बाप दादा की जद्दी जायदाद है। वहां पर हमारी हजारों एकड़ जमीन है। यह ठीक बात है कि हम उसमें से कुछ जमीन बेच कर खा गए नहीं तो हम हसनपुर के सबसे बड़े जमींदार थे। मैंने 1983 में चौधरी भजन लाल जी से कहा था कि आप आगरा कैनाल का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए क्योंकि उसका कंट्रोल अपने हाथ में न लेने से हमें उसका बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है लेकिन आज ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि चौधरी बंसी लाल ने वह काम किया है। किसी ने भी किया है या नहीं किया है लेकिन हम 1983 में यह कहते थे कि आगरा कैनाल का कंट्रोल आप अपने हाथ में लें क्योंकि वह कैनाल मेरे एरिया से गुजरती है। एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह भी कहा गया कि केन्द्रीय पूल में 25 परसैंट गेहूं और 11 परसैंट राईस हरियाणा प्रदेश देता है। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि जहां पालिसी हुकुमत का हिस्सा होता है वहां उसके अन्दर मेहनतकश किसानों का भी हिस्सा होता है जो हमारी पैदावार बढ़ाते हैं। आज अनाज की जितनी पैदावार बढ़ी है वह किसानों की मेहनत के कारण बढ़ी है इसलिए सरकार और किसान दोनों ही पैदावार बढ़ाने के लिए मुबारिकबाद के हकदार हैं। इनमें से कोई एक इस बात का क्रैडिट नहीं ले सकता। इनमें से एक यह नहीं कह सकता कि उसने इस बारे में सब कुछ किया है। यदि इस बारे में कुछ कहूंगा तो यहां पर हंगामा खड़ा हो जाएगा। आजकल किसानों के साथ जो सलूक किया गया है, क्या वह जायज है? मैं एक दिन चेयरमैन के नाते वहां गया था जहां का तस्कर हमारा सारा दिन खा गया लेकिन यह सरकार इतनी फिराखदिली भी नहीं दिखा सकी कि इसने वहां के गरीब किसानों के नाम तक दर्ज नहीं किए और न ही उनको हमदर्दी का कोई लैटर तक भेजा। इन्होंने उनको मार तो दिया जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। मैंने कमेटी का चेयरमैन होने के नाते से देखा है जिस आदमी का कोई कसूर नहीं था उसको रबड़ की गोलियों से छील दिया। हम यह नहीं कहते कि आप लोगों से वोट मांगने कैसे जाएंगे लेकिन आपका यह फर्ज नहीं है कि आप उनके साथ ऐसा सलूक करें। अगर हम उनकी नुमायंदगी करते हैं तो हमें उनकी नुमायंदगी ठीक ढंग से करनी चाहिए। उनको हम कम से कम नाजायज तौर पर तंग न करें। आपको हुकुमत भगवान ने दी है। हुकुमत आपको लोगों की वजह से मिली है इसलिए आपसे कुछ मांगने का लोगों का हक है और उसे पूरा करने का आपका फर्ज है।मेरी आपसे प्रार्थना है कि बजाय इसके कि हर वक्त हर आदमी दूसरे आदमी से ज्यादा नम्बर ले जाना चाहता है यानि अगर कोई सी०एम० साहब की ज्यादा तारीफ करे तो उसका नम्बर ज्यादा होगा यह नहीं होना चाहिए। आदमी को कोई कंक्रीट सुजैशन देनी चाहिए, चाहे उसके लिए उसका नम्बर घट जाए। लेकिन किसी की तरफ से कोई कंक्रीट सुजैशन नहीं आई कि हम किसानों की भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं। (शोर) बहन कमला वर्मा आप मुझे इस बात का फैसला करके बताएं कि आप म्यूनिसिपल कमेटीज का ढिंढोरा पीटती हैं और आप उनके बारे में हमसे सुजैशंज मांगती हैं आप इस बात का जवाब दें कि नक्शा पास करने की पावर आपने उसके एग्जैक्टिव औफिसर को दे रखी है। जो लोगों द्वारा चुने हुए नुमायंदे हैं, उनको वह पावर नहीं दे रखी है। अगर आप यह कहते हैं कि जो लोग चुने हुए नुमायंदे हैं जिनको लोगों ने चुनकर कमेटी में भेजा है उसके चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं यदि नक्शा वह पास

[श्री धर्मबीर गाबा]

न करें तो ठीक बात नहीं है। आप गुड़गांव का रिकार्ड मंगवा कर देख लें वहां का एक भी नक्शा एग्जैक्टिव औफिसर की मर्जी के बगैर पास नहीं हुआ। वहां सारे नक्शे वहां का एग्जैक्टिव औफिसर पास करता है। यदि यह बात मैं गलत कहता हूं तो उसके लिए मैं गुनाहगार हूं। वहां के एग्जैक्टिव औफिसर ने यह लिख कर दिया हुआ है कि उसकी मर्जी के बगैर कोई नक्शा पास नहीं होगा लेकिन फिर भी इस बात की कोई परवाह नहीं करता। आपको नक्शा पास करने की पावर कमेटी को देनी चाहिए। मैं गुड़गांव के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि यह ओहदा पांच साल तक मेरे पास भी रहा है। हमारे वक्त में एक बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर कमेटी की जो स्ट्रीट लाईटें हैं, वे सुबह-शाम के वक्त जलनी चाहिएं ताकि किसी बूढ़े व्यक्ति ने किसी मन्दिर, गुरूद्वारे या सैर करने जाना हो तो आसानी से जा सके या शाम को सैर करनी हो तो ठीक प्रकार से कर सके। इसी प्रकार से हमारी कोशिश रहती थी कि शहर की जो सड़कें हैं, वे ठीक रहें। मैं बताना चाहूंगा कि गुड़गांव शहर की जो एक मेन रोड डाकखाने के साथ लगती हुई निकली है, वहां पर एक एक फुट के गढ्ढे हैं और वे आज से नहीं बल्कि पिछले छः महीने से पड़े हुए हैं लेकिन उनको ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि शहर में कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह सड़क नगरपालिका की है, पी०डब्ल्यू०डी० की है या मार्किटिंग बोर्ड की है। इस वजह से इनका फैसला न होने के कारण उनकी रिपेयर नहीं हो पाती। इन सड़कों की रिपेरयर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब आप ऐसी सड़कों का चाहे वे किसी भी शहर में हों फैसला करवा दें ताकि उनकी रिपेयर हो सके। अगर आप ठीक समझें तो इनको आप टेकओवर करके नगरपालिका को दे दें ताकि उनकी रिपेयर तो हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाने की बात हुई। मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि इसे पहली क्लास से लागू किया जाये। शर्मा जी आप तो प्रौफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं आपको अच्छी सुजैशन को मानना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का हक नहीं है? क्या अंग्रेजी पढ़ने का प्रिविलेज हाई क्लास के लोगों को ही है? क्या चपड़ासी का बेटा चपड़ासी ही लगे और कांस्टेबल का बेटा कांस्टेबल ही रहे? इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे तीनों बच्चे कान्वेंट स्कूल में पढ़े हैं और वे बेहतरीन जगह पर एडजस्ट हैं। मुझे उनके बारे में कहीं पर कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्टरनैशनल लैंगूवेज को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। मेरी शिक्षा मंत्री से प्रार्थना है कि उन्होंने यदि सबाल का जबाव "ना" में दिया है तो क्या उसे "ना" में ही रहने देंगे। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और मैम्बरों की भावनाओं का ख्याल करते हुए आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो ठीक सुझाव आये हैं, उनको मानना चाहिए। आगे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए इस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए और जो काम हम नहीं कर पाये तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी न करें, यह ठीक बात नहीं है। हमें यहां पर इकट्ठे होने का जो मौका मिला है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए और अच्छी बातों पर अमल करना चाहिए। यदि विपक्ष के साथी कोई अच्छे सुझाव देते हैं तो उनको आपको मानना चाहिए। अतः मेरी फिर प्रार्थना है कि आपको हरियाणा की बहबूदी के लिए फिर से इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

डॉ० कमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अच्छे सुझाव दिये, मैं इनका धन्यबाद करती हूं। साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि जो महकमा मेरे पास इस वक्त है इसके ये मंत्री स्वयं रहे हैं, जो सुझाव अब दे रहे हैं उन सुझावों को उस वक्त क्यों नहीं कार्यान्वित किया। जो सड़कों को पी०डब्ल्यू०डी० से या नगरपालिका की सड़कों के झगड़े की बात कर रहे हैं, उस वक्त इन्होंने उसको व्यवाहारिक रूप देना

चाहिए था जो नहीं दिया परन्तु अब यह सरकार अवश्य इस काम को करेगी। अब ये पहली कलास से अंग्रेजी पढ़ाने की बात कह रहे हैं। जब इनका राज था, तो इनके समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल 12 साल तक इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे, उस वक्त इन्होंने इसको व्यवहारिक रूप में लाने की क्यों नहीं कोशिश की। हम अन्य सभी सड़कों की भी जो मार्किट कमेटीज़ की हैं उनकी मुरम्मत या तो कर दी है या अन्य की कर रहे हैं।

श्री धर्मबीर गाबा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमने कोई गलती की है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उस गलती को सुधारा न जाए।

डॉ० कमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इनके सारे सुझावों के लिए इनका धन्यवाद करते हैं। (विघ्न)

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी पहले भी मुख्य मंत्री रहे हैं। मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करें कि जब वे पहले मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने बिजली का प्राईवेटाईज़ेशन क्यों नहीं कर लिया, आज वे बिजली का प्राईवेटाईज़ेशन करने जा रहे हैं। (विघ्न)

डॉ० कमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का प्राईवेटाईज़ेशन करने नहीं जा रहे हैं ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। फिलहाल चार ज़िलों में इसको एक्सपैरिमैंट के तौर पर देखा जा रहा है,लेकिन इन्होंने एक ही रट लगा रखी है कि बिजली का सारे हरियाणा में प्राईवेटाईज़ेशन कर दिया है। यह प्राईवेटाईज़ेशन नहीं है बल्कि इसे बिजली का सुधारीकरण कह सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्ज़ बाद में मिल जाएंगी कि इससे क्या लाभ या नुक्सान हुआ है। आने वाले वक्त में बिजली की नई उत्पादन योजना के अनुसार इनको पता है कि लोग इनको वोट नहीं देंगे, हरियाणा के अन्दर इतनी ज्यादा बिजली पैदा हो जाएगी कि जो जरूरत से ज्यादा होगी उसके लिए हरियाणा की जनता चौधरी बंसी लाल की सरकार के गुण गाएगी और इनको वोट नहीं मिल पाएंगे। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया को तो सोते जागते वोटों की बात ही सूझती है। हो सकता है इससे हरियाणा प्रदेश में बिजली की स्थिति में भी सुधार हो जाए लेकिन 6-6, 7-7 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली लोगों को मिलेगी और लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो फिर इतनी मंहगी बिजली प्रदेश में कौन खरीद पाएगा। मंत्री महोदया, यह बताएं कि इतनी मंहगी बिजली का उपयोग कौन करेगा ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब श्री सुर्जेवाला बोलेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला (नरवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जब मैं पहली बार आया था तो बड़ी आशाओं के साथ आया था कि यहां पर हरियाणा के बड़े-बड़े धुरन्धर राजनीतिज्ञ हैं और उनसे मुझ जैसे नये आदमी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर पिछले करीब अढ़ाई घंटे से जो चर्चा इस सदन के अन्दर चल रही है, उसे देख कर मुझे बेहद दुख तथा निराशा हुई है। एक तरफ विपक्ष के नेता माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दो-तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दूसरी ओर सदन के नेता चौधरी बंसी लाल जी भी तीन दफा मुख्यमंत्री रहे चुके हैं और अब भी मुख्य मंत्री हैं। श्री राम बिलास शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता है और 4 बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं और

[श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला]

अब भी सदस्य और मंत्री हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन से हरियाणा की जनता को बड़ी भारी उम्मीदें हैं और आशा भरी नज़रों से जनता इस सदन की ओर देख रही है इसलिए इस सदन के अन्दर जो भी बात कही जाए वह गम्भीरतापूर्वक कही जाए, सिर्फ एक-दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए या मज़ाक के लहज़े में कोई बात नहीं कही जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम महोदय के अभिभाषण पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा की जाए। हरियाणा की जनता हर बात को देख रही है। उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ की रवायत देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं माननीय गाबा साहब की ताईद करता हूं। आज हम अपनी दिशा खो चुके हैं। केवल नम्बर बनाने के चक्कर में या मुख्य मंत्री जी की चापलूसी करने के लिए कोई बात कही जाए वह ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष, विपक्ष को या विपक्ष सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने के लिए कोई बात न कहें। वे इस बात को ध्यान में रखें कि हरियाणा की जनता ने उनको चुन कर भेजा है इसलिए सामूहिक रूप से सभी लोग मिल कर प्रदेश के हित की बात करें। प्रजातन्त्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। अगर सरकार कोई गलत बात कर रही है तो उसकी जोरदार मुखालफित की जानी चाहिए और सरकार को ठीक रास्ते पर लाने के लिए सरकार के कान खींचे जाने चाहिएं। अगर विपक्ष कोई ठोस बात कहे या कोई सुझाव दे तो उसको सिर्फ इसी रूप में रिजैक्ट नहीं कर देना चाहिए कि यह बात किसी विपक्ष के सदस्य ने कही है, सत्तापक्ष के सदस्य ने नहीं कही है। उपाध्यक्ष महोदय, भाई नृपेन्द्र सिंह जी ने महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ करते हुए सबसे पहले बिजली के क्षेत्र की बात कही। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि किस प्रकार से सरकार हरियाणा में बिजली की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण में यह बात भी बताई गई है कि कहां पर क्या काम किया जाना है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पानीपत ताप बिजली घर 110-110 मैगावाट के चार यूनिट्स को रैंथन करने के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से उनको ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इसके पूरा होने से इन यूनिटों का उत्पादन 8 मैगावाट बढ़ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, 8 मैगावाट यूनिट बिजली पैदा करने के लिए सरकार 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। तकरीबन 37.5 करोड़ रुपये पर मैगावाट बिजली पैदा करने पर खर्चा इस सरकार का होगा। यह न तो इन्टरनैशनल स्तर पर है और न ही नेशनल स्तर पर है। अगर सर, यह बात सही है तो यह काफी चौंकाने वाली बात है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक बात और कही गई है। इस अभिभाषण के पेज नं0 2 पर है :

> "इसके अलावा वर्तमान 30 प्रतिशत विद्युन्मात्रा पर चल रहा यह संयंत्र 80 प्रतिशत विद्युन्मात्रा पर कार्य करेगा"

अगर 32 मैगावाट बिजली बढ़ेगी और 30 प्रतिशत पर चलेगा तो टोटल 41 मैगावाट बिजली पैदा करेंगे, 300 करोड़ रुपये का खर्चा करने के बाद टोटल बिजली 220 मैगावाट पैदा होगी। अगर 32 को ऐड करें तो 188 मैगावाट बिजली कहां गई। यहां अभिभाषण में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसके अलावा अभिभाषण में यह कहा गया है कि :

> "इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान 25-25 मैगावाट वाले निजी-क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे तरल इंधन पर आधारित बिजली उत्पादन यूनिटों से 300 मैगावाट बिजली प्राप्त होने की संभावना है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में चर्चा पिछले अभिभाषण में भी की गई थी। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने 25-25 मैगावाट के यूनिट लगाने के एग्रीमैंट किए थे। आज की मौजूदा सरकार ने जब सत्ता

सम्भाली तो कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो एग्रीमैंट किए हैं वे गलत है उनको रद्द कर दिया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने सदन के मेता और बिजली मंत्री जी को एक बात कही थी कि 25 मैगावाट के यूनिट जल्दी लगवाने चाहिएं। आज डेढ़ साल बाद ये फिर से वही बात कर रहे हैं। अगर ये यूनिट पहले ही लगा दिए जाते तो हरियाणा की जनता को अब तक 6-7 यूनिट बिजली मिल जाती । आज भी यह नहीं बताया जा रहा है कि इन्होंने किससे समझौता किया है। क्या एग्रीमैंट किया है। कितने अमाउन्ट का समझौता किया है या जिससे पहले समझौता किया गया था उन्हीं से समझौता करेंगे। इस समझौते से कितनी बिजली मिलेगी। इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। यह जो कुछ भी है, यह एक वेग बात है। इसके साथ ही अभिभाषण में एक बात और कही गई है कि :

> "इस उद्देश्य के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अलग-अलग राज्य स्वामित्व की बिजली उत्पादन, पारेषण तथा चार वितरण कम्पनियों में बांटा गया है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमला वर्मा जी ने कहा है कि एक्सपैरीमैंटल तौर पर चार जिलों में बांटा गया है। ये इस बारे में रिकार्ड चैक कर लें कि इन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को और इलोदरा के सदस्यों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था और काला बिल पास कर दिया था। आज इसमें क्या क्या करके क्या किया जा रहा है इसको करने के लिए इनको अपनी अन्तर-आत्मा से सोचना चाहिए। हजारों करोड़ों रुपये की वह सम्पत्ति जो हरियाणा की जनता की समपत्ति है, आज बिजली वितरण के नाम को लेकर इस सम्पत्ति को प्राइवेट कम्पनियों के हाथों में दिया जा रहा है। हरियाणा की जनता के लिए इससे भद्दा मजाक और कोई नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक ऐसा इंडिपैंडेन्ट कमीशन बनाया जा रहा है।

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री अत्तर सिंह सैनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यह काम कोई प्राईवेट कम्पनी को नहीं दिया जा रहा है। यह जो चार ग्रुप बनाए जा रहे हैं यह प्राईवेट नहीं हैं बल्कि सरकारी ग्रुप होंगे।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये इससे अगली लाईन भी पढ़ लें। इनके दिमाग में कोई संशय है तो वह दूर हो जाएगा। इसी अभिभाषण में अगली लाईन में लिखा है कि "हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अलग-अलग राज्य स्वामित्व की बिजली उत्पादन, पारेषण तथा चार वितरण कम्पनियों में बांटा गया है जिनका पर्यवेक्षण एक स्वतंत्र विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा।"

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं हमारे योग्य सुर्जेवाला साहब को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो पहले कहा कि एच०एस०ई०वी० को जो विश्व बैंक से ऋण मिला है तथा इससे जो बिजली का उत्पादन होगा तो वह बिजली महंगी होगी। सर, इनका यह खदशा ठीक नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ऐसा करने से बिजली महंगी नहीं होगी बल्कि किसान को बिजली उससे सस्ती मिलेगी। पिछले डेढ़ साल से यह सरकार बिजली उत्पादन के कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। हमारे कुछ साथी सारी स्टेट में यह कह रहे हैं कि बंसी लाल जी की सरकार बिजली बोर्ड को समाप्त कर रही हैं कर्मचारियों की छंटनी कर देंगे, बिजली महंगी हो जाएगी या हम प्राईवेट कम्पनियों को बिजली बेच रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, न ही बिजली बोर्ड हरियाणा के लोगों से अलग होगा और न ही हम कर्मचारियों की छंटनी करेंगे। यह इनकी बिल्कुल निराधार शंका है। यह चार कम्पनियां बिजली के काम को व्यवस्थित करने के लिए हैं। इनकी सेवाओं को और अच्छी तरह से सुधारने के लिए यह किया जा रहा है। बिजली बोर्ड की जो सेवा अब तक हरियाणा को मिली है वह पर्याप्त नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश है इसलिये हमारा इसको सुधारने का प्रयास है न कि प्राईवेटाइजेशन का। जो चार कम्पनियां बनेंगी वह अलग-अलग हैं एक उत्पादन के क्षेत्र में एक वितरण

[श्री राम बिलास शर्मा]

के क्षेत्र में एवं एक ट्रांसफ्यूजन के क्षेत्र में काम करेंगी और उनका नियन्त्रण हरियाणा सरकार के अधिकारी ही करेंगे जैसे एच०एस०ई०बी० है यह भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। (विघ्न) ये जो चार आयोग बनेंगे इनमें आज के बिजली बोर्ड के अधिकारी और कुछ वरिष्ठ अधिकारी हरियाणा सरकार के होंगे, वे उनके ही नियंत्रण में होंगे। यह प्रवृत्ति में ऑटोनोमस ही होंगे परन्तु इन पर हरियाणा सरकार के लोगों का ही नियंत्रण रहेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में लिखा हुआ है कि-

"One of the distribution companies will, initially, be converted into a joint venture company in order to bring in private participation and resultant efficiencies into the system"

एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कम्पनियों को नहीं देंगे और दूसरी तरफ अभिभाषण में लिखा हुआ है कि इसमें प्राइवेट पार्टीसिपेशन होगा। यह ज्वांइट वैंचर हैं और प्राइवेट कम्पनी इसमें आएंगी।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कप्तान साहब, फौज से आए हुए हैं और ताजी ताजी टिकट की लड़ाई लड़कर आए हैं। अब ये उत्साहित हैं या निरूत्साहित हैं यह तो बाद में पता चलेगा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम प्रयोग के तौर पर कुछ कामों में प्राइवेट लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं परन्तु अल्टीमेटली जो नियंत्रण है वह चारों आयोगों का ही रहेगा और उसमें हरियाणा के ही लोग होंगे।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात कही और राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो कहा है, उनमें काफी विरोधाभास है। जैसा कि कैप्टन साहब ने पढ़कर सुनाया है, इसमें यह है कि निजी क्षेत्र को भागीदारी में लाकर उससे जुड़े हुए लाभ को प्रणाली में लाया जा सके।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वकील हाई कोर्ट के ये भी हैं और लाइसैंस हाईकोर्ट के वकील का मेरे पास भी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने खुद माना है और मैं इस महान सदन में कह रहा हूं कि कुछ प्राइवेट भागीदार हैं उनको सेवाओं में सुधार के लिए लाएंगे। जहां तक नियंत्रण का मामला है तो उन पर नियन्त्रण आयोग करेगा। उनका नियंत्रण पर अधिकार नहीं होगा। उनकी सेवाएं हम अपनी सेवाओं को ठीक करने के लिए लेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात को जारी रखते हुए मंत्री जी ने जो एक्सप्लेनेशन दी है उससे तो एक बात समझ में आई कि डिस्ट्रीब्यूशन का मामला, बिजली वितरण का मामला, बिजली बनाने का मामला और बिजली बेचने का मामला तीनों एक ज्वाइंट वैंचर को दिए जाएंगे जिनमें प्राइवेट कम्पनियां भागीदार होंगी और इनके ऊपर एक और भी बॉडी होगी जिसको इंडिपैंडैंट पॉवर रैगूलेटरी कमीशन कहते हैं, जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। पिछले सत्र में जो बिल आप लेकर आए थे उसके अंदर ऐसा साफ लफ्जों में लिखा हुआ है इसका नतीजा यह होगा कि बिजली का भाव किसान को किस रेट से देना है, व्यापारी को किस रेट से देना है और कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजली का रेट क्या होगा, उसका फैसला तीसरा आदमी आर्बिट्रेटर किया करेगा। जो प्राइवेट कम्पनियां होंगी, जो लाभांश के लिए हरियाणा में निवेश कर रही हैं उसमें उनके नुमाएंदे बैठे होंगे और वे अपनी मनमर्जी से फैसला करेंगे। इस प्रकार इसमें प्राइवेट आदमियों की हिस्सेदारी होगी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली का जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह हरियाणा की जनता की मल्कीयत है उसके अंदर आप प्राइवेट आदमी को हिस्सा किस प्रकार से दे सकते हैं।

श्री सत पाल सांगवान : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर सर, शायद मेरे साथी रणदीप सुर्जेवाला डाउट पैदा कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सीधा लिखा हुआ है (विघ्न) Mr. Surejewala, I know much better than you about Electricity. Why are you creating confusion in the minds of the people by saying such things. You should know that there are three system of electricity i.e. generation, transmission and distribution. Deputy Speaker Sir, he does not know about transmission. I can tell him what is trannmission. The electricity is supplied to all the areas of the State i.e. streets, Mohalla or any particular area. It does not mean that if the electricity is not supplied in a particular Gali or street then the distribution is not proper.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आगे अभिभाषण में यह भी कहा गया है (विघ्न) (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का समय नहीं मिला है। इंट्रप्शन बहुत हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : ठीक है सर। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अभिभाषण में कहा गया है कि विश्व बैंक से 2400 करोड़ रुपये का लोन लिया गया है जिससे बिजली की प्रणाली में सुधार किया जाएगा और सहायता प्रदान करने वाली मुख्य एजेंसियों की मदद से यह परियोजना राशि बढ़कर 8000 करोड़ रुपये के नजदीक पहुंच जाएगी। यह पैसा किस राशि के अन्तर्गत हरियाणा सरकार के पास जमा होगा ? फिर ये उसका उपयोग करेंगे या फिर उसका सामान जैसे एक-एक नट बोल्ट 50 रुपये का और बिजली के ट्रांसफार्मर 1-1 लाख रुपये के होंगे। अगर हिसाब की बात की जाये तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक का सारा पैसा हरियाणा में इस्तेमाल हो रहा है ? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो यह ऐड 7900 करोड़ रुपये है परन्तु इसमें से कैश अकाउंट का जो पैसा हरियाणा सरकार को मिलेगा उसमें से मुश्किल से 1/3 ही मिल पायेगा बाकी सबका सब विदेशी कम्पनियों को माल बेचने की ऐवज में लोन के रूप में एडजस्ट करेंगे तथा इस लोन की राशि को विश्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह बात सही नहीं है तो क्या हरियाणा सरकार को यह मालूम नहीं है कि इस सारी राशि को वापस भी करना पड़ेगा ? उसमें ब्याज की दर क्या होगी, कितनी राशि हर साल हरियाणा सरकार को वापस देनी होगी, क्या यह ठीक नहीं है। इस तरह से अन्धाधुंध तरीके से हरियाणा सरकार ऋण ले रही है चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे बिजली बोर्ड का मामला हो या चाहे कोई दूसरा मामला हो। क्या इससे आगे आने वाली सारी नस्लों पर, हरियाणा के आम आदमी पर ऋण का बोझ नहीं पड़ेगा ? क्या सरकार डैब्ट ट्रैप के अन्दर फंसने नहीं जा रही है ? इस बात की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार को लेनी चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आप सदस्यों को कंट्रोल रखें (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आज आप 8 हजार करोड़ रुपये की राशि की बात सिर्फ बिजली बोर्ड के लिए कर रहे हैं। इससे पहले 800 करोड़ रुपये ऋण के रूप में नहर महकमें के लिए ले चुके हैं। 700-800 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग के लिए है। इस तरह से 10-12 हजार करोड़ रुपये का ऋण हरियाणा की जनता पर चढ़ा रहे हैं। क्या हरियाणा की जनता इस बात के लिए सक्षम है कि वह इस ऋण को उतार पायेगी ? क्या यह सारा पैसा आम आदमी, गरीब आदमी, छोटे किसान, छोटे व्यापारी तथा अन्य लोगों से करों के रूप में वसूल नहीं किया जायेगा? इसलिए ऐसे समय में अन्धाधुंध ऋण लेने से पहले गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। इन्होंने जो बिजली के सुधारीकरण की बात की है तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि बिजली के सुधारीकरण और निजीकरण का काम किस सरकार ने शुरू किया था। सुर्जेवाला जी जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के राज में ही सारा का सारा विदेशी ऋण लिया गया। हमारी कोशिश तो निजी-करण को खत्म करके बिजली के सुधारीकरण की है। (विघ्न) मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश का जो कर्जा है वह सारा का सारा इनकी कांग्रेस की सरकार के राज का लिया हुआ है। हम तो उसको सुधारने में लगे हुए हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की आदत है कि वह कोई भी बात बगैर पता लगाये कह देते हैं। कांग्रेस की सरकार ने प्राईवेट सैक्टर से बिजली उत्पादन के लिए समझौता किया था। उसने कर्ज कभी नहीं लिया। यह रिकार्ड की बात है। बिजली महकमे के अफसरान यहां बैठे हुए हैं वे रिकार्ड निकलवाकर देख लें। अगर कांग्रेस की सरकार ने एक रुपये का भी ऋण लिया हो उसके बाद ये बोलें। (विघ्न) सर, मैं उन्हीं की ही बात कह रहा हूं। मैंने उनकी बात का जवाब तो देना है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है तो जवाब दे देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इन के प्रिय नेता चौधरी भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय इन्होंने कुछ कंपनियों के साथ समझौता किया था। एक ऐसी ही कंपनी आईजनबर्ग के साथ उन्होंने गैर कानूनी तरीके से समझौता किया और हमारी सरकार ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए उस समझौते को रद्द कर दिया क्योंकि वह समझौता गलत किया गया था। वह कंपनी खिलौने बनाने का काम करती थी। (शोर) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी, आप कन्कल्यूड करें।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा सारा समय तो माननीय मंत्री जी ने ही ले लिया है। आपके मुकाबले में उपाध्यक्ष महोदय कुछ ज्यादा दिलदार हैं क्योंकि वे बोलने के लिए समय देते हैं लेकिन जब आप आते हैं तो हमेशा ही यह कहने के लिए आते हैं कि कन्कल्यूड करें। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने का और समय दे दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा को डैट ट्रैप पर ले जाया जा रहा है। जब हम 1000 करोड़ रुपये का ऋण ले रहे हैं तो यह भी विचार करना चाहिए कि इस ऋण को वापिस कैसे करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो थोड़ा-बहुत अपनी आगे व पीछे की हालत को ध्यान में रखता है। लेकिन इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बिजली बोर्ड की प्रणाली को सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपये का ऋण लेने जा रहे हैं। इसी प्रकार से मंडी विभाग के ऋण के बारे में भी पिछले बजट सैशन में चर्चा की गई थी। (विघ्न) शिक्षा विभाग के ऋण के बारे में तो मेरे भाई बताएंगे, जब उनको मौका मिलेगा। क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। (विघ्न) आप तो सर्वव्यापी हैं, आपका क्या मुकाबला ? इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, आप हरियाणा को एक डैट ट्रैप पर धकेलने लग रहे हैं क्योंकि यह पैसा हरियाणा सरकार द्वारा वापिस नहीं किया जा सकेगा इसलिए इसका सीधे तौर पर हरियाणा की जनता पर बोझ पड़ेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रणदीप जी, बिल्लू राम जी आपको कोई नोट दे रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से मुझे इनके साथ बैठने का मौका मिला है और हम ने इन से बहुत कुछ सीखा है।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा नोट कैप्टन अजय सिंह जी का है। मुझे यह नोट ठीक नहीं लगता है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये आपके जिले के रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, इसलिए एक-दूसरे के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री महोदय के अभिभाषण में चर्चा की गई और आप भी जानते हैं कि हम आज इक्कीसवीं सदी के द्वार पर खड़े हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि परियोजना आय-व्यय में हरट्रॉम के लिए सालाना 4.75 करोड़ रुपये रखा गया है जो कि एक मजाक सा प्रतीत होता है। क्या आज की सरकार यह बता पाएगी कि उन्होंने हरियाणा प्रांत में इंटरनैट ई-मेल सीधे देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं ? क्या आपने सभी जिला मुख्यालयों को हरियाणा के सिविल सचिवालय के साथ जोड़ा है ? क्या राज्य सरकार को सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ जोड़ा गया है ताकि प्रशासनिक कार्यवाही अच्छी तरह से हो सके। क्या इस ओर किसी ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है ? (घंटी) क्या मंत्रियों और राजनेताओं ने कभी इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया कि जो नई कैटेगरी इक्कीसवीं सदी में होगी वह कंप्यूटर लीट्रेट की होगी।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम कर्मचारियों के वैल-विशर हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि कम्प्यूटर प्रणाली शुरू की जाए। इनको अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए।

18.00 बजे **श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला :** सांगवान साहब को पता नहीं लेकिन अगर कोई काम ज्यादा तेजी से किया जाए तो उससे कर्मचारियों की छंटनी नहीं बल्कि उनमें निपुणता आती है तथा कम्प्यूटरयुक्त प्रणाली से ज्यादा रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। कई बार अध्यक्ष महोदय, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता है।(शोर)

Mr. Speaker : Mr. Surjewala ji, now your time is over. You please sit down.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : कर्मचारियों की भलाई को लेकर मैं 5 मिनट में कन्कल्यूड कर दूंगा। मुझ से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता श्री धर्मबीर गाबा ने कर्मचारियों के बारे में चर्चा की और भाई नृपेन्द्र सिंह ने भी चर्चा की। क्या मौजूदा सरकार हरियाणा के कर्मचारियों की सबसे ज्यादा भला चाहने वाली है ? कल जो सर्व कर्मचारी महासंघ की यहां मीटिंग हुई उसका परिणाम आपने देख लिया, उस मीटिंग में उन्होंने सभी जिला हैडक्वाटर्ज पर सरकार के खिलाफ ऐजीटेशन करने का फैसला किया है। इससे पता चलता है कि सरकार कर्मचारियों की कितनी भलाई करना चाहती है।

श्री सतपाल सांगवान : माननीय सुर्जेवाला और ओम प्रकाश चौटाला आज एम्पलाईज के जितने हमदर्द हो रहे हैं उसके बारे में पूछो मत। स्पीकर सर, 1986-87 में बंसी लाल ने ही चौथा पे-कमीशन दिया था उसके बाद से आज तक वे उनके वैलविशर रहे हैं। बंसी लाल ने पांचवां पे-कमीशन दिया है। मैंने हर एम्पलाई से बात की है खासकर टीचर से। अगर हिन्दुस्तान में कहीं पर भी हमारे प्रदेश के टीचर्ज के बराबर ग्रेड हो तो मैं चैलेंज करता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat. No more now. Please take your seat, Mr. Surejewala.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि मुझे 5 मिनट का समय दे दिया जाए ताकि मैं अपनी बात कन्कल्यूड कर सकूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज ये अपनी पार्टी और कर्मचारियों के हितैषियों की बात करते हैं। जब पिछले दिनों इनका राज था उस समय कर्मचारियों के साथ इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया। पुलिस ने और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को रेल की पटरियों पर लिटाकर अत्याचार किए। आज ये कर्मचारियों की भलाई की बात करते हैं। इनके राज में कर्मचारियों को जेलों में बंद किया गया था और जेलों में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। चौधरी भजन लाल जी के राज में सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादतियां की गई थीं उस समय उनको पीटा भी गया था हमने किसी कर्मचारी भाई के साथ कोई ज्यादती नहीं की, न किसी कर्मचारी को हमने पुलिस से पिटवाया और न उनको रेलों की पटरियों पर लिटाया।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, ये मंत्री हैं और इनको मंत्री पद की जिम्मेदारी का पता होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी आप कृपया बैठ जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, आपने मुझे अपनी स्पीच कन्कल्यूड करने के लिए दो मिनट का टाईम दिया था लेकिन आपने बीच में ही माननीय मंत्री जी को बोलने के लिए समय दे दिया। आपने मंत्री जी को प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए समय दे दिया। आप मुझे कम से कम दो मिनट का टाईम अपनी स्पीच कन्कल्यूड करने के लिए दे दें।

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रणदीप सिंह जी ने एक बात पूछी थी उसके बार में मैं इनको बताना चाहूंगा कि एच0एस0ई0बी0 परचेज करेगा। स्पैसिफिकेशन भी एच0एस0ई0बी0 की होगी। जो टैंडर होंगे वे भी एच0एस0ई0बी0 डिसाइड करेगा। इन्होंने लोन के रेट ऑफ इंट्रस्ट के बारे में पूछा था उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि 6 हजार करोड़ रुपये का रेट ऑफ इंट्रस्ट साढ़े 13 परसैंट होगा।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने पूरी बात खोल कर सदन के पटल पर रखी है। आप 8 हजार करोड़ रुपये और 6900 करोड़ रुपये की बात करते हैं और ब्याज की दर साढ़े 13 परसैंट की बात करते हैं तो आप उसका सालाना साढ़े 13 परसैंट ब्याज कैलकूलेट करें तो वह एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ब्याज की राशि आप वापिस देंगे। यह तो केवल बिजली बोर्ड का है बाकी दो महकमों का लोन अलग से लिया है। वित्त मंत्री जी हाउस में बैठे हैं वह बताएं कि हरियाणा का टोटल बजट कितना है ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हर माननीय सदस्य को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री अतर सिंह सैनी : मैंने आपको रेट ऑफ इंट्रस्ट बता दिया है आप उसको कैलकूलेट कर लें।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, यह तो हरियाणा की जनता को चुभने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी अब आप बैठ जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर साहब, आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दें ताकि मैं अपनी बात कंकल्यूड कर सकूं। आप मुझे दो मिनट का समय दे दें। डेढ़ मिनट तो मंत्री जी ने मुझे इनट्रप्ट किया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं। अब नफे सिंह राठी बोलेंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended upto 7.00 p.m.?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended utp 7.00 p.m.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री नफे सिंह राठी : (बहादुरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज गवर्नर एड्रेस पर चर्चा हो रही है। बिजली के सुधारीकरण की बात हो रही है अच्छी बात है। बिजली का सुधारीकरण होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड की तरफ से कम्प्यूटराईज जो बिल दिये जा रहे हैं वे अधिकतर गलत होते हैं। जब उनको ठीक करवाने के लिए लोग जाते हैं तो उनको ठीक नहीं किया जाता और जब लोग बिजली के बिल नहीं भरते तो बिजली बोर्ड के लोग कनैक्शन काटने के लिए जाते हैं। लोग विरोध प्रकट करते हैं तो उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज की जाती है। यह जुल्म जो किया जा रहा है इसको रोका जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं। हमारे बहादुरगढ़ में छोटी-छोटी मासूम बच्चियों के कत्ल हो रहे हैं और मेरा हल्का दिल्ली की सीमा से तकरीबन 50 किलो मीटर लम्बे, कच्चे-पक्के रास्ते से जुड़ा हुआ है। वहां से शराब की समगलिंग हो रही है। बहादुरगढ़ का जो सिटी थाना है उनके पास एक जीप है। वह जीप ऐसी है कि यदि उसको 1 किलोमीटर तक धक्का मारेंगे तो तब जाकर वह स्टार्ट होगी अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब वह जीप एक किलोमीटर धक्का लगाने के बाद स्टार्ट होगी तो वहां पर वहां के पुलिस वाले लोगों की क्या हिफाजत कर पायेंगे। मैंने जिकर किया है कि वहां पर 8-8 साल की बच्चियों के कत्ल किए गए और उनके साथ बलात्कार किया गया लेकिन उस असली बेबी किलर को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। जब विरोध स्वरूप लोग रोष प्रकट करते हैं तो पुलिस उन पर गोलियां चलाती है। अब जब पीछे ऐसी घटना हुई तो उसमें दो आदमी मारे गए और 3 घायल हुए। सरकार ने मारे गए लोगों की जांच के लिए तो आयोग बैठा दिया लेकिन बेबी किल्लर को पकड़ने के लिए कोई आयोग नहीं बैठाया। यह बड़े दुख का विषय है कि इस किस्म की हत्यायें कब तक होती रहेंगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह बेबी किलर को तुरंत पकड़े। आज हरियाणा का किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी आन्दोलन करने पर तुला हुआ है और आन्दोलन कर रहा है। सरकार इन आन्दोलनों को जबरदस्ती कुचलने पर उतारू है और आन्दोलनकारियों को सख्ती से दबाया जा रहा है। सतनाली में गोलियां चला कर 12 किसानों को मार दिया गया और उनका नाम फिर यहां पर शोक प्रस्ताव की सूची में भी नहीं आने दिया। सरकार इन मारे गये लोगों के आंसू तक पोंछने की कोशिश नहीं कर रही। ये किस आधार पर कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। बिजली बोर्ड के 17000 कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं और आज 42 दिन उनको आन्दोलन करते हुए हो गये हैं। वे 30 वेज बिल्डिंग के सामने बैठे हुए हैं। सरकार ने उनको सर्विस से निकाल दिया है। इस बारे में मेरी सरकार से मांग है कि उनको दुबारा से नौकरी पर ले लिया जाए। अध्यक्ष महोदय,

[श्री नफे सिंह राठी]

ऐसा ही हाल प्राध्यापकों का है वे लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। स्पीकर सर, कल 20 हज़ार कर्मचारियों ने विधान सभा के सामने चण्डीगढ़ में प्रदर्शन किया। स्पीकर सर, अगर कर्मचारी इस प्रकार से नाराज़ होंगे तो इस प्रदेश का काम कैसे चल पाएगा इसलिए इस सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं या उनकी जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने का काम करें। स्पीकर सर, बहादुरगढ़ में एक आटो मार्कीट का निर्माण होना था और उसके लिए करीब 21 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर की थी लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि नोटिफिकेशन होने के बाद इस जमीन को रिलीज़ कर दिया गया। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्ज़ ने सरकार से मिल कर अनअथोराईज़ड कालोनियां काट दी हैं। इसी प्रकार से इसके सामने ही लगभग 40 एकड़ जगह लेकर और कालोनी काटी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस जमीन में हरिजनों की जमीन भी थी। यह जमीन 4-5 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से खरीदी गई है और दो हज़ार रुपये गज के हिसाब से यह जमीन बेची जा रही है। इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तथा ऑटो मार्किट वालों के साथ भी धोखा हुआ है इसकी छानबीन कराई जाये।

श्री अध्यक्ष : यह जगह कहां पर है ?

श्री नफे सिंह राठी : यह जगह मेनसेड नेशनल हाईवे नं० 10 सैक्टर-6 बहादुरगढ़ (सांखोल) के सामने है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं म्यूनिसिपल कमेटी में कार्यरत कर्मचारियों की बात भी कहना चाहता हूं। 1974 में यहां पर 106 सफाई कर्मचारी थे और यहां की आबादी 20 हज़ार थी। आज वहां पर सफाई कर्मचारी 96 हैं उनमें 10 सफाई कर्मचारी पब्लिक हैल्थ में सीवरेज के लिए दिए हुए हैं। 10 सफाई कर्मचारी आमतौर पर अफसरों की कोठियों पर रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1974 के बाद वहां पर कितनी आबादी बढ़ गई है। आबादी के कारण कितना एरिया और बढ़ गया है लेकिन सफाई कर्मचारियों की संख्या सरकार को लगातार लिखने के बाद भी नहीं बढ़ी है और ज्यादा कर्मचारी रखने की इजाजत नहीं मिली है। सिर्फ बहादुरगढ़ में ही नहीं लगभग हर शहर में यही हाल है कि वहां पर सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है जबकि शहरों की आबादी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो किस प्रकार से सफाई व्यवस्था शहरों में ठीक हो पाएगी। पिछले वर्ष जून में मुख्य मंत्री जी बहादुरगढ़ गये थे और वहां की समस्याओं के बारे में उनके नोटिस में लाया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर कई आश्वासन भी दे कर आए थे। अन्य मन्त्रीगण भी वहां पर कई आश्वासन दे कर आए थे कि यह कर देंगे वह करेंगे। स्पीकर सर, इस सरकार के मंत्रियों ने वर्ष 1997 में लाखों रुपये के काम करवाने के वायदे किए थे, सड़कें बनवा देंगे, यह करवा देंगे लेकिन कहीं पर भी कोई पैसा खर्चा नहीं किया गया है। सारी की सारी अप्रोच रोडज़ टूटी पड़ी हैं, सारे हल्के में सड़कों का बुरा हाल है। इन समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। इन समस्याओं को हल करवाने के लिए वहां के लोगों ने एस०डी०एम० के ऑफिस के सामने तीन महीने तक प्रदर्शन किया और राज्यपाल महोदय तथा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी भेजे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ को झज्जर जिले में शामिल कर दिया गया है जब कि वहां के लोगों की यह मांग है कि इसको रोहतक जिले में रहने दिया जाए। वहां के लोग रोहतक जिले में शामिल होना चाहते हैं लेकिन सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है और इसको रोहतक जिले में शामिल नहीं कर रही है और लोगों की भावानाओं से खिलवाड़ कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए और अगर सरकार चाहे तो वहां पर जनमत करवा के देख ले कि लोग रोहतक जिले में रहना चाहते हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, सत्ता में आने से पहले इस सरकार ने लोगों से अनेकों वायदे किये थे लेकिन

इनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो वायदे लोगों के साथ किए थे उनको पूरा किया जाए। स्पीकर साहब, पिछले साल कमला वर्मा जी यहां पर आई थीं उन्होंने वायदा किया था कि बहादुरगढ़ में म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव 6 महीने में करवा देंगी लेकिन आज एक साल हो गया है वहां पर चुनाव नहीं करवाए जा रहे है। आज वहां पर गड़बड़ें की जा रही हैं अगर ऐसा होता रहेगा तो काम कैसे चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले वायदे किए थे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे । बहादुरगढ़ हल्का दिल्ली के बोर्डर पर है। पिछले साल सुप्रीमकोर्ट ने आर्डर दिए थे, उस आर्डर में दिल्ली से 39 हजार फैक्टरियों को 6 महीनें में बंद करके चले जाने को कहा था। उन फैक्ट्रियों से मैक्सीमम फैक्टरियां बहादुरगढ़, सोनीपत और गुड़गांव में आनी थीं। आप सरकार की नीतियों को देखें जहां पर 185 रुपये गज के हिसाब से रजिस्टरी होनी थी वहां पर इन्होंने अढ़ाई हजार रूपये गज का रेट कर दिया । अगर फैक्टरी वालों को इतने मंहगे रेटों के हिसाब से जमीन खरीद कर रजिस्टरी करवानी पड़ेगी तो वे व्हाईट मनी कहां से दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 185 रुपये की जगह अढ़ाई हजार रुपये गज के रेटों का रूल नहीं बनाया गया होता तो हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा फैक्टरियां आतीं। यह जो रूल है वह गलत है।

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं सीवरेज के बारे में कहना चाहूंगा। तमाम शहरों में सीवरेज का बहुत ही बुरा हाल है। सीवरेज का सारा सिस्टम ब्लॉक पड़ा हुआ है। कहीं पर थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो वह भर जाता है। मैं जगन्नाथ जी से कहना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में डिस्पोज़ल सिस्टम बना दिया जाएगा, का आश्वासन दिया गया था और अब वह नहीं बनाया जा रहा है। वहां पर छः इंच की पाईप लगी हुई है और उस पाईप से पूरे शहर का पानी कैसे जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में कुछ किया जाए। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री राम पाल माजरा (पाई) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सर, मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें जहां इन्होंने इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही तो मैं इस संबंध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिनको पढ़ने से, जिनको बताने से इंसान के रौंगटे खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 12 फरवरी, 1995 में बहादुरगढ़ में नेता जी नगर की पूजा का क्या कसूर था, 11 जुलाई, 1995 में परनाले इलाके की शीतल का क्या कसूर था, 12 सितम्बर, 1995 में नेहरू पार्क की करूणा का क्या कसूर था, 14 अक्तूबर, 1995 में शंकर गार्डन की जानी का क्या कसूर था, 4 जनवरी 1996 में अग्रवाल कालोनी की पिंकी का क्या कसूर था, 9 जनवरी 1996 को माडल टाउन की स्वाति और 12 जनवरी 1996 को नेता जी नगर की सलमा का क्या कसूर था, 12 मार्च 1997 को अग्रवाल कालोनी की शक्ति का क्या कसूर था ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन माजरा साहब, यह सरकार तो जून 1996 में आयी है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं 1996-97 की घटनाएं बता रहा हूं। आपकी सरकार बनने के बाद 21 जून 1997 को अशोक विहार की गूंज तथा बहादुरगढ़ की कोमल इनका क्या कसूर था। अध्यक्ष महोदय, वह कली खिल भी न पायी थी कि इनके राज में वह खिलने से पहले ही मुरझा गयी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अंदर इन छोटी-छोटी बच्चियों के अपहरण की कहानी यहीं बंद नहीं हुई। चीका शहर की दो लड़कियों का अपहरण हुआ और उनके बाप ने डी०सी० के एवं एस०पी० के आफिस के चक्कर काटे तथा चक्कर काटने पर भी जब उसे कुछ फायदा नहीं हुआ तो अंत में वह पागल

[श्री रामपाल माजरा]

हो गया। अध्यक्ष महोदय, वह अपनी बेटियों की भीख इस जमाने से और इस सरकार से मांगता रहा लेकिन वे आज तक भी नहीं मिलीं। इसी तरह से पलविन्द्र कौर जो कि आर्य गर्ल्ज कालेज, अम्बाला की लड़की थी, का अपहरण हुआ और आज तक वह नहीं मिली। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार का यह क्रम इस सरकार में भी जारी रहा और ये ला एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए जबकि ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था कि स्थिति बहुत अच्छी तरह की है। अध्यक्ष महोदय, डॉ० रमन भंडारी का दादरी में कत्ल कर दिया गया, दादरी के पास ही इसांवड़ गांव के दो व्यापारियों का अपहरण हुआ और उनका कत्ल हुआ। इसी तरह से उचाना के पास पालवा गांव में नंदकिशोर नाम के व्यापारी की पत्नी कमलेश का कत्ल हुआ और उसका पुलिस ने चालान तक भी पुटअप नहीं किया जिसकी वजह से उन लोगों की रिहाई हो गयी, उनकी जमानत हो गयी। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में इन्होंने कहा कि हमने बिजली के क्षेत्र में बहुत कुछ करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता से इन्होंने वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन आज बिजली केवल रात को ही आती है ताकि चोरों को सहुलियत हो सके और चोर सारा सामान बांधकर चले जाएं। बिजली आठ से लेकर दस बजे तक जरूर जाती है ताकि बच्चे पढ़ न सकें और हरियाणा प्रदेश में शराब के तस्कर शराब को ठिकाने लगा सकें। हरियाणा प्रदेश में इनकी बिजली से तो कहीं पंखा नहीं चला लेकिन चिड़िया ने जरूर उसको हिलाकर चला दिया। इसी प्रकार से बल्ब को दिया जलाकर ढूंढना पड़ा कि यह बल्ब जल भी रहा है या नहीं। हरियाणा प्रदेश में बिजली के बिल तो जरूर बढ़े परन्तु बिजली नहीं आयी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में बहुत से किसानों ने बहुत पहले मनी डिपोजिट स्कीम के तहत ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज मांगे थे। उन्होंने इनको लेने के लिए अपने गहने तक बेचकर दस हजार रुपये बिजली बोर्ड के पास जमा करवाये थे। लेकिन पोलिसी चेंज हो जाने की वजह से उनको आज तक भी कनैक्शन नहीं मिले। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ट्रांसफार्मर तो ये दे नहीं सके लेकिन कम से कम जिन किसानों ने अपने गहने बेचकर पैसा बिजली बोर्ड के पास जमा करवाया है उनको अपनी पोलिसी चेंज करके सरकार कनैक्शन देने का काम जरूर करें। अध्यक्ष महोदय, सरकार को 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर भी बदलने चाहिएं। हमारे उन किसान साथियों का क्या कसूर था जो आन्दोलन कर रहे थे। गोपीचंद, काले खां का क्या कसूर था एवं रामफल का क्या कसूर था और क्या कसूर था इगरा के राजकुमार का। वे केवल ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए अपनी मांग कर रहे थे। इसी तरह से धर्मवीर एवं रामहरे जो कि गोपालवास के रहने वाले थे, का क्या कसूर था। वेदप्रकाश जो कि बाढ़ड़ा का रहने वाला था एवं मनीराम जो कि मंडियाबाली का रहने वाला था, का क्या कसूर था ? ये भी केवल इसी वजह से शहीद हो गये कि वे ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की इस सरकार ने इस प्रकार से उन पर गोलियां दागी कि वे शहीद हो गये।

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ी, पैट्रोल पम्प जलाए, स्टेशन फूंके और ला एण्ड आर्डर मेन्टेन नहीं किया। वे शहीद नहीं हुए हैं, लूटपाट कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करूंगा कि हरियाणा प्रदेश में जो किसान जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये छोटी-छोटी बातें हैं। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि 8 लाख रुपये के बदले में जो ट्रांसफार्मर सड़े पड़े हैं उन ट्रांसफार्मरों को बदलने का काम करें।

श्री अतर सिंह सैनी : आप उन किसानों को कहें कि वे बिजली के बिल भरें।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अभी कृषि मंत्री महोदय, कह रहे थे कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमने कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव कराया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की माली हालत जितनी इस राज में खराब हुई है उससे पहले कभी इतनी खराब नहीं हुई। किसान की सावनी की फसल तबाह हो गई। रबी की फसल की बिजाई नहीं हो सकी और सूरजमुखी की बिजाई होगी नहीं क्योंकि आपके पास बीज नहीं है और यदि बीज है भी तो डुप्लीकेट है।

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल कमियां गिना रहे हैं माईनरों और नहरों की सफाई से किसानों को 315 करोड़ रुपये की ज्यादा आमदनी हुई है उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई है उन किसानों को मुआवजा देने का काम करें। आज किसान की 3-3 फसलें खराब हो गई हैं किसान बर्बाद हो रहे हैं और मंत्री जी एयर कंडीशंड बंगलों में बैठे हैं। आदरणीय सहकारिता मंत्री जी अभी हाउस में बैठे नहीं हैं उन्हें कृषि मंत्री जी बता देंगे। आज सहकारिता विभाग कोपरेशन नहीं बल्कि करप्शन का अड्डा बन गया है, करप्शन डिपार्टमेंट बनकर रह गया है। वर्षों बाद आज भी ट्रैक्टर लोन पर लेने के लिए किसान को अपनी 8 किल्ले जमीन सरकार के पास गिरवी रखनी पड़ती है 8 किल्ले जमीन की कीमत कम से कम 8 लाख रुपये है और हमारे कुरुक्षेत्र जिले में 8 किले जमीन की कीमत 16 या 20 लाख रुपये के करीब बैठती है। दो लाख रुपये का ट्रैक्टर लेने के लिए 8 या 16 लाख रुपये की जमीन किसान को गिरवी रखनी पड़े तो इसमें किसानों का क्या भला होगा। दो लाख रुपये के बदले में किसान की 8 किल्ले जमीन बांधकर रखना किसान के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री जी 2 या 3 एकड़ जमीन के बदले किसानों को ट्रैक्टर दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : यह 8 एकड़ का प्रोविजन कब से शुरू हुआ है और कीमत कब से बढ़ गई है यह भी बता दें ताकि उसका जवाब भी सहकारिता मंत्री जी साथ ही दे दें।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, पहले 20 एकड़ होती थी बाद में घटाकर 8 एकड़ की थी।

श्री नरबीर सिंह : यह जो 8 एकड़ की बात कह रहे हैं यह घटाकर 6 एकड़ कर दिया है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको यह भी नहीं पता कि 8 एकड़ की आजकल कीमत क्या है। ये कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में 20 लाख रुपये कीमत है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, राम पाल माजरा जी जो जी में आ रहा है कहते जा रहे हैं। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड मंगवाया जाए। मेरे माननीय साथी ने कहा है कि एक एकड़ की कीमत कहीं-कहीं एक लाख रुपये है व कुछ अच्छे इलाके जैसे कुरुक्षेत्र जिले में दो या अढ़ाई लाख रुपये प्रति एकड़ है इस हिसाब से 8 एकड़ जमीन की कीमत कहीं 8 लाख रुपये व कहीं 16 या 20 लाख रुपये है क्योंकि कई जगह दो लाख रुपये कीमत है तो 16 लाख हो गई और कई जगह अढ़ाई लाख कीमत है तो इस प्रकार 20 लाख हो गई।

श्री कर्ण सिंह दलाल : माजरा साहब, आप खेतीबाड़ी की बात करते, दवाईयों की बात करते तो वह बात आपके मुंह से अच्छी लगती, परन्तु यह बात अच्छी नहीं लगती। आपके राज में जमीनों पर आपकी ग्रीन बिग्रेड द्वारा नाजायज कब्जे किये जाते थे। दवाईयों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती थी। आपके राज में तो जो खाली जमीन, खेत नजर आते थे या खाली प्लाट नजर आते थे उन पर कब्जा किया जाता था। इन बातों पर कहते आप अच्छे नहीं लगते। आपका कोई सुझाव है तो आप दीजिए हम उन पर विचार करेंगे।

श्री रामपाल माजरा : आप उन लोगों की स्टेज पर प्रशंसा कर चुके हैं। आपको सुझाव भी दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छोटे छोटे किसान जिनके पास एक-एक और दो-दो एकड़ जमीन है उनको ऋण देने की लिमिट होगी। अगर उनको ऋण देने का प्रावधान गांव में जो मिनी बैंक होते हैं उनके माध्यम से कर दिया जाये तो अच्छा होगा। उनका जो ऋण बनता है उसका चैक काट कर मिनी बैंक में दे दिया जाये और उन किसानों को वहां पर पैसा दे दिया जाये और पटवारी के रिकार्ड में पर्चा दर्ज किया जाये। गन्ने के बारे में हमारे साथी कहते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हमने दिया है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 50 प्रतिशत का जो शूगर मिल देती थी वह खर्चा भी इस सरकार ने किसानों पर लाद दिया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। अपनी बात तो ये कह चुके हैं। जहां तक गन्ने के भाव की बात है आज चौधरी बंसी लाल के नेतृत्व की हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को जो गन्ने का भाव दिये हैं उतने भाव आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिये। इनके नेता तो कुछ और कह रहे थे। चौधरी देवी लाल जी के राज में तो किसानों को गन्ना अपने खेतों में जलाना पड़ा था। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मेरी आपसे सबमीशन है कि कोई भी सदस्य जब बोलता है तो किसी को बीच में दखल नहीं देना चाहिए। अब तक कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे तो किसी भी सदस्य ने बीच में नहीं टोका। जब हमारी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं तो ये बीच में दखल दे रहे हैं। यह सरकार बनने के बाद गन्ने की लोडिंग और अन-लोडिंग का ट्रांसपोर्ट चार्जिज का भार किसानों पर डाला गया है चाहे वह 50 प्रतिशत ही क्यों न डाला गया है। हमारे साथी उसी बारे में जिक्र कर रहे हैं तो इसमें इनको परेशानी क्यों हो रही है।

श्री बंसी लाल : स्पीकर सर, मैं एक बात बता दूं कि जब इनकी सरकार थी, उस समय जो भी शूगर मिल लगी थी उसमें घटिया सब स्टैंडर्ड का माल लगाया गया था। कैथल की मिल लगी तो उसमें कितना सब स्टैंडर्ड और कितनी घटिया मशीनरी लगाई गयी थी। भूना की मिल में साढे सात प्रतिशत की रिकवरी हो रही है। कैथल में भी रिकवरी कम आ रही है। महम में भी इन्होंने शूगर मिल लगवाई थी उसमें भी घपला ही घपला है। ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी करवाओ। इंकवायरी भी करवा देंगे।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भी हिन्दुस्तान में या प्रदेश में जांच की अच्छी एजैंसी है उससे जांच करायें और उसके लिए जो दोषी होगा आपके सामने आ जायेगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जांच भी करवा देंगे।

श्री रामपाल माजरा : पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह बात कही थी कि पेमेंट डिले होती है तो उसमें ब्याज देने का प्रावधान है इसका फैसला माननीय हाईकोर्ट ने भी कर दिया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर गन्ने की पेमेंट में डिले होती है तो हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए किसानों

को ब्याज भी दिया जाये। हरियाणा प्रदेश के किसान अगर गन्ने का बीज पूरा नहीं कर सकते हैं तो उन पर पैनल्टी डाल दी जाती है और यह पैनल्टी की राशि उनके टोटल अमाउंट से काट ली जाती है। यह भी प्रोविजन है कि जिन किसानों ने पिछले 30 दिन में गन्ना सप्लाई किया है, यह पैनल्टी की राशि उनमें बांट दी जानी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मेरी सहकारिता मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि यह पैनल्टी की राशि को किसानों को देने का काम भी किया जाए। इसके साथ-साथ मैं विकास मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि किसी गांव की एक गली पक्की हो जाती है तो दूसरी गली कच्ची रह जाती है और गांव का सारा पानी वहां पर खड़ा हो जाता है। अगर गांव की सारी गलियां पक्की हो जाती हैं तो गांव के बाहर गोहर कच्चे रह जाते हैं, वहां पर पानी खड़ा हो जाता है और कीचड़ बन जाता है। इससे कहीं पर आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। इसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था बनाई जाए ताकि गांवों के लोगों को सुविधा हो सके। अध्यक्ष महोदय, जब गांव में कोई मंत्री जाता है तो वहां की पंचायत अपनी मन-मर्जी से ही हजारों रुपये इस खाते में डाल देते हैं। जैसे कि टैंट का ही 10 हजार रुपये लिख देते हैं। इसके लिए मेंडेटरी खर्च 300 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि पंचायत के ऊपर इस नाजायज खर्चे का बोझ न पड़े। उसके अतिरिक्त, जहां-जहां हरिजन चौपालें अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा किया जाए। स्कूलों के कमरे जहां कहीं भी जो अधूरे पड़े हैं, उनको प्रायरिटी पर बनाया जाए। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि हम ने बहुत सारे स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है। इनकी बात ठीक है कि दर्जा बढ़ाया है, लेकिन ऐसा करते समय बैलेंस नहीं रखा गया है। विपक्ष के साथियों के हल्कों में तो केवल एक या दो स्कूलों का ही दर्जा बढ़ाया गया है जबकि दूसरी ओर शिक्षा मंत्री महोदय के हल्के में 15 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अध्यापकों और लैक्चरर्ज की नियुक्तियां भी ठेके पर की गई और ठेकेदारी प्रथा लागू की गई। अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षाविद् रहे हैं। आप तो शिक्षा के बारे में भलीभांति जानते हैं कि वह अध्यापक तनावपूर्ण स्थिति में कैसे सही ढंग से पढ़ा सकेगा जिसका कि ठेका एक निश्चित दिन खत्म होने वाला है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आघात है। मेरी यह मांग है कि या तो इस ठेकेदारी प्रथा को ही खत्म किया जाए या इस को एडहॉक में बदला जाए। हमारे एक दो साथियों ने हमें कहा कि उन्हें भिवानी का स्टेशन दे दिया गया है तो पता करने पर मालूम हुआ कि ऐसे आदेश दिए गये थे कि सर्वप्रथम भिवानी के रिक्त पदों को ही भरा जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाएंट ऑफ आर्डर । माजरा साहब को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। वे सदन में बोल रहे हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी से ही बोलना चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि अध्यापकों की नियुक्ति बिल्कुल मैरिट के आधार पर की गई है तथा किसी भी जिले में चाहे वह फरीदाबाद हो, भिवानी हो या कुरुक्षेत्र हो, के साथ भेदभाव नहीं किया गया तथा न ही किसी जिले को प्राथमिकता ही दी गई। अगर इस प्रकार का कोई कार्य हुआ है तो इनकी सरकार के समय में ही हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप खुद भिवानी में रहते हैं। अगर आपने कोई ऐसी बात देखी हो तो आप कृपया इनको बताएं। लेकिन इनको सच्चाई ही बोलनी चाहिए।

श्री सत नारायण लांठर : अध्यक्ष महोदय, कल का अखबार आपने शायद पढ़ा होगा जिसमें श्री अजय चौटाला का ब्यान है कि भिवानी हल्के में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है और भिवानी हल्के में कुछ नहीं किया गया है। जबकि ये लोग बाहर जाकर के कहते हैं कि सिर्फ भिवानी हल्के में विकास कार्य किए गए हैं। (शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, भाई लाठर ठीक कह रहे हैं कि कल के अखबार में श्री अजय चौटाला का ब्यान है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि भिवानी एक छोटा सा टाउन है जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। (विघ्न) इनको शर्म आनी चाहिए, ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष स्वाभाविक था। कर्मचारी और अधिकारी ही प्रदेश की एक किस्म से आंखें होते हैं। इन अधिकारियों को भी हैड ऑफ दि डिपार्टमैंट द्वारा 6 महीने में 5-5 बार बदल दिया जाता है कर्मचारियों को खासकर अपने चहेतों को नोट लिखकर उनके मुताबिक ही लगाया जाता है। यहां एक डी०एल०आर० की तरफ से कानूनगो की लिस्ट आई थी उसमें लिस्ट आउट होने के बाद किसी के आगे नाट ट्रबी-ट्रांसफर्ड और किसी के आगे आऊट आफ डिस्ट्रिक्ट और किसी के आगे मेवात में बदल दिया जाए, लिखा था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, यह मामला प्रशासनिक है। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी ठीक काम नहीं करता तो उसको जिले से बाहर भी भेजा जा सकता है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : हम यदि कहें तो ठीक लगता है परन्तु ये लोग मैरिट की बात करते हैं जो खुद हमारे पास आते हैं कभी किसी को सस्पैंड करवाने के लिए, किसी को री-इनस्टेट करवाने के लिए और किसी की तबदीली करवाने के लिए। लेकिन आपको सदन में कोई गल्त बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इन्होंने अपने चहेतों को प्रमोशन देने का भी काम किया। जब तक अनिल अरोड़ा की प्रमोशन नहीं हो गई, 9 एक्सीयनज को एस०ई० बनाने का काम किया गया और अनिल अरोड़ा का नाम 10 वें नम्बर पर था उसकी प्रमोशन होने के बाद प्रमोशन का काम बन्द कर दिया गया।

श्री अतर सिंह सैनी : आपके राज में जितने भी लगाए गए थे सारे के सारे उल्टे पड़ गए। जितने भी लगाए गए वे सारे कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कोई हाई कोर्ट द्वारा निकाल दिए गए जबकि हमारी सरकार में सारे मैरिट पर ही लगाए गए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय इनके राज में ट्रैक्टरों के ड्राईवरों को बस के ड्राईवरों के स्थान पर लगाया गया जिसके कारण 8-10 एक्सीडैंड रोजाना हुआ करते थे।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी की बात मैं कहना चाहूंगा। इस शराब बंदी की नीति की विफलता की जिम्मेदारी भाजपा की है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के पड़ौसी सूबा दिल्ली, राजस्थान और यू०पी० में इनका राज है और उन्होंने ठेके हरियाणा की सीमा के पास लाने का काम किया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : माजरा जी, अगर बी०जे०पी० के लोग इतने बुरे हैं तो अपने नेता जी से पूछो कि वह क्यों रोज इनके पैरों को हाथ लगाते रहते हैं।

श्री बंसी लाल : कर्ण सिंह दलाल जी ठीक कह रहे हैं उनका बड़ा नेता लाठ और चौटाला बी०जे०पी० के डिस्ट्रिक्ट लैवल के एक-एक आदमी के पास जाकर पैर पकड़ते रहते हैं। जिस दिन से हमारा बी०जे०पी० के साथ नैगोशिएशन हुआ है उस दिन से मैंने बी०जे०पी० के किसी भी आदमी को

फोन नहीं किया है। मेरी तो क्रैडीबिलिटी थी लेकिन इनकी तो धेले की भी क्रैडीबिलिटी नहीं है। इसलिए माजरा जी कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इनकी क्रैडीबिलिटी के बारे में सारा हरियाणा जानता है। एस०वाई०एल० हरियाणा के किसानों की लाईफ लाईन है। उसको बनाने के लिए 21 महीनों से कोई कोशिश नहीं की गई।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी से पूछना चाहूंगा कि 1977 में जब देवी लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केन्द्र में मोरार जी देसाई की सरकार थी और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे तब एस०वाई०एल० की क्या प्रोग्रेस थी बल्कि चौधरी बंसी लाल जी ने एस०वाई०एल० कैनाल खुदवानी शुरू की थी वह इन्होंने बन्द कर दी थी। अध्यक्ष महोदय, 1987 में इनका राज आया था और पंजाब में इनका गवर्नर लगाया हुआ था, केन्द्र में इनकी सरकार थी। उस वक्त एस०वाई०एल० कैनाल का मुद्दा कहां था।

श्री राम पाल माजरा : चौधरी बंसी लाल जी ने इसी सदन के अन्दर 13 जुलाई 1992 को एक स्पीच दी थी मैं उसको पूरी पढ़ कर तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा मैं उसकी पिछली दो लाइनें पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा था कि एस०वाई०एल० कैनाल की लाइनिंग का 91 प्रतिशत और अर्थ वर्क का 92 प्रतिशत काम चौधरी देवी लाल जी ने करवाया था। यह उस समय की चौधरी बंसी लाल जी की स्पीच का एक अंश है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट व्हीकल्ज का बहुत बुरा हाल है। जबसे आर०टी०ओज० की पावर्ज एस०डी०एम० के पास आई हैं तब से प्राइवेट व्हीकल्ज का बुरा हाल हो गया है। जीप, मैटाडोर, थ्री व्हीलर और विक्की तक के चालान हो जाते हैं। विक्की जो 1500 रुपये में आती है उसका चालान दो हजार रुपये तक हो जाता है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के किसान इस सरकार से बहुत दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं। पत्रकारों पर झूठे मुकदमें बनाए जाते हैं। चौधरी देवी लाल जी कहा करते थे कि बूढ़े लोगो आप डरो मत मैं आपकी पैंशन कर दूंगा, तो चौधरी बंसी लाल जी कहा करते थे कि बूढ़ों की पैंशन हो ही नहीं सकती। अब हम यह भी कहते हैं कि किसानों और मजदूरी करने वालों को हम बिजली मुफ्त देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि चौधरी बंसी लाल ने कहा था कि ओल्ड ऐज पैंशन हो ही नहीं सकती जबकि सच्चाई यह है कि ओल्ड ऐज पैंशन चौधरी बंसी लाल जी ने ही शुरू की थी।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, 1969 में यह पैंशन मैंने ही शुरू की थी उस समय ये राजनीति में पैदा भी नहीं हुए थे।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, मैं और माजरा साहब विधान सभा की एक कमेटी में इकट्ठे थे तो मुझे थे उस कमेटी का काम नहीं करने दिया करते थे ये कहते रहते थे कि आप लोग आने वाले डेढ़ साल के अन्दर किसानों को पूरी बिजली दे देंगे तो हमारे पास एजीटेशन करवाने के लिए कुछ नहीं रहेगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, यह इनकी सैल्फ मेड बात है। ये बात बनाने में माहिर हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, मैं और माजरा दोनों एस्टिमेटस कमेटी में इकट्ठे थे तो ये हर मीटिंग में कहते थे कि आप डेढ़ साल के बाद किसानों को पूरी बिजली दे देंगे तो हमारे पास एजीटेशन करवाने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा।

Mr. Speaker : The House is adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

*18.53 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday the 21st January, 1998)

30002—H.V.S.—H.G.P. Chd.